खण्ड-239, अंक-5
गुरूवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(21 फरवरी, 1963 ई0)

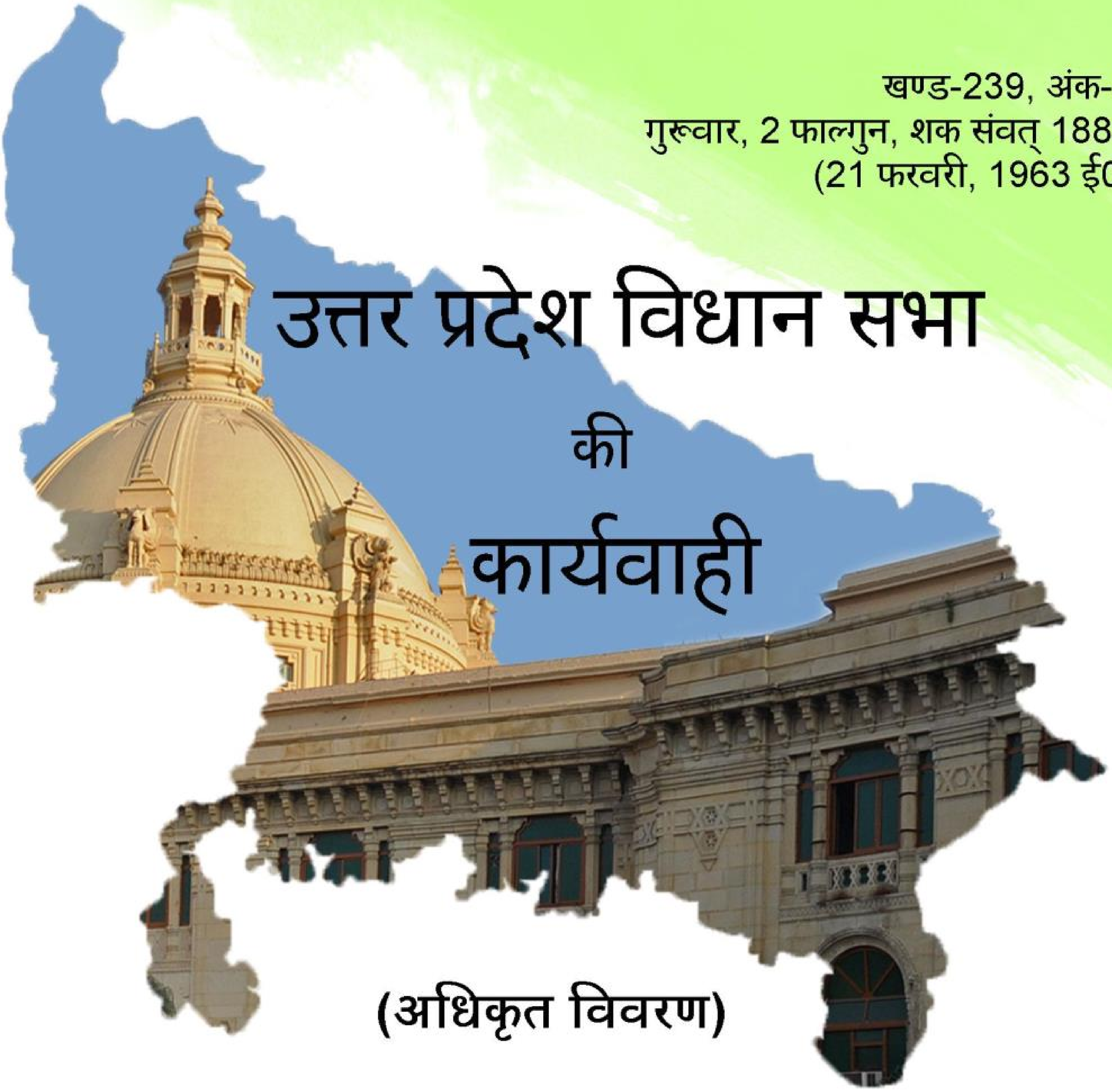

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०३–३०७
२४ मई, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १२ के उत्तर का शोधन ..	३०७–३०९
प्रश्नोत्तर	३०९–३३०
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ की प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति	३३०
अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों की नामावली में संयुक्त समाजवादी दल के कम सदस्य रखने पर आपत्ति	३३०–३३१
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	३३१
श्री चन्द्रशेखर की बलरामपुर अस्पताल में चिकित्सा के संबंध में जानकारी ..	३३१–३३२
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३३२–३३४
१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	३३५–३७९
नत्थियां	३८०–३८७

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्र सनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह श्री,
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविंदसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती,
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पाती राम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बना सीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बल रीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू लाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्द्र, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह,श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव,' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

बृहस्पतिवार, २१ फरवरी, १९६३

२४ मई, १९६२ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १२ के उत्तर का शोधन

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कुंवर श्रीपालसिंह के २४ मई, १९६२ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १२ का शोधित उत्तर पढ़ता हूं, मूल प्रश्न था कि--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ११ मई, १९६२ को बाजपुर, जिला नैनीताल स्थित चीनी मिल में मिल मालिकों तथा श्रमिकों में संघर्ष हुआ? यदि हां, तो कारण क्या था तथा हताहतों की संख्या क्या है?

इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया था:--

मिल मालिकों तथा श्रमिकों में कोई संघर्ष नहीं हुआ। गन्ना उत्पादकों तथा शुगर फैक्टरी बाजपुर के मजदूरों में हल्का दंगा हुआ जिसके फलस्वरूप ९ व्यक्तियों को हल्की चोटें आईं। गन्ना तोलने की मशीन में कुछ अकस्मात खराबी आ गई थी जिससे कि बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण के समय उत्पादकों द्वारा उससे गन्ना की तौल कम होती पाई गई। इसके फलस्वरूप यह घटना घटित हो गई।

किन्तु इसका संशोधित उत्तर इस प्रकार है—

मिल मालिकों तथा श्रमिकों में कोई संघर्ष नहीं हुआ। गन्ना उत्पादकों तथा

[श्री नवलकिशोर]

शुगर फैक्टरी, बाजपुर के मजदूरों में हल्का दंगा हुआ जिसके फलस्वरूप १२ व्यक्तियों को चोटें आयीं। सिर्फ एक व्यक्ति को एक गंभीर चोट के अलावा सभी अन्य व्यक्तियों को हल्की चोटें आईं। दंगे का कारण गन्ना ढोने वाले मजदूरों (Cane carrier Labourers) तथा गाड़ीवानों (Cartmen) के बीच हुआ एक झगड़ा था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी बतायेंगे पहला उत्तर तथा दूसरा उत्तर भेजने वाला कौन अधिकारी था जिसकी वजह से सरकार को पहली दफा गलत उत्तर देना पड़ा ?

श्री नवलकिशोर—

प्रश्न का उत्तर शुरू में भी और अब भी जिलाधीश से आया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि मंत्री लोग यहां कुछ कह जाते हैं और २, ४ दिन बाद या महीने भर बाद फिर कहते हैं सही जबाब यह है। तो यह एक परिपाटी जो पड़ रही है बड़ी गलत है। मैं नहीं जानता या तो मंत्रीगण पूरी तरह से तैयार हो कर नहीं आते या जो वहां से जवाब आया उसको आंख बन्द कर पढ़ दिया। इस परिपाटी को रोकथाम हो, नहीं तो रोज संशोधन होता रहेगा, और आपने देखा कि अपर हाउस में गृह मंत्री जी ने कुछ कहा और चेयरमैन ने कितनी डांट लगायी। आप इस ओर ध्यान दें और इसकी व्यवस्था करें ताकि ऐसा आगे न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आप मंत्री जी को जरा डांट लगाइये।

श्री नवलकिशोर—

आपकी आज्ञा से एक बात कह दूं कि यह परिपाटी का सवाल नहीं है और जहां तक डांटने की बात है अपर हाउस में तो चेयरमैन ने डांटा तो मान्यवर, यहां तो माननीय दुबे जी और काशीनाथ जी ही काफी हैं। इसके बारे में जिलाधिकारियों को इस बात के लिये कह दिया गया है कि वह आइन्दा से प्रश्नों के मामले में ज्यादा जागरूक हों।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उन पर सख्ती होनी चाहिये, कहने से काम नहीं चलेगा तथा मंत्री जी फाइल देख कर और तैयार होकर आया करें।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक हो सके सरकार को चाहिये कि सख्ती के साथ उन लोगों को आगाह कर दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मंत्री जी बतायेंगे गाड़ीवानों में और मजदूरों में पहले से क्या झगड़ा था ?

श्री नवलकिशोर—

एक साहब की गाड़ी तुल गई थी तो वह केन कैरियर के ऊपर उसको खाली कराने के वास्ते गये। कुछ बैलेंस गाड़ी का बिगड़ गया इस पर जो गाड़ीवान था उसमें और मेट में झगड़ा हुआ और यही बात बढ़ गई।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अधिकारियों ने जो पहले उत्तर दिया वह जानबूझ कर घटना को छिपाने के लिये ऐसा किया और मंत्री जी को सदन में गलत सूचना देने के लिये बाध्य किया, तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर—

इसमें छिपाने की कोई बात नहीं थी। जैसे ही सूचना हमको मिली हमने सदन को बता दिया और खेद प्रकट कर दिया, उनको तम्बीह कर दी। संशोधित उत्तर पढ़ दिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी बतायेंगे जो १२ व्यक्तियों को चोटें आयीं हैं यह दोनों तरफ के लोगों को आयी हैं या एक तरफ के लोगों को।

श्री नवलकिशोर—

दोनों तरफ के लोगों को ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे इस किस्म की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री नवलकिशोर—

इस तरह की घटनायें आम तौर से नहीं होतीं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी को सूचना है कि जिनको गाड़ीवान कहा जाता है वे गाड़ी वाले नहीं हैं बल्कि मिल मालिकों के हायर्ड गुंडे हैं ?

श्री नवलकिशोर—

इसकी सूचना माननीय मित्र को हो तो हो। मुझे नहीं है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री ऊदल—

[५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बुन्देलखंड के समाचार पत्रों को लोक सेवा आयोग के विज्ञापन न मिलना

*२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को रिक्त स्थान संबंधी सूचनाएं बुन्देलखन्ड क्षेत्र के किन-किन समाचार पत्रों में पढ़े-लिखे नवयुवकों के लाभ के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ? यदि नहीं किये जाते, तो क्यों ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

आयोग की रिक्त स्थान संबंधी सूचनाएं बुन्देलखन्ड क्षेत्र के किसी समाचार-पत्र में नहीं प्रकाशित की जाती हैं। प्रत्येक स्थानीय तथा क्षेत्रीय पत्रों में आयोग के विज्ञापन छपने असंभव हैं क्योंकि ऐसा करने में बहुत अधिक व्यय होगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मंत्री जी बुन्देलखण्ड की जनता की सुविधा के लिये वहां के पुराने अखबार 'जागरण' में इस तरह के समाचार देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जैसा मैंने बताया स्थानिक पत्रों का सवाल नहीं है । कमीशन ने कुछ पत्र नियुक्त कर दिये हैं और कुछ कैटेगरीज हैं कि किस किस्म का विज्ञापन दें । क्योंकि अगर यह चीज मान ली जाय कि प्रान्त के हर हिस्से में हो तो बहुत खर्चा हो जाता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मंत्री जी बतायेंगे वह कौन-कौन पत्र हैं जिनमें कमीशन ने विज्ञापन देना आवश्यक समझा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास लम्बी लिस्ट है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें या कहें तो पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बता दीजिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पहली लिस्ट में पायनियर, नार्दर्न इंडिया पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स, लीडर और नेशनल हैराल्ड हैं जिनमें आयोग के विज्ञापन छपते हैं ।

दूसरी लिस्ट में ऐसे पत्रों के नाम हैं जिनमें गजटेड और नान-गजटेड दोनों पोस्ट्स हैं सबार्डिनेट-भारत, नवजीवन, स्वतंत्र भारत, आज, हिन्दुस्तान और कौमी आवाज ।

तीसरी लिस्ट है जो सबार्डिनेट नान गजटेड के लिये है--प्रयाग पत्रिका, विश्वमित्र, प्रताप, जागरण और वीर भारत ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, ऐसा होता है कि नियुक्तियों के बारे में जब ठीक से ऐडवर्टीजमेन्ट नहीं हो पाता तो बहुत से खण्डों में लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस ओर कोई विचार करेंगे कि जो स्थानीय पत्र हैं, जिनका सरकुलेशन ज्यादा है उनको भी एडवर्टीजमेन्ट देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं बता दूं कि ऐसा है नहीं । इसके अलावा वह गजट में भी जाता है और यह भी प्रयत्न किया जाता है कि लोकल दफ्तरों के मातहत भी उनका ऐडवर्टीजमेन्ट होता है और इन्फार्मेशन सेंटर्स और दूसरी जगह भी भेजा जाता है ।

झांसी जिले में धैरा रेलवे स्टेशन से अमरीक राय का अपहरण

*३--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १ दिसम्बर, १९६२ से २० दिसम्बर, १९६२ के बीच धैरा रेलवे स्टेशन, जिला झांसी से एक पंजाबी ठेकेदार का डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया ? यदि हां, तो अपहरण किये जाने का क्या कारण है और ठेकेदार की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये और क्या अपहरण करने वाले डाकू पकड़े जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर--

जी हां । यह सत्य है कि डकैत शंकरसिंह के गिरोह ने दिनांक १८-१२-६२ को धैरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से ठेकेदार श्री अमरीक राय का अपहरण किया । सम्भवतः रुपया वसूल करने के कारण ठेकेदार का अपहरण किया गया था । उक्त ठेकेदार वापस आ गये हैं और उनकी रक्षा के लिये संबंधित थानाध्यक्ष को विशेषरूप से हिदायत दे दी गई है । उपरोक्त गिरोह की खोज समस्त सम्भव स्थानों तथा जंगलों में की गई किन्तु अभी तक गिरोह पकड़ा नहीं जा सका ।

*४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० से दिसम्बर, सन् १९६२ के बीच कितने लोगों का अपहरण झांसी जिले में डाकुओं द्वारा किया गया तथा कितने डाकू अपहरण के सम्बन्ध में पकड़े गये ?

श्री नवलकिशोर—

सन् १९६० से दिसम्बर, १९६२ के बीच झांसी जिले में उक्त ठेकेदार के अपहरण के अतिरिक्त १४ अन्य व्यक्तियों का विभिन्न डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया। अपहरणों के संबंध में कुल १३ डाकुओं को गिरफ्तार किया गया, और १० डकैत पुलिस से मुठभेड़ में मारे गये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह भी है कि उपरोक्त ठेकेदार को करीब ४ बजे दिन में धैरा स्टेशन से डाकू लोग उठा ले गये और करीब ३ हजार रुपया लेने के बाद स्टेशन से ४ मील के फासले पर दिन में ही छोड़ गये और पुलिस यह सब देखती रही ?

श्री नवलकिशोर—

जिन साहब का अपहरण हुआ उनका तो कहना यह है कि पुलिस की आहट पा कर डकैत भाग गये मगर झांसी में अफवाह यह है कि उनको ५ हजार रुपया देना पड़ा।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन ठेकेदार के अलावा भी पिछले दो महीने में करीब ४–५ आदमियों को डाकू और उठा ले गये, और उनसे लम्बी रकमें मांगी जा रही हैं, जिसकी वजह से जंगल क्षेत्र में कोई ठेकेदार जाता नहीं है और वहां काफी अशान्ति है ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने प्रश्न ४ के उत्तर में स्वयं कहा है कि इनके अलावा १४ आदमियों का अपहरण किया गया, १३ डकैत पकड़े गये और १० एनकाउन्टर में मारे गये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, उत्तर में यह लिखा है कि उन ठेकेदार की सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया। मेरी अर्ज यह है कि जब ठेकेदार स्वयं डाकुओं के चंगुल से छूट कर घर आ गये हैं तो उनकी सुरक्षा का कौन-सा प्रबन्ध किया गया और जो आज भी ४–५ आदमी डाकुओं के कब्जे में हैं उनकी सुरक्षा के लिये क्या इन्तजाम किया गया है ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य प्रश्न को पढ़ें तो दिसम्बर, १९६२ तक की सूचना उसमें मांगी गयी है जो मैंने दे दी। उसके बाद जनवरी के महीने में क्या हुआ यह सूचना न तो उन्होंने मांगी थी और न मेरे पास है। जहां तक ठेकेदार की हिफाजत का प्रश्न है, मैंने कहा था कि थाना इन्चार्ज से कह दिया गया है और वे एहतियात बरतेंगे ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं यवस्था चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह था कि अभी ४–५ आदमी और हैं. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, आपकी व्यवस्था का सरकार ने जो जवाब दिया वह हो गया ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, गलत सूचना अगर दी जाय तो आप व्यवस्था देंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या गलत सूचना दी ?

श्री लखपतराम शर्मा—

४–५ आदमियों को अभी थोड़े दिन हुये डाकू पकड़ कर ले गये। आपने कहा कि उसमें अवधि दी थी। मैंने उस अवधि के अलावा प्रश्न किया था।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका कहना था कि आपका ओरिजिनल प्रश्न ठेकेदार की सुरक्षा के बारे में था, इन आदमियों के बारे में नोटिस नहीं है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

बुन्देलखंड डिवीजन में ऐसी घटनायें हुआ करती हैं। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां उत्तराखंड की तरह एक डी० आई० जी० नियुक्त कर के इस प्रश्न को सरल करे?

श्री नवलकिशोर—

इस बीच में कई डाकुओं के गैंग्स को लिक्विडेट भी किया गया है। वहां पी० ए० सी० भी है और थानों में फोर्स भी बढ़ायी गयी है। मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर इन्तजाम बहुत माकूल है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी डिवीजन में डाकुओं के आपरेशन्स बहुत दिनों से चल रहे हैं और पिछले ३-४ महीनों से और भी सक्रिय हो गये हैं और जो सरकार का प्लान था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का ज्वाइंट आपरेशन डाकुओं के खिलाफ चल रहा था, वह अब भी चल रहा है तो सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, झांसी डिवीजन में मध्य प्रदेश का बार्डर होने के कारण यह समस्या रहती है और जैसा कि मैंने अर्ज किया डाकुओं को लिक्विडेट करने में काफी कामयाबी हुई है। देवीसिंह और जरनैलसिंह समाप्त कर दिये गये हैं। जहां तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध है दोनों के कोआर्डीनेशन के साथ काम चल रहा है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, देवीसिंह का नाम मंत्री जी ने लिया, उसको मरवाने में रघुनाथसिंह जी का सहयोग था। उनका एक आदमी और एक कांस्टेबिल मार दिये गये हैं और उनकी जान लेने के लिये भी डाकू उतारू हैं। उनकी जान की रक्षा के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, किसने मरवाया और किसका हाथ है, इतनी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रक्षपाल सिंह—

श्रीमन्, सरकार के पास पत्र हैं कि किस आदमी द्वारा मारा गया। इसका जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि मंत्री जी के पास नोटिस नहीं है तो जवाब कैसे दिया जाय? उनके पास सूचना कैसे आये?

श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, यह बात मालूम हो जाय कि सरकार उनकी रक्षा के लिये आगे सक्रिय रहेगी?

श्री नवलकिशोर—

अगर माननीय सदस्य कोई बात लिखकर देंगे तो विचार किया जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार को जानकारी है कि डाकुओं के जो आपरेशन्स बढ़ रहे हैं उनके पीछे पोलिटिकल पैटरोनेज है और संरक्षण है जिसके कारण सरकारी अधिकारी 'उचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, एक साहब का नाम लेकर प्रश्न किया गया है यदि उससे संबंध है तो मुझे पता नहीं है। सरकार के इल्म में इसके पीछे कोई पोलिटिकल पैटरोनेज नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उन्हीं शब्दों में भीषण बात कर सकता हूं। आपके ही ग्रुप के सज्जन हैं जिनके ऊपर एलीगेशन लगा हुआ है, आप उत्तर दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

आप गलत कहते हैं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग डाकुओं द्वारा अपहरित किये गये और छूट आये हैं, उनके द्वारा डाकुओं के हाइड आउट्स और उनके काम करने की जानकारी हासिल की है, यदि हां तो उनको खत्म करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अर्ज किया १३ डाकू पकड़े गये हैं। आम तौर से यह होता है कि जब डाकू लोगों को पकड़कर ले जाते हैं तो उनकी आंखें बंद कर देते हैं। फिर भी जब कभी कोई हिन्ट दिया गया तो विभाग ने उस पर काम किया है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि देवीसिंह डाकू के गिरोह का सफाया किया गया और काउंटर में देवीसिंह को मारा गया, मैं जानना चाहता हूं कि देवीसिंह के गिरोह ने कोई बयानात दिये हैं और उन बयानात में किस मंत्री महोदय की भी बात कही गयी है कि वह उनकी संरक्षता कर रहे थे? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यह बात सही नहीं है।

*५-६—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

[हटा दिये गये]

सहारनपुर जिले में इण्टरटेनमेंट टैक्स

*७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर तथा जिले में जुदा-जुदा पिछले तीन सालों में कितनी-कितनी आमदनी Entertainment tax के रूप में सरकार को होती रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नत्थी 'क' देखिये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ३८० पर)

*८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर में मौजूदा Entertainment Tax Inspector, श्री एस० एन० गौड़ कब से सहारनपुर में आये हैं और उनके आने के बाद साल के पहले नौ महीनों में पिछले तीन सालों के उन्हीं महीनों से आमदनी में क्या अन्तर हुआ है और क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नत्थी 'ख' देखिये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ३८१ पर।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बतायेगी कि मौजूदा जो वहां पर गौड़ साहब आये हैं उनके आने के बाद तकरीबन ७० हजार की वृद्धि ९ महीने में हुई है, उसका विशेष कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

विशेष कारण कुछ नहीं है । अगर आप नत्थियों को देखेंगे तो मालूम होगा कि जहां गौड़ साहब नहीं देखते हैं वहां भी वृद्धि हुई है ।

[२१ फरवरी, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी आक्र ण के बाद कुल कितने व्यक्ति भारत रक्षा कानून में गिरफ्तार हुये हैं ? इनमें कितने किस-किस दल से संबंध रखते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

इस प्रदेश में १५-२-६३ तक ४६ व्यक्ति डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये हैं । उनमें से ३१ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, पांच रिपबलिकन पार्टी व बाकी दस व्यक्ति किसी दल के नहीं हैं ।

*२—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ने इनके साथ जेल में किस व्यवहार का आदेश दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को जो जेल में बन्द हों U. P. Security Prisoners Rules, 1950 को कुछ संशोधनों के साथ लागू कर दिया गया है ।

*३—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इनकी रिहाई पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इन मामलों में डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स के अधीन पुनरीक्षण की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

*४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

[हटा दिया गया]

गुड़ में वादे का सौदा

*५—श्री गेंदा सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपा कर बतायेंजी कि गुड़ का वादे का सौदा न हो सके इसके लिये भारत सरकार ने कदम उठाने के पहिले राज्य सरकार से सलाह ली या नहीं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गई ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

यद्यपि यह विषय केन्द्रीय सरकार का है तथापि वर्तमान सीजन में गन्ने के डाइवर्जन (Diversion) की अधिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह अनुभव किया गया कि यदि गुड़ में वादे का सौदा फार्वर्ड ट्रेडिंग की रोक थाम कर दी गई तो गुड़ के भाव कृत्रिम रूप से न बढ़ेंगे और चीनी मिलों को यथेष्ट गन्ने की सप्लाई कायम रह सकेगी । अतएव इस आशय से राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की गई ।

*६—श्री गेंदासिंह—

क्या राज्य सरकार ने गुड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है या ऐसा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ ने गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु सरकार को इस प्रतिबन्ध (Ban) की आवश्यकता फिलहाल प्रतीत नहीं होती है ।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि गुड़ बनाने में किसानों को जो इस वक्त कीमत मिलती है उससे एक सवाये का फर्क पड़ता है, तो सरकार इस समय किसानों को गुड़ बनाने में मदद क्यों नहीं करती ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

किसान खुद गुड़ बना रहे हैं इसलिये मदद का सवाल नहीं पैदा होता ।

श्री गेंदासिंह—

जिस वक्त वादे के सौदे पर रुकावट भारत सरकार ने लगाया उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको रोकने की चेष्टा की या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह तो मैंने अभी अर्ज किया कि राज्य सरकार ने इसमें रजामंदी दी कि फार्वर्ड सौदों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह सही है कि इस वर्ष जो पिछले वर्ष का भाव था उससे गन्ने के भाव में एक करोड़ रुपया सरकार के हिसाब के मुताबिक कम मिल रहा है और गुड़ बनाने में २ करोड़ रुपये का मुनाफा होता है तो सरकार इस २ करोड़ रुपये के मुनाफे का रास्ता क्यों बन्द कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कोई रास्ता नहीं बन्द किया जा रहा है । किसान ज्यादातर गुड़ बना रहे हैं यही कारण है कि मिलों में गन्ना नहीं जा रहा है ।

श्री गेंदासिंह—

फिर वादे के सौदे को रोकने का उद्देश्य क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह जनरल पालिसी की बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है । इससे गुड़ बनने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि किसान अपना गुड़ बना रहे हैं प्रश्न सीधा सीधा है कि वादे के सौदे पर रोक लगाने का कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अगर आपने जवाब सुना हो तो मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया था ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या यह सरकार, सभी बातों को देखते हुये कि किसानों को अधिक पैसा भी मिलेगा और भोजन की सामग्री में भी कोई कमी नहीं आयेगी, राष्ट्रीय हित में यह उचित समझती है कि गुड़ के उत्पादन को कम किया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गुड़ किसान जितनी जरूरत महसूस कर रहा है उतनी बना रहा है उसके उत्पादन में कोई कमी करने का सवाल नहीं है और न उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ के वादे के सौदे पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप गुड़ की कीमत बाजार में गिर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसा नहीं है ।

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नागरिक सुरक्षा समिति में कौन-कौन सदस्य हैं और वे किन-किन राजनैतिक दलों के हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

(१) शासन की जानकारी में प्रदेश में नागरिक सुरक्षा समिति कोई नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय "प्रदेशीय नागरिक परिषद्" से है । उसके सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(२) इस परिषद् का निर्माण राजनैतिक दलों के आधार पर नहीं हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३८२–३८३ पर)

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समिति के सदस्यों का मनोनयन उनके द्वारा किन-किन आधारों पर हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जिन व्यक्तियों को सहायक एवं उपयोगी समझा गया उनको नामजद कर दिया गया ।

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समिति की बैठक निर्माण के बाद कितनी बार हो चुकी है और मार्ग व्यय आदि में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

(१) २६ नवम्बर, १९६२ को परिषद् निर्माण हुई और उसके बाद परिषद् की बैठक दो बार हो चुकी है । प्रथम बैठक २ दिसम्बर, १९६२ तथा दूसरी बैठक ५ जनवरी, १९६३ को हुई ।

(२) मार्ग व्यय आदि में कोई खर्चा नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके जो महामन्त्री हैं उनका वेतन कितना है और उन्हें और कौन-कौन सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके बारे में इस समय तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उनको कोई वेतन इस कार्य के लिये नहीं मिलता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

और कोई सुविधा दी गई है ? वह बता दीजिए । मोटर या निवास स्थान और जो सुविधा दी गई हो, वह बता दीजिए या कोई सुविधा नहीं दी गई है, ऐसे ही बना दिए गए हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने जैसे कहा, इसकी तो मेरे पास में इस वक्त सूचना नहीं है कि कोई निवास-स्थान है या नहीं है । वेतन कोई नहीं है । रह गया दफ्तर वगैरह कोई है या नहीं तो इसकी सूचना आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का सवाल है, मेरा सवाल था कि कितना रुपया खर्चा हुआ है और पूछा जाता है कि मन्त्री को क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं तो कहते हैं कि नोटिस दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, नहीं। आफिस की बात अलग है। आपने कहा है टी० ए० वगैरह के लिए.....

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैंने पूछा है कि कौन-कौन-सी सुविधायें प्राप्त हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--

ओरिजिनल क्वेश्चन में तो यह था कि मेम्बरों के ऊपर कितना खर्च हुआ और आफिस का उसमें नहीं था। उसके लिये आप फिर से नोटिस दे दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

तीन ही तो सवाल आप स्वीकृत करते हैं और उसके बाद सप्लीमेंट्री भी नहीं करने देते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--

सप्लीमेंट्री तो आप ने किया, और करना चाहें तो कर लीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय नागरिक परिषद् का निर्माण हुआ है और उसकी दो बैठकें हुईं तो इन बैठकों में कौन-कौन से मुख्य निर्णय लिये गए और उनमें से कितनों को अब तक सरकार ने कार्यान्वित किया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह तो एक लम्बे ब्योरे का सवाल है ! अगर आप सूचना देंगे तो मैं बता दूंगा लेकिन उसमें की बहुत-सी चीजें अखबारों में निकल चुकी हैं .....

श्री चन्द्रजीत यादव--

जो मुख्य-मुख्य हैं उनको बता दीजिए और उनमें से कितनों को सरकार ने कार्यान्वित किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

असल में पहली बैठक में कई उप-समितियां इन्होंने बनायीं विविध काम करने के लिए, एक धन संग्रह करने के लिए बनायी, एक जन-सम्पर्क और सहयोग के लिए बनायी, मेडिकल समिति बनायी, युवक सुरक्षा समिति बनायी, सेना सुरक्षा समिति बनायी और आर्थिक समिति बनायी। मैं समझता हूं कि उन समितियों के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि क्या-क्या कार्य यह करेंगी।

श्री रक्षपालसिंह--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रदेशीय नागरिक परिषद् है इसका कंट्रोल और सुपरविजन जिला स्तर की कमेटियों पर भी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरा खयाल है कि होना चाहिये। इसकी मेरे पास सूचना नहीं है क्योंकि इस विषय में कोई प्रश्न नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसे एक दिन माल मन्त्री श्री हुकुमसिंह जी ने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठ बन्धन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर कौन-सा कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को इस कमेटी में नहीं रखा गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा, किसी पार्टी विशेष के रिप्रिजन्टेटिव की हैसियत से यह कमेटी नहीं बनाई गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमने पूछा था कि कारण क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों को इसमें नहीं रखा गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि राजनीति के बेसिस पर किसी को इसमें नहीं रखा गया है। गवर्नमेन्ट जो जवाब देना चाहे वही दिया जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि यह कमेटी किसी दलगत आधार पर नहीं बनाई गई है तो जिन लोगों को नामिनेट किया गया है उसमें क्या मापदंड रखा गया है और किस आधार पर उनका नामिनेशन हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यदि आप ने मेरा उत्तर सुन लिया होता तो आप यह प्रश्न न करते। उसमें मैंने यह कहा कि जिन लोगों का सहयोग समझा गया उनको रखा गया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस समिति में बार्डर डिस्ट्रिक्ट के कौन लोग हैं, यदि हां, तो उनका नाम क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

समिति की सूची रखी है उस को आप देख लें, मालूम हो जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं बार्डर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के नाम जानना चाहता हूं जिनको उसमें रखा गया है उत्तराखंड के कितने लोग हैं वह बतला दें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बार्डर डिस्ट्रिक्ट को जो रिप्रिजेन्ट करते हैं, उसमें हमारे मुख्य मन्त्री जी भी हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

लिस्ट के नामों से यह प्रतीत होता है कि जितने नाम उसमें दिये गये हैं उनमें बार्डर डिस्ट्रिक्ट यानी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल का एक भी आदमी नहीं है जिनके ऊपर इस प्रदेश की रक्षा निर्भर है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

प्रदेश की रक्षा बार्डर डिस्ट्रिक्ट पर है यह बात मैं मानता नहीं हूं। वह रक्षा तो सभी लोगों को करनी है। समिति में जो लोग हैं वह इस प्रदेश की रक्षा करेंगे यह भी मैं नहीं मानता हूं। जो मेम्बर हैं या नहीं हैं उन सब के ऊपर यह भार है।

ऐसोसिएटेड रिडिफ्युजन फिल्म कम्पनी द्वारा फरेंदा तहसील में चित्र लेना

*१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के उत्तरी सरहद पर बसे महराजगंज तथा फरेंदा तहसीलों के गांवों के रहने वाले लोगों तथा सरहद का फोटो जनवरी के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में Associated Redefusion नामक एक अंग्रेजी फिल्म कम्पनी के लोगों ने जो अपना सम्बन्ध यू० एन० सी० एफ० से बताते हैं लिया है ? यदि हां, तो यह कार्य वे लोग किसके इजाजत से कर रहे हैं तथा इसके पीछे क्या उद्देश्य है ?

श्री नवलकिशोर--

गत १० जनवरी से १८ जनवरी तक उक्त कम्पनी के कुछ प्रतिनिधियों ने गोरखपुर जिले की तहसील महाराजगंज के करमहा, रामपुरवा और खेसरहा ग्रामों तथा सदर तहसील के चरगांवां मुर्गीपालन केन्द्र के चित्र एक डाक्यूमेंटरी फिल्म के निर्माण के सम्बन्ध में लिये हैं। यह कार्य उन्होंने भारत सरकार की अनुमति से किया है और इस का उद्देश्य F. A. O. के द्वारा चलाये गये Freedom from Hunger आन्दोलन के सम्बन्ध में इंगलैन्ड की Committee of Freedom from Hunger Campaign द्वारा आगामी मास के मध्य में आयोजित किये जाने वाले सप्ताह में प्रदर्शन करने का है।

*११--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह फिल्म कम्पनी वही है जिसने महात्मा गांधी के ऊपर कोई तस्वीर बनाई है, जिसे भारत सरकार ने जब्त कर लिया है ?

श्री नवलकिशोर--

राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रिडिफ्यूजन अंग्रेजी फिल्म कम्पनी इंग्लैन्ड की वही कम्पनी है जिस कम्पनी ने "नाइन डेज आफ रामा" नामक पिक्चर गांधी जी के ऊपर बनाई थी और जिस पिक्चर की प्रतिलिपि भारत सरकार ने सारे देश में जब्त कर ली है ?

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, यह वही प्रश्न है जिसका जवाब मैं अपने उत्तर में दे चुका हूं कि उसकी सूचना इस सरकार के पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि कर्महा और दूसरे गांव जो लिस्ट में दिए हुए हैं उन गांवों में जा कर इस कम्पनी ने वहां लोगों को नंगा कर के उनके चित्र लिये और उन चित्रों पर ही यह "फ्रीडम फ्राम हंगर" नामक फिल्म बन रही है जो हमारी गरीबी का प्रर्शन करेगी ?

श्री नवलकिशोर--

ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) --

क्या माननीय मन्त्री जी को ऐसी सूचना है कि यह चित्र लेने कंपनी के पदाधिकारियों के साथ भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी गये थे ?

श्री नवलकिशोर--

उनके साथ के लोगों के डिटेल्स नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि गोरखपुर, बस्ती, और देवरिया के सरहदी गांवों के भी फोटो इस कंपनी ने लिये हैं और उस सम्बन्ध में मैंने स्वयं जिलाधीश गोरखपुर को यह इत्तला लिखित दी है कि इस प्रकार कंपनी हमारी गरीबी का उपहास कर रही है और इसी कंपनी ने "नाइन डेज आफ राम" नामक फिल्म भी महात्मा गांधी पर बनायी थी और जिसमें इंडियन पीपुल और भारत सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया था जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नवलकिशोर--

गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट को उन्होंने क्या लिखा यह मैं नहीं जानता, लेकिन सीमा के चित्र नहीं लिये गये और इस कम्पनी का ऐसा कोई मंशा नहीं था। "फ्रीडम फ्राम हंगर" जो फिल्म बन रही है यह इसलिये कि उसे दिखा कर इंग्लैन्ड की जनता में जाग्रति पैदा की जाय और उससे कुछ पैसा लिया जाय ताकि योजनाओं पर कुछ काम हो सके इस उद्देश्य से यह फिल्म तैयार की जा रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मंत्री जी ने बतालाया कि वे गोरखपुर में कहां गये इसकी इत्तला उनको नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से जब यह आये थे तो उनके मूवमेंट चूंकि बार्डर एरियाज में हैं इसलिये उनकी जानकारी सरकार ने रखी या नहीं ? यदि रखी, तो क्या जानकारी उसको प्राप्त हुई ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने सीमाओं के चित्र नहीं लिये। जिन गांवों में उन्होंने चित्र लिये हैं उस क्षेत्र के प्रमुख उनके साथ थे और उनके सामने चित्र लिये गये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं जानना चाहूंगा कि गोरखपुर के बार्डर एरिया में कौन खास बात थी जिसके चित्र लेने के लिये सरकार द्वारा इस कंपनी को हुक्म मिल गया और वह दूसरे प्रदेशों, बंबई आदि को छोड़ कर इसी एरिया में चित्र लेने आयी ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने कहा कि इसमें सवाल सीमा का नहीं आता....

(व्यवधान)

गोरखपुर, बस्ती के कुछ ब्लाक्स हैं जिनमें एक्सपेण्डिड न्यूट्रिशन के सम्बन्ध में प्रोग्राम चल रहा है इसलिये उन गांवों को छांट कर चित्र लेने की बात पैदा हुई।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या मन्त्री जी को पता है कि इससे भी कम न्यूट्राइज्ड एरियाज मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में हैं तो केवल उस स्थान को ही क्यों चुना गया, दूसरे एरियाज को क्यों नहीं चुना गया ?

श्री नवलकिशोर--

जो यू० एन० आई० सी० एफ० है उसके द्वारा गवर्नमेन्ट आफ़ इण्डिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की परमीशन लेकर और यहां की सरकार से इजाज़त ले कर इस कम्पनी ने वहां के चित्र लिये हैं और इस प्रकार के लांछन निराधार हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो नंगे लोगों के फोटो लिये जाने की बात कही गयी है उसके बारे में क्या यह सरकार भारत सरकार से सूचना प्राप्त करने की कृपा करेगी कि यह वही कम्पनी है जिसने यह किया है तथा "नाइन डेज़ आफ़ रामा" नाम की फिल्म भी इसी ने बनायी है और क्या जब वे चित्र लेने गये तो प्रदेशीय सरकार ने अपने सूचना विभाग का कोई अधिकारी उन के साथ भेजा या नहीं ?

श्री नवलकिशोर--

जो सरकार के पास सूचना है उसके अनुसार प्रमुख महोदय चित्र लेते समय साथ थे। यह कहना कि नंगे आदमियों के चित्र लिये गये, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह--

क्या उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके द्वारा विदेशियों द्वारा चित्र लिये जाने पर प्रतिबन्ध हो ?

श्री नवलकिशोर--

इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मन्त्री जी इस बात की फिर से जांच करायेंगे कि १० जनवरी से १८ जनवरी के बीच में इस फिल्म कम्पनी ने फोटो लेने शुरू किये तो दैनिक पत्र "अमृतबाजार पत्रिका" में लेख छपे और उन्होंने फिल्म कम्पनी के लीडर जो मि० ब्राउन थे उनसे कहा कि इस तरह से हमारे बच्चों का फोटो क्यों लिया जा रहा है और नंगे चित्र क्यों लिये जा रहे हैं तो वह फौरन् ही कलकत्ता मेल से रवाना हो गये और वहां से इंगलैन्ड चले गये, इसकी पूरी सूचना मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना आप गवर्नमेन्ट से जानना चाहते हैं या अपने आप देना चाहते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं आप के द्वारा गवर्नमेन्ट से पूछ रहा हूं कि जिस समय "अमृत बाजार पत्रिका" में और सारे अखबारों में यह खबर छपी कि यह वही कम्पनी है जिसने "नाइन आवर्स आफ रामा" नाम की पिक्चर बनायी है और हमारे गांवों में जा कर हमारी गरीबी के नंगे चित्र लिये और हमारी सरहद में भगवानपुर के चित्र लिये तो जब कि प्रेस कारेस्पांडेंट उस अखबार का स्वयं मिला कम्पनी वालों से और उस की इत्तला जिलाधीश को दी तो जिलाधीश ने उस कम्पनी को ऐसे चित्र न लेने देने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, यह तो इतना बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। अगर माननीय पांडेय जी लिख कर दे दें तो उसके ऊपर जानकारी की जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैंने लिख कर जिलाधीश को दिया है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि उस फिल्म कम्पनी द्वारा गोरखपुर के गांवों का चित्र लेने के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश था ? यदि हां, तो क्या गोरखपुर के अधिकारियों ने अपने देख-रेख में वह चित्र लेने दिये ?

श्री नवलकिशोर--

इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के प्लानिंग विभाग को लिखा गया और यहां से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा गया कि उनको जो भी सुविधा हो वह दी जाय।

गोरखपुर में प्रतिरक्षा मंत्री के आगमन के दिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी

*१२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में प्रतिरक्षा मंत्री जो २७ जनवरी, १९६३ को गोरखपुर विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण देने आये थे उन के निवास स्थान पर कोई व्यक्ति छुरे के साथ पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में पूरे वाकये की रपट मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

प्रतिरक्षा मंत्री २७ जनवरी, १९६३ को नहीं वरन् १७ जनवरी को गोरखपुर गये थे और उस दिन १ बजे दोपहर को विश्वविद्यालय के उपकुलपति के निवास स्थान पर पहुंचे थे। उसी दिन सुबह लगभग ९ बजे उपकुलपति के निवास स्थान के पास सड़क पर एक व्यक्ति छुरे से एक अन्य व्यक्ति को जिससे उसका झगड़ा हो रहा था धमकाते हुये सी० आर० पी० सी० की धारा १५१ के अधीन गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई

अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। वह एक पुराना हिस्ट्री शीटर है और उसके विरुद्ध सी० आर० पी० सी० की धारा १०७ के अन्तर्गत मामला अदालत में विचाराधीन है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी ने आज के अखबार में छपी हुई १८ जनवरी की उस रिपोर्ट को देखा है जिसमें कहा गया है कि वहां पर छुरी लेकर एक व्यक्ति माननीय रक्षा मंत्री के सामने घूम रहा था, उनके बंगले के सामने और संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने पकड़ा है ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने अर्ज किया, हमारे डिफेन्स मिनिस्टर साहब एक बजे दोपहर को वहां पहुंचे और यह वाकया ९ बजे सबेरे का है। इससे उसका क्या वास्ता है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, उसके बाद वह गिरफ्तार किया गया और यह छुरा उसके झोले से निकला जो उस समय वहां मौजूद था। उसका बयान पुलिस ने लिया। तो क्या माननीय मन्त्री जी उसका बयान सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मैं कहता हूं वह तो ४ घंटे पहले पकड़ा गया था। आप कहते हैं बाद को।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

उसके बयान को सदन के सामने क्या आप रखेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

चूंकि यह केस सबजूडिस है, उसका यहां से वास्ता क्या है ?

गन्ना संघ एवं गन्ना समिति कर्मचारियों की मांगें

*१३--श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेशीय गन्ना संघ एवं गन्ना समिति कर्मचारी यूनियन ने श्रम मंत्राणी को मई, १९६२ में एक पत्र प्रेषित किया था जिसमें यह मांग की गई थी कि गन्ना संघ तथा गन्ना समितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत तय कराये जायं तथा क्या मुख्य मंत्री से भी इस विषय में अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

*१४--श्री बालकराम वैश्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड में विभिन्न उप विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता देने की नीति गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्रचलित प्रणाली के अनुसार ही वर्ष १९५१-५२ से प्रारम्भ की गई थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना --

जी हां।

*१५--श्री बालकराम वैश्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव केन यूनियन्स फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ में गन्ना समिति में ७५--१२० के वेतन-क्रम में कार्य करने वाले एक कर्मचारी को वर्ष १९५८ में ८०-२४० वाले वेतन-क्रम में नियुक्ति करने के बावजूद भी उसके विशेष भत्ते को वेतन में सम्मिलित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या उसी प्रकार से जो अन्य व्यक्ति

गन्ना समितियों या जिला गन्ना कमेटियों से संघ कार्यालय में नियुक्त किये गये उनके विशेष भत्ते को भी वेतन में सम्मिलित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। अन्य कर्मचारियों के विषय में प्रश्न फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति के विचाराधीन है।

श्री बालकराम वैश्य—

कब तक विचार समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बहुत जल्दी इस पर विचार होकर फैसला हो जायेगा।

श्री बालकराम वैश्य—

क्या गन्ना आयुक्त के कोई ऐसे आदेश जारी किये गये जिसमें पहले उनको स्पेशल एलाऊन्स दिया गया, फिर उसको स्पेशल पे में परिणत किया गया और फिर उस स्पेशल पे को रद्द कर दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसी सूचना नहीं है, अगर तफसील से लिखकर माननीय सदस्य नोटिस दें, तो सूचना दे दी जायेगी।

श्री बालकराम वैश्य—

मेरे पास उस आर्डर की प्रतिलिपि है, कहिये तो पढ़ दूं ? यह १२ इन्सटालमेन्ट्स में वसूल किया जा रहा है, उनके प्राविडेन्ट फंड से वसूल किया जा रहा है ऐसे आदेश हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप भाषण दे रहे हैं, सवाल नहीं है। कोई सवाल हो तो पूछिये।

सेक्रेटरी, केन यूनियन, बरहज के खिलाफ शिकायत

*१६—श्री उग्रसेन—

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की सूचना है कि दिनांक २१ दिसम्बर, १९६२ को सेक्रेटरी, केन यूनियन, बरहज थाने में रखे हुये यूनियन के सेफ को जबरदस्ती तुड़वा रहे थे ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्राप्त सूचना के अनुसार जबरदस्ती नहीं बल्कि, जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया, तथा अध्यक्ष, बरहज केन यूनियन के समक्ष, थाने में रक्खे हुये समिति का सेफ कुंजी खो जाने के कारण तुड़वाया गया था। चूंकि सेफ में रक्खी हुई रोकड़ को कैश बुकों के अनुसार सही पाया गया, अतएव सेक्रेटरी, केन यूनियन, बरहज के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि उक्त सेक्रेटरी ने १० हजार रुपये जो गन्ने की कीमत थी किसी व्यापारी को सूद पर दे दिया था और अध्यक्ष यूनियन के पकड़ने पर उक्त कार्यवाही कर रहा था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। यह सर्वथा निर्मूल है।

*१८—श्री उग्रसेन—

क्या गन्ना विकास मंत्री सेक्रेटरी, केन यूनियन, बरहज के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उस सेफ की कितनी कुंजियां हैं और किस-किस के पास रहती हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसकी कुंजी आनरेरी सेक्रेटरी के पास रहती थी । चूंकि वह खो गईं थी, इसलिये अध्यक्ष के सामने उसे खुलवाया गया ।

श्री उग्रसेन—

दोनों कुंजियां एक ही साथ कैसे और क्यों खो गईं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरे पास यह इत्तला है कि आनरेरी सेक्रेटरी के पास कुंजी थी जो उनसे खो गई । इसके लिये उनसे जवाब तलब किया गया है ।

श्री उग्रसेन—

१० हजार रुपया गन्ने का दाम जो आया वह कहां रखा था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि १० हजार रुपया आया और उसमें रखा गया । ९४७ रुपये उसमें से निकले थे ।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि थाने में रिपोर्ट के तीन दिन पहले गन्ने के दाम जब किसानों को चुकता करने थे तो १० हजार रुपये केन यूनियन के सेक्रेटरी ने एक बगल के व्यापारी को सूद पर दे दिया था और ३ दिन वह सूद पर रहा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह सही नहीं है ।

देवरिया जिले में घर फूंकने की घटनाएं

*१९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर थाने के अकटहिया उर्फ पटिआरी, ग्राम में जनवरी, १९६३ में किसी यादव का मकान जला डाला गया है ? यदि हां, तो इसके अभियोग में कितने लोगों का चालान हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—

दिनांक ६ जनवरी, १९६३ को श्री महादेव पुत्र कवलेश्वर यादव, निवासी ग्राम अकटहिया ने थाने पर सूचना दी थी कि ५/६ जनवरी की रात को उसका घर फूंक दिया गया है । इसके आधार पर धारा ४३६ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया और इसकी जांच हो रही है। अभी किसी अभियुक्त का चालान नहीं हुआ है ।

*२०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के बरहज थाना के परसिया तिवारी नामी ग्राम में नवम्बर, दिसम्बर, १९६२ में हरिजन टोले को फूंक डाला गया है ? यदि हां, तो इसके अभियोग में कितनों का चालान हुआ है ?

श्री नवलकिशोर--

दिनांक १३ नवम्बर, १९६२ को उक्त ग्राम के श्री बहती हरिजन की झोपड़ी को कुछ व्यक्तियों द्वारा जला दिये जाने तथा उस पर आक्रमण किये जाने आदि की सूचना मिलने पर मुकदमा कायम किया गया और जांच के पश्चात् इसमें ६ अभियुक्तों का चालान किया गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महादेव ने किन-किन लोगों पर रिपोर्ट की है और जांच में देर होने का क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर--

मागीं अहीर पुत्र रामदेव उस गांव का है जिस पर मुकदमा कायम किया गया है। यह करार है, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या उस रिपोर्ट में श्री सुन्दरसिंह जी का भी नाम है ?

श्री नवलकिशोर--

नोटिस चाहिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

बहती हरिजन की झोपड़ी जो फूंकी गई क्या उसकी आग से छः और झोपड़ियां भी जल गईं ?

श्री नवलकिशोर--

इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन--

बहती हरिजन का घर और उसके बाद पूरी हरिजन बस्ती जलने के बाद जो मुकदमा कायम हुआ उसमें चार्ज-शीट क्यों नहीं लगी ?

श्री नवलकिशोर--

यह मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।

*२१-२२--श्री कल्पनाथसिंह--

[हटा दिये गये।]

रिहन्द बांध से बिहार में सिंचाई

*२३--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिहार में रिहन्द बांध का पानी किस सन् में सिंचाई के लिये दिया जाता है और इससे प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष कितना रुपया प्राप्त होता है तथा गतवर्ष तक कुल कितना रुपया प्राप्त होना था और कितना प्राप्त हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

रिहन्द बांध से लगातार ६००० क्यूसेक पानी बिजली बनाने के लिये छोड़ा जा रहा है जिससे बिहार प्रदेश में सोन नहर द्वारा ५ से ८ लाख एकड़ अधिक (दोनों फसलों में) सिंचाई हो सकेगी। अतएव बिहार सरकार से रिहन्द बांध के निर्माण में व्यय हुई धनराशि का उचित भाग उत्तर प्रदेश सरकार को दिये जाने के बारे में बातचीत चल रही है।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैंने पूछा था कि किस सन् से पानी सिंचाई के लिये दिया जाता है, उससे प्रति वर्ष कितनी आय होती है और कितना रुपया बकाया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर आप मेरा उत्तर समझ लेते तो यह न कहते । मैंने उत्तर में कहा कि इतनी सिंचाई हो सकेगी । सिंचाई होने पर ही दाम का प्रश्न उठेगा । हमने कहा कि पानी आप इस्तेमाल करेंगे, उसके दाम दीजिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

पानी अभी तक नहीं दिया गया तो सिंचाई की अनुमानतः लागत तो बता दें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जब इस्तेमाल करने लगेंगे उस समय लागत का निश्चय हो सकेगा । हमने बिहार सरकार से कहा कि आप इस पानी से बांध बनाकर बिजली भी पैदा कर सकेंगे, तो उसके भी और सिंचाई के भी दाम दीजिये । गन्डक बांध योजना जब बनी तो उस समय बिहार को पानी की आवश्यकता थी । हमने उनसे कहा कि हम गन्डक की बात तब निश्चय करेंगे जबकि आप हमारे पानी के दाम देंगे ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्टतया अनुमान बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

करीब ८।। करोड़ रुपया पानी का हमें बिहार सरकार से मिलना चाहिये ।

*२४--२६--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला आजमगढ़)--

[७ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस

*२८--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा आदेश सरकार को प्राप्त हुआ है कि बन्दूक तथा रायफल व रिवाल्वर का लाइसेंस देने के लिये हैसियत की जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल चाल-चलन की ही जांच करायी जाया करे और बन्दूक व रायफल का लाइसेंस संबंधित हाकिम परगना ही दे दिया करें ?

श्री नवलकिशोर--

प्रश्न में अंकित आशय के कई आदेश केन्द्रीय सरकार से नहीं प्राप्त हुये हैं, किन्तु आर्म्स, ऐक्ट, १९५९ (Arms Act 1959) जो कि १ अक्तूबर, १९६२ से लागू किया गया है की धारा १४(२) के अनुसार प्रार्थी की हैसियत कम होने की वजह से ही बन्दूक, रायफल तथा रिवाल्वर का लाइसेन्स देने की प्रार्थना अस्वीकृत नहीं की जा सकती है । चाल-चलन, प्रार्थी की उपयुक्तता (fitness) इत्यादि के विषय में यदि लाइसेन्स प्रदान करने का अधिकारी (Licensing Authority) आवश्यक समझें तो जांच करा सकते हैं । उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार बन्दूक तथा २२ बोर रायफल का लाइसेन्स जिलाधीश तथा (हाकिम परगना) (Sub-Divisional Magistrate) दोनों ही दे सकते हैं ।

*२९--श्री गणेशचन्द्र काछी--

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट--तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

रिहन्द तथा मार्टिन कम्पनी की बिजली का रेट

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि रिहन्दडैम तथा मार्टिन कम्पनी के बिजली के रेटों में भिन्नता के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बिजली की लागत कई बातों पर निर्भर है जैसे डिमांड का लोड फैक्टर तथा पावर फैक्टर, ट्रांसमिशन लाइनों तथा सब स्टेशनों का खर्चा और ट्रांसमिशन तथा ट्रांसफार्मेशन में होने वाली विद्युत् शक्ति की स्वाभाविक क्षति। चूंकि रिहन्द तथा मार्टिन कम्पनी की बिजली उत्पादन की लागत भिन्न है अतः बिजली की दरें भी भिन्न हैं।

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[५ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*३२-३३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[२८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में अपराध

*३४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राय बरेली जिले की तहसील महराजगंज के अन्तर्गत चारों थानों बछरावा, शिवरचतगंज, महाराजगंज एवं मोहनगंज में १९६१-६२ में कितनी डाकेजनी व चोरियों की वारदातें हुयीं ? क्या उनमें सब वारदातों की जांच हो चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों और यदि होगी तो कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३८४ पर)

थाना भीमपुरा

*३५—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि कुछ माह पूर्व भीमपुरा पुलिस थाना (जिला बलिया) जो किरीहीड़ापुर में है उस को भीमापुर में लाने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया गया था ? यदि हां तो उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, चूंकि ग्राम भीमपुरा में कोई उचित भवन उपलब्ध नहीं है अतः ग्राम किरीहीड़ापुर से थाने को अभी हटाया जाना संभव नहीं है। वर्तमान थाने की इमारत की आवश्यक मरम्मत करा दी गई है।

*३६-३८—श्री विजयसिंह—

[७ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[७ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[८ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४४—श्री ऊदल—

[२० फरवरी, १९६३ को प्रश्न ४० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

सचिवालय के पुराने संयुक्त सचिव, उप-सचिव

*४५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार ६ दिसम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि उप-सचिव, तथा संयुक्त सचिवों का स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है और वे किस-किस विभाग के कौन-कौन हैं ? क्या इस योग्यता के अन्य व्यक्ति नहीं है जो इनका स्थान ग्रहण कर सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकारी आदेशों के अनुसार सचिवालय के अफसरों का साधारण तौर पर एक स्थान से तीन से चार साल के बाद स्थानान्तरण होना चाहिए । केवल ७ ऐसे संयुक्त-सचिव तथा उप-सचिव हैं जिनको एक स्थान पर ४ वर्ष से अधिक हो गए हैं । इनका स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से नहीं किया गया । इसलिए किसी व्यक्ति की योग्यता का इसमें प्रश्न नहीं उठता है । उन १८ संयुक्त सचिव तथा उपसचिवों की जिनको सचिवालय में ३ वर्ष से अधिक हो गये हैं, सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८५ पर)

*४६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार ने १८ व्यक्तियों में से किसी का स्थानान्तरण किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अब केवल ७ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक स्थान पर ४ वर्ष से अधिक हो गए हैं । इनका स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणवश नहीं किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

मुरादनगर विद्युत् स्टेशन को आग लगने से क्षति

१—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के मुरादनगर विद्युत् सब-स्टेशन में जनवरी, सन् १९६३ के तृतीय सप्ताह में आग लग जाने के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो उक्त घटना का विस्तृत विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, एक १३२ के० वी० सब स्टेशन मुरादनगर में बन रहा है जिसके निर्माण के समय १३–१४ जनवरी, १९६३ की रात में आग लग गयी थी । आग के कारण जो हानि हुई उसका मूल्य अनुमानतः ९ लाख रुपये है । घटना का विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी च आगे पृष्ठ ३८६ पर)

२—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त घटना की जांच कराने का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा तथा जांच कब तक समाप्त कर देने का आदेश दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, सरकार ने श्री बी० एन० मेहरोत्रा, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग को जांच पड़ताल आफिसर नियुक्त किया है और जांच को शीघ्र ही पूरा करने का उन्हें आदेश दिया गया है ।

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[७ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया ।]

उपमंत्रियों का यात्रा भत्ता

४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता दृष्टिकोण से मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के भत्ते में कोई कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मंत्रियों को कोई भत्ता नहीं मिलता इसलिये उसमें कटौती का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

उप मंत्रियों को यात्रा के समय First class officers की भांति दैनिक भत्ता मिलता है जिसकी दरें सदन के सदस्यों के दैनिक भत्ते से भी कम हैं इसलिये उप-मंत्रियों के दैनिक भत्ते की दरों में कटौती करने का कोई विचार नहीं है ।

५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१ मार्च, १९६३ के लिए प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

६–८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

९–१०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को सिसवां ग्राम से आवेदन-पत्र

११—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री प्रथम सत्र (१९६२) के ९ वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं० ४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र में यह कहा गया है कि स्थानीय थानेदार और पुलिस अधीक्षक के यहां इसके पहिले प्रार्थना-पत्र दिये गये पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त प्रार्थना-पत्र में यह कहा गया है कि प्रार्थी ने दिनांक ८–१–६२ को एक प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष, मधुबन और पुलिस अधीक्षक को भेजा था । यह प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष अथवा पुलिस अधीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि गांव सभा के प्रधान का इस सम्बन्ध में क्या बयान है और इनके अतिरिक्त और किसका-किसका बयान असत्यता की पुष्टि के लिए लिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्री दासी, प्रधान ग्राम सिसवा देवारा ने अपने प्रार्थना-पत्र का समर्थन किया, किन्तु कथित आरोपों की पुष्टि में शहादत पेश न कर सका । निम्नलिखित व्यक्तियों ने पूछतांछ पर यह बताया था कि कथित अरोपों में सत्यता नहीं है:—

सर्वश्री (१) रामदेव अहिर (२) सुदामा (३) अमरीक (४) लगनअहीर (५) मल्हौर चौकीदार, व (६) सुखदेव ।

मूढ़ा थानान्तर्गत श्रीमती रईसन की मृत्यु की जांच

१३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रईसन बीबी लल्ला, जो २५–२६ अक्तूबर, १९६२ ग्राम बीरपुर, बरियार, थाना मूड़ा, जिला मुरादाबाद में मरी, उसकी पुलिस स्टेशन पर क्या रिपोर्ट दर्ज हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस संबंध में थाने पर जो रिपोर्ट लिखाई गई उसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८७ पर)

१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मरने वाली औरत का पोस्टमार्टम किस तारीख को किस समय हुआ और किस डाक्टर ने किया और मरने के क्या कारण बतलाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल आफिसर, पुलिस अस्पताल, मुरादाबाद ने दिनांक २७–१०–६२ को १ बजे दिन में किया । मृत्यु के कारण के बारे में डाक्टर कोई राय नहीं दे सके ।

१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को इस काण्ड के बारे में कोई दरख्वास्त प्रधान, ग्राम सभा, वीरपुर बरियार की तरफ से प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस घटना के संबंध में ग्राम सभा प्रधान का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था । मामले की जांच हो रही है ।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ की प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है । वह इस प्रकार है—

"उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २०२ के उपनियम (१) के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष ने श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट को उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ की प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया है ।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों की नामावली में संयुक्त समाजवादी दल के कम सदस्य रखने पर आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों की जो नामावली घोषित हुई उसमें हम लोगों के दल का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है और न हमको बुलाकर हमारी इस विषय में कोई राय ही ली गयी, हमसे पूछा भी नहीं गया । श्रीमन्, आप सर्वसत्ता संपन्न हैं, आप यहां विराजमान हैं, आप उसका जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो श्री अध्यक्ष के अधिकार की बात है । आपके दल से श्री कमलासिंह को अधिष्ठाता मंडल में रखा गया है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन, हमारे इतने अधिक सदस्य हैं, उनमें से केवल एक को ही रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो माननीय अध्यक्ष का डिस्क्रिशन है ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, पिछले साल हमको बुलाया गया था । लेकिन क्या इस प्रकार से बिना हमसे पूंछे हुए घोषणा कर देने से हमें अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है ? कृपया आप हमारे ऐतराज को माननीय अध्यक्ष के कदमों तक पहुंचा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वे तो सब बातें जान ही लेंगे ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हमने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

कल मैंने पत्रकार बंधुओं से निवेदन किया था कि कल उन्होंने माननीय गया प्रसाद जी को जनसंघ लिख दिया था और आज भी जनसंघ लिख दिया है । इसी प्रकार रघुनाथ सिंह जी को स्वतंत्र लिख दिया है । पत्रकार बंधु जरा इसको देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कन्फ्यूजन मालूम होता है क्योंकि ऐसे दो सदस्य हैं जिनके नाम गयाप्रसाद हैं । एक जनसंघ के हैं और दूसरे आपके दल के हैं । इसमें संशोधन कर दिया जायगा ।

श्री चन्द्रशेखर की बलरामपुर अस्पताल में चिकित्सा के संबंध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, एक और निवेदन है कि हमारी पार्टी के नेता श्री गेंदासिंह जी ने एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा था तथा एक पत्र गुप्ता जी को लिखा था । चन्द्रशेखरसिंह जी ने भी एक पत्र गुप्ता जी को लिखा था । श्री उमाशंकर जी ने एक अल्पसूचित प्रश्न दिया था कि चन्द्रशेखर जी एम० पी० का बलरामपुर अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने अनादर किया, उनकी देखभाल नहीं की और उनको डिस्चार्ज कर दिया । आपने दफा ५३ का प्रश्न अस्वीकार कर दिया और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उसको स्वीकार किया । मैं जानना चाहता हूं कि उस सवाल का क्या हुआ ? उसको ७-८ दिन हो गये हैं । और अब ५-६ दिन के लिये यह सदन उठ रहा है । उसका उत्तर सदन में आ जाना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता । उसको देख कर बता दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अब आप क्या बतायेंगे, अब तो छुट्टी हो रही है । आपने ही उत्तर दिलाने का आश्वासन दिया था, उसका उत्तर हो जाना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कुछ आप पूछें उसके बारे में सारी बातें मेरे दिमाग में हों और मैं उनका उत्तर दे दूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपने खुद ही हाउस में आश्वासन दिया था और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार किया था ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)--

बात यह है कि कई सदस्य मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझसे शिकायत की कि इन्हें सचेस्टिव एपेंडिसाइटीज का खयाल है जबकि डाइनोस कोलाइटिस किया गया है । मैंने

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

तुरन्त बलरामपुर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन मिलाया और उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने सारे कागजात देख कर बतलाये कि उन्हें कोलाइटिस ही है, एपेंडिसाइटिज नहीं है। अगर हम उनका आपरेशन कर देते तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती। खाली एक्सरे वगैरह की बात नहीं है। उनको ६ दिन तक अस्पताल में रखा गया और तमाम टेस्ट किये गये, उनका ब्लड काउन्ट किया गया। उनसे सम्बन्धित कागजात को माननीय सदस्य देख लें तो समझ सकते हैं कि डाइगनोसिस गलत नहीं की गयी। वह राइट साइड ही है, रांग साइड नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

सिर्फ डाइगनोसिस की बात नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मुझे तकलीफ होती है जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जैसे बुजुर्ग इस तरह की बात सदन में कहते हैं कि उनसे बलरामपुर के सुपरिटेंडेंट से बातचीत हुई। मैं फिर यहां बतलाना चाहता हूं कि हमारे सामने ही उन्होंने फोन मिलाया, लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब फोन पर नहीं मिले। फिर उन्होंने हमें बतलाया कि गुप्ता जी से बात करके मैं बतलाऊंगा और आज सदन में इस तरह की बात कह रहे हैं। हो सकता है कि गुप्ता जी से उनकी बाद में आपस में बातचीत हो गयी हो, लेकिन सदन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय सदस्य को मैं बतला दूं कि सुपरिटेंडेंट, बलरामपुर, एक मिस्टर गुप्ता ही हैं। उन्होंने मुझे सारे कागजात दिखलाये थे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह जो कहा गया है कि चन्द्रशेखर जी ने वहां से डिस्चार्ज ले लिया, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं लिया बल्कि उनको वहां से निकाल दिया गया जैसा कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से मालूम होगा और ये सारी चीजें डाक्टर से ताल्लुक रखती हैं, तो इसका तो जवाब दे दीजिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह बात गलत है कि उनको निकाला गया। उनको एक हफ्ते तक अस्पताल में रखा गया और उनका ट्रीटमेंट हुआ। इलाज सम्बन्धी सारे डाकुमेंट्स मौजूद हैं। जब उन्होंने डिस्चार्ज मांगा तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

श्री बलवानसिंह—

चेकिंग के लिये उनको ७ दिन तक अस्पताल में रखा गया और डाक्टरों ने उनकी कोई परवाह नहीं की जिससे वे वहां से चले गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब हो चुका है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना है उसमें यह लिखा हुआ है कि :

डाइरेक्टर आफ एजूकेशन की तरफ से कुछ गजट में छपा है, उस पर आप कहते हैं कि इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा होता है। एक तो यह बहुत लम्बा है, दूसरे इस डाकुमेंट का इस हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है लिहाजा मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री काशीनाथमिश्र (जिला बलिया)—

आप सुना तो दीजिये।

आप नियम में पढ़ लें। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ६७ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में साफ लिखा है कि "तत्पश्चात् सदस्य अपनी शिकायत, यदि कोई दस्तावेज हो तो उसके सहित, सदन के सम्मुख पढ़ेगा तथा एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा। अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सदस्य को सुनने के उपरान्त, यह विनिश्चित करेंगे कि क्या शिकायत नियमित है।" तो इसके अनुसार आप पहले हमारा संक्षिप्त वक्तव्य सुन लें कि किस आधार पर सरकारी गजट जो कि पब्लिक डाकूमेंट है और उसमें गलत बात....

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप जरा सुन लें, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं। आप जरा बैठ जायं। जो डाकूमेंट सदन के सामने लाया गया है उसके अनुसार इस सम्बन्ध में कोई प्राइमाफेसी केस बनता ही नहीं और इसके बारे में जो प्रश्न आपने उठाया है वह उठता ही नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, आप की व्यवस्था चाहता हूं। हमारा कहना यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में नियम ६७ में साफ लिखा हुआ है कि जब कोई सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देगा तो आप उसका एक संक्षिप्त वक्तव्य सुनेंगे और उसको सुनने के बाद आप निर्णय करेंगे। आपने अभी श्री काशीनाथ जी की बात को नहीं सुना है, तो आपने बिना उनके संक्षिप्त वक्तव्य के कैसे व्यवस्था देने की कृपा की ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ६४ में यह है कि जब आज्ञा हो तभी सुनने की बात उठेगी। और जब प्राइमाफेसी केस नहीं है तो कैसे यह अवहेलना की बात मानी जा सकती है। ६७ से पहले तो यह ६४ नियम है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

आप देखें कि ग्रहीता की शर्तें क्या हैं। नियम ६७ में देखा जाय, उसमें है कि कोई विशेषाधिकार अगर प्रस्तुत होता है तो उसकी ग्रहीता की शर्तों को पढ़ने के बाद आप पहले सुन लेंगे और उसके बाद आप निश्चित करेंगे कि उसे लिया जाय या न लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

जब नोटिस में ही नहीं आता और सूचना ही ठीक नहीं है चूंकि इस सूचना में जो विषय उठाया गया है उसका सदन से कोई ताल्लुक नहीं है अतः कोई अवहेलना का प्रश्न नहीं होता है। इसलिये इस की सूचना लेने से मैं इंकार करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, वह आप जरा सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं इस पर आप की जरा सफाई चाहता हूं। सफाई भी हो सकती है या नहीं ? व्यवस्था के प्रश्न पर क्या कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो सकता ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, व्यवस्था के प्रश्न पर क्लेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

यह पब्लिक रिकर्ड है, पब्लिक डाकूमेंट है और उसका फ्रैबिकेशन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--
लेकिन सदन से उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--
इस सदन से बिलकुल उसका ताल्लुक है ।

श्री उपाध्यक्ष--
नहीं, आप बैठ जायं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--
आप तो हमारा प्रोपोजीशन सुनते नहीं तो कैसे मालूम होगा कि सदन से ताल्लुक है ?

श्री उपाध्यक्ष--
नहीं, आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--
तो क्या आप क्लेरिफिकेशन भी नहीं सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--
जी नहीं । आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--
अच्छा, नहीं सुनेंगे तो न सुनिये, उसमें किया क्या जा सकता है फिर ।

श्री काशीनाथ मिश्र--
मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है उसे तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--
मैं नियमावली के नियम ६७ का अन्तिम प्रतिबन्ध पढ़ता हूं, सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
प्वाइंट आफ आर्डर किस बात पर है । नियम ६४ को देखिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--
मेरा प्वाइंट आफ आर्डर पहले सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
अब उस पर रूलिंग हो चुकी है और उसके बारे में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--
उसके बारे में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--
माननीय काशीनाथ जी, प्वाइंट आफ आर्डर पर मैंने एक रूलिंग दे दी । अब उस सम्बन्ध में कोई दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं लिया जा सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--
तो आप मेरा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--
जी नहीं, अब उस रूलिंग के बाद सुनने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--
तो मैं अब आपकी इस रूलिंग के विरोध में ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करता हूं ।

(श्री काशीनाथ मिश्र ने सदन का परित्याग किया ।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)––

श्रीमन्, कल मैंने अपनी लोकप्रिय सरकार का ध्यान पूर्वी जनपदों की ओर आकर्षित किया था जहां की जनता सिसक-सिसक कर रोती है, जहां का मनुष्य जीवन को अभिशाप और मृत्यु को वरदान समझता है। यह कल मैंने पूर्वी जनपदों की दशा का वर्णन करते हुये बताया था। हमारे एकाध माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह तो वहां का अतिरंजित चित्रण है, दो आने से चार आने मजदूरी की ही बात सत्य है। वास्तव में यह अतिरंजित वर्णन नहीं है। पूर्वी जनपदों और विशेषकर गाजीपुर जनपद में इतनी गरीबी छायी हुई है कि वहां के लोगों का जीवन निर्वाह अब भी चोटे पर और गोबरहे पर होता है। इसका प्रमाण यह है कि प्लानिंग कमीशन के सदस्य हमारे जनपद में गये थे और वहां गाजीपुर के सादियाबाद क्षेत्र के उन उपेक्षित क्षेत्रों को उन्होंने देखा था जहां निर्धनता अपना पग तोड़कर बैठी हुई है। उस समय लोकप्रिय पत्रों, "नवजीवन," "नेशनल हेरल्ड" और "संसार" के प्रतिनिधि भी उनके साथ थे और "आज" का प्रतिनिधि तो प्लानिंग कमीशन के साथ पूरे निरीक्षण काल में था और जहां जहां गांवों में प्लानिंग कमीशन के सदस्य गये वहां वहां वह भी साथ था। उन लोगों ने आकस्मिक निरीक्षण, बिना सूचना के भी किया और गांवों में लोग घुस गये और वहां की परिस्थिति के बारे में उन्होंने पूछा तो वहां के लोगों ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हम लोगों को तो २ आने से ४ आने तक मजदूरी मिलती है और हम लोग अपना जीवन चोटे पर बिताते हैं। आज दिन भी निम्नकोटि की बस्तियों में आप चले जाइये तो वहां आपको उस गोबरहे के दर्शन होंगे जो उच्छिष्ट होता है और जिसको मनुष्य क्या पशु भी खाने से घृणा करेंगे।

इसका कारण यह है कि उन जनपदों में यातायात का कोई साधन नहीं है। यातायात के साधनों की कमी से उद्योग धंधों में कमी आयी है। औषलियों की भी कमी है उसका काफी अभाव है। यदि कोई व्यक्ति वहां बीमार पड़ जाता है तो वह बिना उपचार के घर पर ही मर जाता है, उसके अस्पताल तक जाने के लिये कोई साधन नहीं है। यदि यातायात के साधन होते तो कम से कम वहां के गरीब इक्के या रिक्शे चलाकर या छोटे मोटे उद्योग धंधे करके अपना जीवन निर्वाह कर लेते यातायात साधनों का तो स्वाद प्लानिंग कमीशन को भी मिला था जब वह कच्ची सड़कों से गुजर रहे थे तो उनकी मोटर एक पुल के ऊपर गिरते गिरते बची। इस तरह प्लानिंग कमीशन के सदस्यों ने अपनी आंख से उस जनपद की धूलभरी सड़कों का निरीक्षण किया। यदि यह कहा जाय कि वहां निर्धनता है तो अतिशयोक्ति न होगी। जिन समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने लिखा था कि यह बात कुछ अतिरंजित मालूम होती है, जब स्वयं उन्होंने उस क्षेत्र में प्लानिंग कमीशन के साथ जा कर देखा तो उन्होंने कहा वास्तव में गाजीपुर जिले में निर्धनता है और दो चार आने मजदूरी मिलती है, आज भी वहां स्वराज्य का कोई चिन्ह नहीं है। प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य ने कहा था स्वराज्य मिले १५ साल हो गये, लेकिन गाजीपुर में कोई चिन्ह उसका नहीं दिखाई देता। गाजीपुर के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कोई व्यवस्था नहीं की। मुझे तो यही कहना पड़ता है कि––

कामना यही कि स्वर्ग-सा मधुर प्रदेश हो, खिलें प्रसून प्रेम के कहीं न क्लेश लेश हो।
सुखी सकल समाज हो, कहीं न द्वेष शेष हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश का, विवेक में गणेश हो।

इतना ही नहीं बल्कि:––

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर के पहले,
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।

---

*२० फरवरी, १९६३ की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत उम्मीदों के साथ इस बजट का इंतजार कर रहा था, चूंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हमारे वित्त मंत्री जी और विकास मंत्री दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे इसलिये कि एक नये प्रकार का बजट लाया जाय जिसमें इस समय की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखा जाय । चीन के आक्रमण के बाद जो संकट देश में पैदा हुआ है उसकी बिना पर जो नई जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई है उनको मद्देनजर रखा जाय । मामूली पुराने खर्चों में कुछ कमी की जाय ताकि साधन हाथ में आयें. जनता में यह विश्वास पैदा किया जाय कि संकटकाल में सरकार और जनता मिल कर देश की रक्षा करेगी और जनता के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा होगी । मैं समझता था अब की नया बजट आयेगा और उसमें झलक होगी उन जिम्मेदारियों की, उस संकट की, जो आज देश के सामने है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद दो महारथियों के जुटे रहने पर, दो दो महीने तक बजट, ट्रेडीशनल बजट ही सामने आया । मैं बोलना चाहता था मुझे मालूम नहीं होता था क्या बोलूं जो पिछले साल बजट था वही इस साल भी है । ७ करोड़ रुपया एमरजेंसी के लिये रख दिया गया, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स में कोई फर्क नहीं है । अगर मुझसे पूछा जाय कि क्यों बजट का स्वरूप नहीं बदला बावजूद हमारे काबिल दोस्तों की कोशिशों के, तो मेरा जवाब होगा कि ब्यूरोक्रेसी ने बजट को बदलने नहीं दिया और इस माने में यह एक ट्रेडीशनल ब्यूरोक्रेटिक बजट है । मैं जरूर बजट की आलोचना करूंगा और एक दोस्त की हैसियत से करूंगा कि मैं जब कहता हूं कि दोस्त की हैसियत से, तो मेरे भाई इधर मजा लेते हैं । रामसुन्दर जी हैं नहीं । हां, मैं दोस्त हूं, मैं आपका भी दोस्त हूं और चाहता हूं कि इस संकट के समय सब एक दूसरे के बनें और जो आलोचना हो वह ऐसी हो जिससे नाजायज तरीके से ऐसी बातें न कही जायं जिससे देश के अन्दर अराजकता फैले, डिमोरलाइजेशन हो । अगर संकट दरअसल संकट है तो कुछ तब्दीली आनी चाहिये । मैं बुनियादी तब्दीली की बात नहीं करता, लेकिन कुछ तब्दीली अयां होनी चाहिये । अगर वह तब्दीली नजर नहीं आती तो मैं दोस्त की हैसियत से आलोचना करूंगा ।

मैं इसको नौकरशाही बजट इसलिये कहता हूं क्योंकि नौकरशाहियत का एक रुझान होता है । अगर उसमें जरा भी छेड़छाड़ की जाय तो सारी इमारत गिर जाय । मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज की तरफ से बड़ा भयंकर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वहीं की वहीं गाड़ी रही । मैं समझता हूं कि आज के बजट में नुमायां तौर पर दो, तीन चीजें आनी चाहिये थीं । पहली चीज तो यह कि डिफेंस पोटेन्शल मजबूत होना चाहिये । वित्त मंत्री जी ने सही तौर पर कहा कि हमारी कोशिश है कि डिफेंस पोटेन्शल मजबूत हो । नेशनल डिफेंस कौंसिल डिफेंस पोटेन्शल की मजबूती को डिफाइन करती है । कल के अखबार में देखिये । मजबूत होने के माने हैं कि हम अपनी बेसिक प्लानिंग को मजबूत करें और खासतौर पर औद्योगीकरण को मजबूत करें और उसमें भी खासतौर पर उन उद्योगों को जिनका सम्बन्ध सुरक्षा से है । मैं समझता हूं इस बजट में उस चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया । डिफेंस पोटेशन्स की बात की गयी, ७ करोड़ रुपया रखा गया । किसके लिये ? एक रक्षा दल होगा, पुलिस बढ़ेगी, सड़कें बनेंगी, । पुल बनेंगे मैं मानता हूं, यह सब होना चाहिये, लेकिन इसके अलावा अगर संकट का सामना हमको करना है तो कुछ और चीजें होनी चाहिये । यह डिफेंस पोटेशन्स अंडरस्टैन्डिग सीमित है । इसके अलावा मेरी कसौटी यह है कि अगले साल में हमारा औद्योगीकरण और खासतौर पर ऐसे उद्योग जिनका ताल्लुक डिफेंस से है वह किस हद तक बढ़े और उसमें क्या आपने प्लानिंग की । मैं उसमें कमजोरी देखता हूं और उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, क्योंकि मुमकिन है कि इसी रुपये में आप कुछ इधर-उधर कर सकें और मुमकिन है कि एक दोस्त की आलोचना को मद्देनजर रखते हुये अगले साल आप कुछ परिवर्तन करें ।

औद्योगीकरण को लीजिये, पिछले साल रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट में औद्योगीकरण के लिये ८ करोड़ ७० लाख रुपया था। अगर हमारी आंखें गलत हों तो हम तो अमेच्योर हैं और इतना पेचीदा बजट होता है कि समझ में नहीं आता। लेकिन ८ करोड़ से बढ़ा कर १० करोड़ कर दिया, मैं इसको बिलकुल नाकाफी समझता हूं। हमारी थर्ड प्लान के आब्जेक्ट्स और टारगेट्स में यह है कि औद्योगीकरण इतनी तेजी से बढ़े कि प्लान का २० प्रतिशत रुपया उद्योग की तरफ जाय, लेकिन ८ करोड़ से १० करोड़ हो जाना काफी नहीं है और उसमें से भी लगभग ८ करोड़ उन उद्योगों से आपको मिलता है और इन्कम साइड में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरे बजट में जो अधिक प्राविजन करते हैं वह २/३ करोड़ के करीब करीब है। कैपीटल एक्सपेंडीचर ४ करोड़ के करीब रखा है। वह बुनियादी उद्योगों पर नहीं हैं, बल्कि कोआपरेटिव और बैंकिंग क्रेडिट के लिये है। मैं इस बात को एक दफा नहीं, हजार बार कहूंगा कि यू० पी० का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है जब तक मजबूती के साथ औद्योगीकरण को नहीं अपनायेंगे। यू० पी० औद्योगीकरण में सब से पिछड़ा हुआ है। इसका कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं जानता, लेकिन जाहिर है कि सरकार की नीति इस ओर नहीं जाती है। मैंने पिछली बार बजट पर बोलते हुये कहा था कि सबसे कम कैपिटल आउट ले उद्योगों पर है और सब से कम पर कैपिटा इन्कम इस प्रदेश की है, सब से कमजोर ढांचा कम्पनियों का यू० पी० में है, दस हजार से ज्यादा टैक्स देने वाली कम्पनियां यहां पर बहुत कम हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुये अगर संकट के समय में भी औद्योगीकरण का ड्राइव नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि चेतना में कमी है। मैं उसको पैदा करना चाहता हूं। आज जो पुलिस और पचीसों दूसरे विभागों पर जो रुपया खर्च कर रहे हैं क्यों न उस में से बचाकर नये उद्योगों को मजबूती के साथ बनाया जाय। हमारे उद्योग मंत्री जी ने बयान दिया था कि लगभग ४५ फीसदी रुपया जो छोटे और बीच के उद्योगों के लिये दिया गया है वह मिसयूटिलाइज हुआ है। अभी पूरे जिलों की जांच नहीं हुई है। थोड़े ही जिलों की जांच हुई है। बड़े सरमायेदारों को जो रुपया दिया गया है पता नहीं वह कहां इस्तेमाल हो रहा है।

यह बात मैंने पिछली बार कही थी कि पार्लियामेंट में लोगों को यह शिकायत यू० पी० से है कि यहां की औद्योगीकरण की योजनायें बहुत कमजोर होती हैं और ब्लूप्रिंट्स अच्छे नहीं होते, इसलिये दूसरे सूबे झपटते हैं और केन्द्रीय सरकार से रुपये ले लेते हैं। हमारे यहां केवल चुर्क सीमेंट फैक्टरी और इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी हैं और कुछ फैक्टरियां ऐन्टी बयोटिक्स वगैरह की हैं जो विदेशी मदद से हो रही हैं, और कोई भी नहीं है। इनका भी पता नहीं चलने में कितने साल लग जायं यह संकट का जमाना है और हम वार सिच्युयेशन से गुजरे हैं, क्यों न एक कमीशन मुकर्रर किया जाय जो हमारे साधनों को जुटाये और हमारी पर कैपिटा इन्कम को बढ़ाये। सारे प्रदेशों में काफी पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है जबकि हमारे यहां कुल ३ फीसदी बढ़ी है। इसलिये हमारे यहां औद्योगीकरण और पैदावार बढ़नी चाहिये। सिर्फ आपके सिपाही और रक्षा दल प्रदेश की रक्षा नहीं कर पायेंगे। यू०पी० की कृषि की पैदावार अपनी जगह पर फी एकड़ कम हुई है।

एग्रीकल्चर पर जो रुपया है वह आप देखें कि १९६२-६३ में ४ करोड़ ९६ लाख है, १९६३-६४ में ६ करोड़ १० लाख। २०० करोड़ के बजट में इतना बड़ा जहां कृषि समाज है उसमें ४ करोड़ से ६ करोड़ होना और कैपिटल आउट ले १ करोड़ ८१ लाख है, लगभग ४ परसेंट बजट का होता है। यह लम्बी चौड़ी बातें डिफेंस पोटेंशल की कहना लफ्फाजी है। यह है बुनियादी बात।

दूसरा प्रश्न इमर्जेन्सी के पीरियड में होता है टाइटेनिंग आफ दि बेल्ट की मुझे आशा थी कि टाइटेनिंग आफ दि बेल्ट होगा। १ करोड़ २५ लाख सिर्फ निकला। यह पूरे बजट का आधा परसेंट भी नहीं आता। और निकाला कौन गया बेचारा सूखा हुआ ला कमीशन बैठा था, उसको निकाला गया, एक मुरझाया हुआ ट्रेनिंग कालेज था। कुल ४८० अफसर या चपरासी चले गये। यह बातें माफ कीजिये, जंचती नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस जमाने में डे-टु-डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी करना मुमकिन नहीं

[श्री जेड० ए० अहमद]

है। माफ कीजिये, अगर डे-टु-डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी नहीं करेंगे तो यह ब्युरोक्रेसी आपकी गवर्नमेन्ट को ले बैठेगी। मेरा दावा है, एक कमीशन मुकर्रर हो, जितना बजट है उसका आधा बजट सरकारी पदों पर खर्च होता है। मैं झूठा हूं तो आप मुझे बुरा कहिये। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कमीशन बैठाया जाय। आधा बजट उधर जाता है, इसके आंकड़े नहीं दिखाये जाते हैं। अगर एक वेलफेयर स्टेट में बजट का ५० परसेंट ब्युरोक्रेसी पर खर्च होता है और ५० परसेंट बाकी चीजों पर, तो वेलफेयर स्टेट के लीडरों को देखना चाहिये। आज ब्युरोक्रेसी की हालत यह है कि हाइली इनएफीशेंट ब्युरोक्रेसी है। आफिसर्स की संख्या जैसे ही बढ़ती जाती है, वैसे ही इनइफीशेंसी भी बढ़ती है। एक विशश सर्किल है। कोई टेस्ट नहीं इफीशियेंसी का। कोई डिपार्टमेन्टल चेक अप नहीं है। आडिट रिपोर्ट को देखा जाय करोड़ों रुपया चला जाता है। इनफ्रक्टुअल ऐक्सपेंडीचर पर, लेकिन क्या कोई कमेटी बिठायी जाती है? पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, एसटीमेट्स कमेटी में एक्सप्लेनेशंस आते हैं यह हो गया, वह हो गया, लेकिन क्या किसी के ऊपर कोई चेक है? किसी अफसर को सजा दी गयी? कहा जाता है कि एक्सप्लेनेशन मांग लिया गया, कोई रिटायर हो गया, कोई बाहर चला गया, वह हमारी पकड़ में नहीं है। यह बातें हैं। वेलफेयर स्टेट को जागना पड़ेगा, अगर वह नहीं जागती तो यही नौकरशाही चाहे आपकी कितनी वफादार बनी रहे, लेकिन एक वक्त आयेगा कि यह नौकरशाही आपको ले डूबेगी।

अब मैं वेस्टेज की दो तीन मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् १९६१-६२ की आडिट रिपोर्ट को आप लीजिए। ६० हजार से ज्यादा आबजेक्शन्स आडिट रिपोर्ट में ऐसे थे जिसमें कि ५४ करोड़ रुपये इन्वाल्व थे जो, मार्च, १९६१ तक तय नहीं हो पाये। हमारी कमेटी लिखती रही, बताइए, क्या कारण हैं। यही जवाब आता रहा—मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। इसके आगे चलिए। १९६१-६२ की रिपोर्ट यह कहती है कि २.३५ करोड़ रुपया सरकार का जाया हुआ इम्बोलिजमेंट, इन्फ्रक्चुअस एक्सपेंडीचर, अवायडेबिल एक्सपेंडीचर और नान-पेमेंट आफड्यूज में। फिर नौकरशाही का निकम्मापन और मैं आपसे कहता हूं कि इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में १८५२ ट्यूबवेल्स का आर्डर दिया जाता है जिसमें नेट लास १३.८२ करोड़ रुपया आता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १,५०० ट्यूबवेस्स का आर्डर दिया जाता है। इसके अन्दर लास आता है १.७७ करोड़। (व्यवधान) अगर मैं गलत होऊं तो कहिए। हो सकता है कोई एक फिगर गलत हो, लेकिन यह एक प्राबलम है, एक बुनियादी प्राबलम अपनी जगह पर है और मौजूदा ब्यूरोक्रेसी को टाइटेन करने की जरूरत है। माननीय वित्त मन्त्री जी आर्ग्यूमेंट देंगे कि अनएम्प्लायमेंट है। मैं भी नहीं चाहता कि अनएम्प्लायमेंट हो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट अनएम्प्लायमेंट को दूर करने की एजेंसी बने। आखिर यह विशश सर्किल कहां जाकर खत्म होगा? हम अनएम्प्लायमेंट नहीं चाहते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूलिंग करने की जरूरत है। तो मैंने वेस्टेज की तरफ इशारा किया, एकोनामी की तरफ इशारा किया। जाहिर है कि अगर एकोनामी नहीं होती तो रिसोर्सेज का प्राबलम, साधनों की समस्या उठ खड़ी होती है। या तो एकोनामी कीजिए या साधन पैदा कीजिए। जहां साधन हैं उनको पकड़िए, जो लुटेरा तबका है उसको दबाइए या फिर चलिए उसी किसान की तरफ, वही अन्नदाता है, वही देगा। लेकिन अब वह हो नहीं सकता। आप जानते हैं क्या उसकी आर्थिक सीमायें हैं, आप जानते हैं क्या उसकी राजनीतिक सीमायें हैं? और इसीलिए आप इस बजट के अन्दर तय नहीं कर पाये कि कहां टैक्स लगाया जाय। इन्डाइरेक्ट टैक्स यू० पी० में बहुत काफी है, कहां तक इन्डाइरेक्ट टैक्स बढ़ाइएगा? आज यू० पी० सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वह कहे कि किस चीज पर टैक्स वह बढ़ायेगी और मैं समझता हूं इसीलिए टैक्स आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। पिछले साल जो टैक्स बढ़ाया था और जो साधन आपके पास हैं उनका ठीक से इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त सरकार के ड्यूज लगभग १ करोड़ रुपये के हैं अगर मैं गलत होऊं तो ठीक कर दीजिएगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । लाउड स्पीकर में डाक्टर साहब की आवाज तो आ ही रही है, एक दूसरी आवाज और सुनायी पड़ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी तलाश करने के लिए आदमी भेजा है ।

श्री जेड० ए० अहमद—

१९६१-६२ तक १८ करोड़ ड्यूज थे जिसमें ९.६४ करोड़ सेल्स टैक्स के ड्यूज थे १९५९ से लेकर १९६२ तक के तीन सालों के, जब कि एक साल की एवरेज इनकम ११.५४ करोड़ है सेल्स टैक्स की । इस तरह एक साल की एवरेज इनकम का ८३.५ परसेंट बकाया है । फिर फारेस्ट डिपार्टमेंट का ३.७५ करोड़ बकाया है । इस डिपार्टमेंट से सरकार को जो आमदनी होती है उसका इतना बकाया है । इस सरकार को साल में जो आमदनी होती है उसका इतना बड़ा हिस्सा बकाया रह जाता है । अब आप देखिये कि लैंड रेवेन्यू का कितना एरियर है। सन् १९६१-६२ में ३.३३ करोड़ । सेल्स टैक्स का ९ करोड़ ६४ लाख । लैंड रेवेन्यू से सरकार को साल में २१ करोड़ ४२ लाख की आमदनी होती है और उसका ३ करोड़ ३३ लाख बाकी रह जाता है । इसका मतलब यह है कि सरकार का ड्यूज १५ परसेन्ट के ऊपर है । यह हकीकत है आपके आफिसर क्या कर रहे हैं ? इससे यह पता चलता है कि आपकी सेल्स टैक्स की मशीनरी कितनी करेप्ट है जिसकी वजह से वसूली नहीं होती है । जितना रुपया यह पड़ा हुआ है इसको वसूल करने की कोशिश नहीं की जाती है । इसमें ईमानदारी की जरूरत है । इसी तरह से ६१-६२ में इर्रीगेशन का रुपया आता है .६० करोड़ सालाना और सरकार का जो ड्यू रह जाता है वह ६.५ लाख । जो ऊपर का तबका है उससे कोई चीज वसूल नहीं होती है । यह एक बड़ा प्राबलम आपके सामने है । मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति को भी आर्थिक परिस्थिति के साथ साथ देखना चाहिये क्यों कि हम राजनीतिक लोग हैं, दूकानदार नहीं हैं । हमको राजनीतिक परिस्थिति को भी सामने रखना चाहिये । अगले साल गरीबों पर ही टैक्स नहीं लगाना चाहिये । अगर टैक्स लगाना है तो ऊपर के तबके पर लगायें । सरकार का बहुत सा बकाया है उसको ही सरकार वसूल कर ले, १० करोड़ वसूल करले या ५ करोड़ ही वसूल कर ले तो उसका काम चल जायगा और काफी होगा । इस यू० पी० के अन्दर एक ऐसा संकट उपस्थित हो गया है कि जब आपको रिसोर्सेज के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा । मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी बहुत दफा परेशान होते हैं कि कहां से निकालें और कैसे निकालें । मगर रिसोर्सेज का प्राबलेम आपको तय करना पड़ेगा और बुनियादी तौर पर तय करना पड़ेगा और आपको उन वर्गों के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने इस संकट के वक्त में देश के लिये कुछ नहीं दिया । किसी ने ५ हजार और किसी ने १० हजार दे दिया, लेकिन कोई खास उन्होंने मदद नहीं की । निजाम हैदराबाद ने कह दिया कि मैं तो गरीब हो गया और उनके पास ५, ५ रुपये के मनिआर्डर लोगों ने भेजना शुरू कर दिया । आप इसको देखें कि कितना सोना करीब १० लाख ग्राम के गरीबों की तरफ से आया है और सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने दिया लेकिन कितना सोना आपको उन लोगों से मिला है जिनके पास सोना भरा पड़ा है और कितने ने सरकार की मदद की ? यह नीति का सवाल है । आपकी शब्दावली पूरे भाषण में उनके प्रति इतनी नरम है कि . . .

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मेरी आदत है, मैं क्या करूं ।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैं नरम भाषा पसन्द करता हूं, लेकिन नरम भाषा के बाद गरम काम भी होना चाहिये । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माने यह हैं कि आप कहते हैं नरम बातें लेकिन काम करेंगे सख्ती से । मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि अगले साल साधन जुटाने का जहां तक

[श्री जेड० ए० अहमद]

सवाल है वह गरीबों से नहीं होगा बल्कि उस तबके से होगा जिन्होंने राष्ट्र के लिये सैक्रिफाइस नहीं की है और गरीबों के ऊपर ही सारा बोझ डाला है।

अन्त में मैं दो-तीन बातें और अर्ज करना चाहता हूं। चूंकि यह बहस एक राजनैतिक बहस हो गई, मैं नहीं चाहता था कि यह राजनैतिक बहस हो लेकिन अब होगई तो एक राजनैतिक जानवर की हैसियत से मुझे भी अपनी राजनीति के बारे में कुछ कहना ही पड़ेगा। मेरे भाई जो अभी तक खामोशी से सुनते रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आगे भी जरा खामोशी से सुनते रहें। आज घड़ी घड़ी सवाल उठाया जाता है कि कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ मिल गये। जब कोई बात उठायी जाती तो कहा जाता है कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। कोई किसी से मिलता नहीं, न कोई किसी से शादी करता है। हम बुड्ढे हो गये हैं, अब क्या शादी करेंगे, (व्यवधान)। मैं तो अपनी बुढ़िया से ही संतुष्ट हूं। सवाल यह है कि रात दिन जमाना बदलता है। नयी राजनीतिक परिस्थितियां आती हैं और उनमें जिनके दिमाग बुनियादी सवालों पर एक दूसरे के नजदीक होते हैं, उनके रुख बदलते हैं, वे साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं। पुरानी दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं, नये ब्लाक पैदा होते हैं और मैं जरूर कहता हूं कि इस संकट में नेहरू सरकार की, केन्द्रीय सरकार की और उसके पीछे चलने वाली सरकारों की जो बुनियादी नीतियां रही हैं हम अपने को उनके ज्यादा नजदीक समझते हैं। अभी हमारे जनसंघ के दोस्त गरीबों की बहुत दुहाई दे रहे थे। हमारे राजा साहब ने भी कल कैपिटलिस्टों पर हमला किया कि वे कैपिटलिस्टों के साथ बंधे हुये हैं। मुझे हंसी आयी उनकी इस बात को सुन कर। मेरा तो यह विश्वास है कि आज जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी माउथपीस हैं हिन्दुस्तान के वैस्टेड इंटरेस्ट्स की। आज जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी वह बातें करती हैं कि जो उन नीतियों के खिलाफ हैं कि जिनको हमारे १०० साल के राष्ट्रीय आन्दोलन ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और हजारों वीरों बनाया है, जो नीतियां अमर हैं और एक क्षण के लिये भी नहीं मरेंगी। और जो जिन्दा रहेंगी क्योंकि हिन्दुस्तान जिन्दा रहेगा उसकी राष्ट्रीय परंपरा जिन्दा रहेगी। उन नीतियों पर जब वार होता है—मैं आप से अपील करता हूं कि सुन लीजिये, हम से खतरा है, हम गद्दार हैं, लेकिन फिर भी हमें सुन लीजिये। तो उसको हम बर-दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि आज सब से बड़ी नीति यह है कि हिन्दुस्तान एक देश है जो दुनिया में सितारे की तरह चमका है और उस के पीछे कुछ नीतियां हैं। खोखली बातों से वह नहीं चमका। हमने दुनिया को कहा कि हम साम्राज्यविरोधी हैं, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, हम शान्तिपक्ष के लिये खड़े हैं, भले ही कोई कुछ करे, लेकिन हमारी बुनियादी नीतियां अमर हैं। हमने कहा कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी को मानते हैं और समाजवादी लक्ष्य को सामने रख कर प्लानिंग के जरिये आगे बढ़ेंगे, और हमारे दोस्त अगर इस एक एक चीज का विरोध करें, कहें कि देश को मिलिटराइज कर दिया जाय, यहां चला जाय, वहां चला जाय, प्लानिंग छोड़ दी जाय, नान-एलाइनमेंट की पालिसी गलत है, तो हमारा आपका साथ कैसे रह सकता है? हमारी और आपकी जड़ें दूसरी दूसरी हैं। कल किसी नेता ने कहा था कि वेस्टर्न ब्लाक में हमें चला जाना चाहिये। हम कहां जा रहे हैं? और इन बातों को लेते हुये अगर पंडित नेहरू को ठोका जाता है, उन पर आक्रमण किया जाता है तो हर हिन्दुस्तानी का फर्ज है कि वह जवाहरलाल के साथ खड़ा रहे। यहां शादी का सवाल नहीं है। हिन्दुस्तान एक मोड़ पर खड़ा है, अभी कहीं पहुंचा नहीं है। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से और इधर के लोगों से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान या तो इधर जायगा या उधर जायगा, बीच में नहीं रह सकता। हिन्दुस्तान को अपनी राष्ट्रीय नीतियों को पकड़ कर, खड़े हो कर उनकी रक्षा करनी पड़ेगी या फिर उसे गिरते गिराते, लुढ़कते तबाह होते जाना पड़ेगा उस जगह पर जहां बहुत से देश चले गये, खत्म हो गये। नान-अलाइनमेंट की पालिसी का सवाल है, वह दिमागी कलाबाजी नहीं, अवसरवादी नहीं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपिल आफ लाइफ है एक आजाद मुल्क के लिये, जो आगे बढ़ना चाहता है और दुनियां के अन्दर चमकना चाहता

है। उसके साथ हिन्दुस्तान की इंटीग्रल लाइफ बंधी हुई है, जो अगर किसी ब्लाक के साथ चला गया तो उसके अन्दरूनी जीवन में हस्तक्षेप होगा और अन्दरूनी डिमाक्रैसी खत्म होकर डिक्टेटर-शिप कायम होगी।

जब स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के दोस्त गाली देते हैं तो उसके लिये हम तैयार हैं, हम बहुत बेशर्म हैं। हालांकि इससे पहले वह हमारे साथ बहुत दिन थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में चले गये। उनका वह वाम-पक्षी मोर्चा कहां गया? कौन उसमें वाम-पक्षी है, कौन नहीं है, समझ में नहीं आता। उसके बाद, मुझे अफसोस है कि मेरे पुराने दोस्त उग्रसेन जी जो कि बहुत जोशीले नौजवान हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कल मुझे उनकी स्पीच से अफसोस हुआ। वह अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन कहते कहते इतना ज्यादा समाजवाद कह गये कि हमारे स्वतंत्र पार्टी के भाइयों ने कहा कि अब तो हमारे लिये कुछ कहने को बचा नहीं। आज मैं खास तौर से उनकी तरफ ध्यान इसलिये देता हूं और उनकी इज्जत इसलिये करता हूं कि वह पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब समाजवादी रेस तो डबल है। जगजीवनराम ने जो कहा था कि हमें गोल्ड चाहिये, गन चाहिये और नेहरू चाहिये, यह जो उन्होंने कह दिया कि नेहरू चाहिये तो कितना बड़ा पाप किया। यह आलोचना थी, सोशलिस्ट पार्टी की आलोचना थी। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में सोशलिज्म की बुनियादें कांग्रेस के अन्दर, कांग्रेस को छोड़िये देश में अगर डाली है तो वह नेहरू ने डाली हैं (तालियां)। आज के सेटअप में सोशलिज्म के रूझानात की तरफ आज अगर कहीं से बल मिलता है तो वह नेहरू है। हालांकि मैं नेहरू की सरकार की नीतियों से बहुत कुछ इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन मुझे बताये कोई कि अगर आज नेहरू न हो तो कौन है उसकी जगह? हमें आज नेहरू चाहिये।

फिर मुझे ताज्जुब हुआ। उग्रसेन जी नहीं है, उन्होंने फरमाया कि नैशनल केडेट कोर वगैरह के लिये कहा गया कि लाखों आदमी भर्ती होंगे और उसके बाद जब भर्ती बुलाई गयी तो सिर्फ ६५ आदमी आये। इससे बात कुछ हट जाती है। मैं इसके मानी निकाल सकता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के नौजवानों की ट्रेनिंग बेकार, हमारे सारे प्रयत्न बेकार, जाओ वेस्टर्न ब्लाक में और अमेरिका और दूसरे मुल्कों से फौजें लेकर आओ, यहां तो कुछ नहीं है, अगर यह कहा जाय तो क्या नाजायज बात होगी? अगर आप इतने हल्के तरीके से कहते हैं कि लाखों आदमियों के बजाय इतने आदमी आये तो इसका प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ने वाला है? प्लानिंग गलत, उसमें एक नहीं १०१ कमजोरियां हैं, बुनियादी तौर पर वह बहुत पिछड़ा हुआ देश है सब कुछ है, लेकिन जायेगा तो प्लानिंग के रास्ते से ही?

गरीबों की बात दुबेजी करते हैं, लेकिन कहते हैं प्लानिग छोड़ो, कैपिटलिस्ट की बात करो और समाजवाद छोड़ो। दोनों बातें कांट्रैडिक्टरी हैं। गरीबों की बात करो, लेकिन प्लानिंग छोड़ कर और समाजवाद छोड़ कर और पब्लिक सेक्टर छोड़ कर यह क्या हुआ प्रतिक्रिया-वादी भी जनता की दुहाई देकर चलता है, हिटलर भी समाज में सोशलिज्म की बात लेकर आया था। मैं दरख्वास्त करूंगा समाजवादी भाइयों से कि आज हिन्दुस्तान एक चौराहे पर है, इस तरह की बातें कहने से कुछ वोट आपको भले ही मिल जायं.... (शोर, बहुत शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, बहुत शोर हो रहा है, यह ठीक नहीं है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है। डाक्टर साहब, अब आपका समय समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

श्री जेड० ए० अहमद--

इससे आप वोट भले ही ले लीजिये मगर समाज और राष्ट्र की जड़ों को आप उससे खोखला कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--

अभी माननीय ऊदल ने मुझे दूसरे दल का सदस्य कह दिया....

श्री उपाध्यक्ष--

उस वक्त इतना शोर हो रहा था कि मैंने उसको सुना नहीं।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह चाइनीज इस्पाइज हैं, यह देशद्रोही हैं, इनको खत्म करना चाहिये, इस पार्टी को खत्म करना चाहिये ...

(अत्यन्त शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत शोर मच रहा है,यह ठीक नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, जब डाक्टर अहमद साहब बोल रहे थे, १० मिनट तक बत्ती जलती रही और वह बोलते रहे ....

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत है। ४-५ मिनट जरूर जलती रही। एक दो मिनट का टाइम में सभी माननीय सदस्यों को दे देता हूं। (व्यवधान) आप लोग बैठ जाइये। यह ठीक नहीं है, बहुत शोर हो रहा है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

माननीय ऊदल ने श्री केशरीप्रसाद पांडेय को जनसंघी कहा है। उनको आप यह शब्द वापस लेने को कहें, वे जनसंघ पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं तो केवल आपकी आइ कैच करने के लिये खड़ा हुआ था, ऊदल जी ने मुझ जनसंघी कहा जब कि मैं समाजवादी संयुक्त दल का सदस्य हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराज जाइये। यह सब जानते हैं कि आप समाजवादी दल के सदस्य हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि आपके विचार ऐसे हैं जैसे जनसंघियों के होते हैं..... (अत्यन्त शोर)

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

आप मेरी बात सुनें। आप गलतबयानी किसी से नहीं करा सकते हैं। माननीय ऊदल जी ने गलत बयानी की है। आप अपने विचारों से उसका भाष्य नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष--

बीच में इन्टरप्ट करने के लिये किसी कांग्रेसी को कोई जनसंघी कहे तो वह जनसंघी हो नहीं जाता। इसके माने सिर्फ यह हैं कि जनसंघ जैसे विचारों के हैं। इसमें कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं है। (व्यवधान) जनसंघी कह देना कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या किसी को जनसंघी कहना कोई गाली मानी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि जनसंघी कहना कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री बलवानसिंह—

आपने यह व्यवस्था दी कि किसी भी शख्श को किसी दूसरी पार्टी का कह दिया जाय तो इसमें कोई गलती नहीं है। श्रीमन्, लेकिन वह चीज तथ्य के बिलकुल विपरीत है। आप माननीय ऊदल जी से उस लफ्ज को वापस लेने के लिये कहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी को जनसंघी कहना अनपार्लियामेंटरी नहीं है। मैंने तो केवल उसका मतलब ही साफ किया। इसलिये उसमें कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं या बाहर चले जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आप मेरा निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। आप कृपा करके बैठ जायं। अनुशासन में रहना ही अच्छी बात है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जांय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के बाद नहीं। आप बैठ जायं या बाहर जायं। बैठ कर आप उठें नहीं।

श्री बलवानसिंह—

अगर, आप उन शब्दों को श्री ऊदल से वापस नहीं करवाते हैं तो उसके विरोध में हम लोग २ मिनट के लिये सदन से बाहर जाते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि जरा सी बात के लिये सदन में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया और कुछ सदस्यों को दुख हुआ। ऐसे वातावरण से संसदीय पद्धति को क्या हानि होती है, यह मैं स्वयं समझ सकता हूं क्योंकि ४–५ मर्तबा मुझे उठना पड़ा। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के वातावरण में कुछ मुलामियत आये। मैं जेड० ए० अहमद साहब को बधाई देता हूं और उनके विपरीत विचार रखने वाली पार्टी के नेता श्री भानुप्रताप जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपने विचार रखे और सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की। लेकिन साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां उन्होंने कोशिश की ऊंचा उठने की, वहां जब अपनी पार्टी के प्वायंट आफ व्यू पर आये तो उन्होंने जिस चीज को कह कर शुरू किया था उसी चीज के ऊपर खतम कर दिया। मैं बड़ी नम्रता के साथ विरोधी पक्ष के भाइयों से कहूंगा कि अभी २ मिनट का जो नजारा हुआ उसने यह साबित कर दिया कि आज कांग्रेस सरकार और पंडित नेहरू की ही ऐसी ताकत है जो डेमोक्रेसी को इस मुल्क में चला सकती है और अगर कांग्रेस सरकार इस देश में न होगी तो प्रजातंत्र इस देश में नहीं चल सकेगा। तानाशाही चाहे जिस किस्म की होगी, लेकिन उससे प्रजातंत्र नहीं चलता। तानाशाही प्रजातंत्र में मेल खा नहीं सकती, फिर प्रजातंत्र की बात करें और मन में कुछ दूसरी चीज हो। चाहे कोई किसी भी पार्टी का आदमी हो, मुझे इस बात का विश्वास है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि भाषा व विचारों से भी तानाशाही को हटाना पड़ेगा तभी प्रजातंत्र सफल हो सकता है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

जिस चीज से वातावरण पैदा होता है, आप कांग्रेस की आलोचना कीजिये, सरकार की आलोचना कीजिये, पंडित नेहरू की आलोचना कीजिये, इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन उस आलोचना से अपनी पार्टी का कोई मकसद पूरा करना हो, अपना कोई मतलब निकालना हो, कोई नीति या कोई योजना इस तरह की रखनी हो जिससें सरकार के कामों पर पर्दा पड़े, असलियत जनता के सामने न आवे, तो उससें देश का भला नहीं होने वाला है और न उत्तर प्रदेश का ही भला होने वाला है ।

आज जो हमारा बजट है, चाहे इसका जो नाम दीजिये, मैं अर्ज करूंगा कि किसी भी देश का बजट उस देश की आर्थिक व सामाजिक दशा को देखने का एक दर्पण होता है । जिस साल जैसी परिस्थिति होती है, जैसी विशेष परिस्थिति होती है या जो चीज होती है, बजट में उसका प्रतिबिम्ब होता है । इस तरह सें मैं कहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश का बजट सुरक्षा अभिमुखी है । डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने जहां और बहुत सी बातें कहीं वहां अन्त तक अपनी पार्टी की बात ही उनके दिमाग में छायी रही । मैं मानता हूं कि कम्युनिस्ट में भी बड़े भले आदमी हैं और डाक्टर साहब भी उन्हीं में से हैं जिनकी गिनती देशभक्तों में हो सकती है, लेकिन उसी कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे देशभक्त हैं तथा उनकी हमदर्दी चीन के साथ नहीं है । डाक्टर साहब का कहना था कि यहां प्रजातंत्र नहीं है बल्कि यहां ब्यूरोक्रेसी शासन चला रही है । मैं आपको बतला दूं कि चाहे जिस पार्टी के भी माननीय सदस्य बोले, उनमें ज्यादातर माननीय सदस्यों ने आल इंडिया पिक्चर को सामने रख कर, और सारे देश के बजट को सामने रख कर ही हमारी सरकार का क्रीटिसिज्म किया । बहस के बीच में नेहरू जी को लाया गया, हिन्दुस्तान की परिस्थितियों को लाया गया, नान एलाइनमेंट पालिसी को लाया गया और इस तरह से सारी चीजें आयीं जो उनके दिमाग पर छायी नहीं । वे ऐसी चीजें थीं जिनको पार्लियामेंट में उठाना चाहिये था और जिनका जवाब पार्लियामेंट को देना चाहिये था । फिर भी चूंकि वे सवाल उठाये गये हैं इसलिये उनका जवाब भी थोड़ा बहुत जरूरी होता है ।

मैं कहता हूं कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब, जिनकी में कद्र करता हुं, आज से नहीं बल्कि जब वह कांग्रेस में थे, पार्टी छोड़ने की बात तो अलग रही, लेकिन उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत खराबी है । मैं स्वयं इसे महसूस करता हूं, काम करता हूं और जानता हूं कि कुछ अड़चने होती हैं, लेकिन में विश्वास दिलाता हूं कि आज पंडित नेहरू जिस तरह से इस देश का शासन चला रहे हैं और जो उन के सच्चे भक्त हैं और जो यहां भी सरकार चला रहे हैं उनका उन पर पूरा विश्वास है, जो बृटिश साम्राज्यवाद के सामने नहीं झुके और जो बड़े से बड़े किसी साम्प्रदायवाद के सामने नहीं झुके उन के सामने यह ब्यूरोक्रेसी कोई चीज नहीं है, उसके आगे कभी भी हम नहीं झुक सकते । आप किन किन इशूज को आज सामने लाना चाहते हैं ? आज क्या समय देश के सामने है, जो सुरक्षा का मूल प्रश्न हमारे सामने है उसी से ओत प्रोत बजट हमारे सामने आना चाहिये था और वह लाया गया है । क्या आज इस इशू को उठाने का समय है कि केपिटलिस्ट्स को खत्म किया जाय और क्या केवल यही इशू आज सामने है कि ब्यूरोक्रेसीं को कैसे खत्म करें या कि आज हमारे सामने एक फौरी इशू यह है कि चीन जैसे दुश्मन ने जो हम पर हमला किया है उसका कैसे मुकाबला किया जाय ? अगर इस पैराये (पैमाने) में आप इस बजट को नापेंगे और देखेंगे तो आप कहेंगे कि यह एक अच्छा बजट है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ समझने में फर्क हो सकता है उसको ठीक करने की और समझने की बात हो सकती है । यह बजट इसी दृष्टिकोण सें बनाया गया है बाकी इस में कमियां हो सकती हैं, हमारे वित्त मंत्री जी कोई भी मंत्री जी इस की पूर्णता का दावा नहीं करते । हमारे वित्त मंत्री जी और विकास मंत्री जी बराबर दो तीन मास सें कोशिश करते रहे कि किस तरह से अन्य खर्च में कमी करें और बजट में सुरक्षा सें संबंधित कामों को कैसे आगे बढ़ायें और उसके लिये ज्यादा पैसा रखें । लेकिन कम से कम जिस चेतना सें ओत-प्रोत होकर उन्होंने यह सब

किया है उसकी थोड़ी बहुत दाद दें। जो बात ब्यूरोक्रेसी और वेस्टेज को रोकने की कही गई वह हम सब चाहते हैं। हम सब को वेस्टेज बुरा लगता है और एक क्षण भी कोई वेस्टेज पसन्द नहीं कर सकता और उसको दूर करने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम ब्यूरोक्रेसी को सब को ठीक करना चाहते हैं।

जहां तक टैक्स लगाने की गरीबों के संबंध में बात कही गई, अभी ६ मास हुये आपने एक बिल के द्वारा टैक्स लगाने की बात यहां मंजूर की थी उसका भार करीब करीब गरीबों पर ही पड़ता है। हम ने उसमें ८ एकड़ से नीचे वालों को एग्जेम्ट कर दिया, आप सब उस पर राजी हुये क्योंकि एक विशेष परिस्थिति हमारे सामने थी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह परिस्थिति कायम रही और यह चीन का आक्रमण जारी रहा और जैसें यह कोल्डवार चल रही है और आजअगर दुनिया में कोई हिन्दुस्तान का दुश्मन है तो वह चीन है, वह हमारा एनिमी नंबर १ है और अगर उस के मुकाबले के लिये यहां पर टेक्सेज लगाने की जरूरत पड़ेगी और चाहे हम सारे पूंजीपतियों का धन क्यों न छीन लें जब तक सारा देश अपने रिसोर्सेज को नहीं जुटायेगा हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चीन की आज २५ लाख फौज है और १ करोड़ २५ लाख की सेकिन्ड लाइन आफ डिफेंस है। चीन के आदर्श की बात करने वाले उन्हीं आदर्शों पर जरा चीन को देखें। २६ जनवरी के नेशनल हेराल्ड में वहां की नेशनल इनकम के बारे में दिया हुआ है कि चीन की पर केपिटा इन्कम एशिया में और दुनिया के सब देशों में सब से कम है। उनकी पर कैपिटा इन्कम ५७–५८ में ६३ यान थी और ५९–६० में वह रूरल इन्कम ८५ यान हो गयी जो करीब ३५ डालर पड़ती।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उनकी नेश्नल इन्कम का वह कौन सा हिसाब है, उसे बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बता दिया। आप सुनते तो नहीं। आप बैठिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने बतलाया कि वह करीब ३५ डालर के और सब मिलाकर ५० डालर के चीन की पर कैपिटा इन्कम। उसी समय हिन्दुस्थान की पर कैपिटा इन्कम ६४ डालर है। चीन से हमारी आमदनी ज्यादा है। चीन अपनी फौज पर अपनी नेशनल इन्कम का ८ परसेंट खर्च करता है और हम अपनी इन्कम का १.७ परसेंट। पाकिस्तान अपनी नेशनल इन्कम का ४.२ परसेंट खर्च करता है अपनी फौज पर और उसकी पर कैपिटा आमदनी ५३ डालर। तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि चीन जहां अपनी आमदनी का ८ परसेंट खर्च करे और हम इतना कम खर्च करें तो उससे मुकाबला होने पर सोचिये कि फिर हम उस दुश्मन से लड़ने के लिये क्या डिफेंस का प्रबन्ध करेंगे या नहीं और अगर करना पड़ा तो टैक्स भी लगायेंगे अगर जरूरत पड़ गयी और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो बचत करके भी कर सकते हैं।

यह बात बड़े जोरों से कही गयी है कि ११ करोड़ या १७ करोड़ बाकी है। कौन नहीं चाहेगा कि वसूल न किया जाय ? डाक्टर अहमद साहब ने कहा कि सेल्स टैक्स में करप्शन है और इसीलिये इतना है बकाया, लेकिन रेविन्यू में तो सब वसूल हो गया उसके लिये उन्होंने दाद नहीं दी।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर आपको चीन का मुकबला करना है तो आपको ढूंढ़ना पड़ेगा कि कितना साधन आपके पास है। हमारे यहां मनुष्यों की कमी नहीं। ६१ की सेन्सस के मुताबिक १५ से लेकर ३४ साल तक एज ग्रुप के ७ करोड़ से ऊपर मेल्स हैं और इसमें अनमैरिड की तादाद ढाई करोड़ के करीब है। इन सबको अगर फौजी ट्रेनिंग देना हो किसी न किसी तरीके की तो हम दे सकते हैं, लेकिन एक सिपाही बनाने के लिये ३ साल लगते हैं चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट बनाये या प्रान्तीय सरकार, उसके लिये हमें करना ही है। तो जो बात मैं कहना चाहता था कि चाहे प्रोपैगन्डा

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

की दृष्टि से हो लेकिन अखबार में निकला था कि चीन के किसी प्रदेश में ७ औंस का डेली राशन था जो साढ़े ३ छटांक पड़ता है। और होटल्स में लिखा हुआ है कि देशभक्त वह जो राशन से भी कम खाता है और यहां यह कहा जाता कि ज्यादती हो रही है वसूली में, ब्यूरोक्रेसी परेशान कर रही है। चीन का जब मुकाबला करना है तो वह तो पेट की रोटियां निकालते हैं तो फिर हमें अपने आप त्याग करना ही पड़ेगा। डाक्टर जेड०ए० अहमद साहब की उस बात से मैं सहमत हूं कि औद्योगीकरण किये बिना हिन्दुस्तान का भला हो नहीं सकता। यह सही है कि यू० पी० का औद्योगीकरण नहीं हुआ और उद्योग धंधे यहां पर बहुत कम हैं इसमें दो रायें भी नहीं हैं, लेकिन यह भी सही है कि यू० पी० एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जब तक कृषि की तरक्की नहीं होती, किसान और मासेज के पास बचत नहीं होती, तब तक आप चाहे जितना औद्योगीकरण करें, औद्योगीकरण हो नहीं सकता। उसके लिये वही दूसरा फ्रन्ट फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का है। वह भी हम कर रहे हैं। तो जो असली बात मैं कह रहा था वह यही थी कि इमरजेंसी का वक्त है, कोल्ड वार हमारी चल रही है, किसी वक्त भी युद्ध हो सकता है, हम अपनी आंख उधर से बन्द नहीं किये हैं और इसको जानकर ही बजट बनाया, लेकिन कुछ लोग उसको बड़ी लाइटली देखते हैं। हमारा एन० सी० सी० और ई० सी० सी० आदि, जितने भी कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में हमारे कार्य हैं उनके लिये ५५ लाख रुपया सरकार की ओर से इस बजट में रखा गया है और ट्रेनिंग के लिये एक सैनिक स्कूल खोला गया, पी०ए०सी० की नई बटालियन्स बना रहे हैं। आखिर यह सब क्या है? माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, वह स्वतंत्र पार्टी में किसी वजह से गये, लेकिन हम जानते हैं कि खेती के मामले में उनकी राय महत्व रखती है, फिर भी उन्होंने कई जगह कंट्रेडिक्टरी बातें कहीं, जैसे माननीय जेड०ए० अहमद साहब ने कहा कि गरीब देश का किसी तरह उद्धार नहीं हो सकता अगर वह समाजवाद को न अपनायें और अगर समाजवाद को अपनाता है तो वह चीजें करनी पड़ेंगी जिसको भानु प्रतापसिंह जी ने कहा था कि अपनी पार्टी के अनुसार हम कर रहे हैं और नेहरू जी का दबाव हमारे ऊपर है। तो यह कोई नई चीज नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है, नेताओं का थोड़ा बहुत दबाव मानना पड़ता है, उनकी पार्टी में भी यही है। तो उन्होंने कहा था कि सरकार, प्लानिंग कमीशन, नेहरू और ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई है। माननीय जेड० ए० अहमद ने नीचे का पल्ला लिया। अगर आप छोटे किसान की तरक्की चाहते हैं, मासेज की तरक्की चाहते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दूसरा जरिया नहीं कि समाजवाद बनाया जाय, कंट्रोल कुछ लाया जाय, बड़ी आमदनी वालों की आमदनी पर अंकुश लगाया जाय और छोटों की मदद की जाय। उन्होंने कहा खेती की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक किसान ऐफोर्ड न हो जाय कि उसको कम से कम इतनी कीमत मिलेगी अपने प्रोड्यूस की। मैं कहना चाहता हूं मार्केट का कंट्रोल करना चाहते हैं, प्राइस, कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे होगा? फ्री ट्रेड में होगा, समाजवाद नहीं होगा और फिर जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। गेहूं, चावल पर मिनिमम प्राइस फिक्सड है और जो अन्य गल्ला है उस पर भी, आपने पाटिल साहब का बयान पढ़ा होगा, उन पर भी मिनिमम प्राइस लगा रहे हैं।

यह मैं मानता हूं जितनी तरक्की होनी चाहिये उतनी नहीं होती। मैं थोड़े से आंकड़े आपको बता दूं। कहा गया खेती में कुछ नहीं हुआ। खेती ऐसी चीज है यहीं नहीं दुनिया के हर देश में, अमरीका तक में भी जहां काफी तरक्की हुई है खेती के मामले में, मनुष्य जो कर सकता था खेती को बढ़ाने में, टेक्नोलोजी में और नेचर को कंट्रोल करने में, अब भी वहां पर आधे से अधिक खेती कुदरत पर निर्भर करती है। तो भारत ऐसे गरीब मुल्क में खेती में अगर कुछ पैदावार कभी गिर जाती है तो कुदरत के कारण ऐसा होता है। कुदरत का हिस्सा रहेगा और आगे भी रहेगा और रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय मंत्री जी लंच के बाद बोलें।

मैं एक बात तय करना चाहता हूं। चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, अतः कुछ समय में परिवर्तन कर लिया जाय ताकि कुछ ज्यादा लोग बोल सकें, तो अगर आप सब की राय हो तो बजाय १५ मिनट के १० मिनट कर दिया जाय ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मेरा निवेदन यह है कि आप और अधिष्ठाता महोदय, जो भी इस चेयर पर बैठें, वह निश्चित समय ही सदस्यों को दिया करें। १५ मिनट के बजाय ४० मिनट का समय आप लोगों को दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कहां दिया ? वह तो नहीं दिया। खैर, तो अब यह रहा कि आयन्दा से १२ मिनट का समय दिया जायगा।

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, कमलासिंह यादव, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में कृषि एक प्रधान धंधा है और बावजूद इसके कि कुदरत साथ दे या न दे, फिर भी हमने कृषि के क्षेत्र में कुछ उन्नति ही की है और वह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़ों से जाहिर हो जायगा। फर्स्ट प्लान में हमारा टारजेट १२१.४० लाख टन का था और हम एचीवमेंट कर पाये ११८.०६७ लाख टन। थोड़ी सी ही कमी रही। सैकिंड प्लान का हमारा टारजेट १४२.६७ लाख टन था और प्रोडक्शन १४२.४७ लाख टन हुआ। इस तरह से जो हमारा टारजेट कृषि के क्षेत्र में था उसको हमने करीब-करीब पूरा किया। ५०-५१ में हमारी कृषि की जो पैदावार थी उससे हमने करीब ३७ लाख टन अधिक बढ़ायी। जहां तक खेती का ताल्लुक है, उसमें बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने कहा था कि खेती की पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। यह ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि खेती के क्षेत्र में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। पिछला साल खराब गया, लेकिन इसके पिछले साल में पैदावार अच्छी हुई थी। हमने एग्रीकल्चर के टारगेट को पूरा किया। यह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश का कृषि के संबंध मे कार्य ऐसा नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा निन्दा की जाय।

एक बात माननीय उग्रसेन जी तथा अन्य साथियों ने कही कि हिन्दूस्तान में गरीब और गरीब होता जा रहा है। कोई चीज किसी तरह से कह देना और आंकड़ों का हिसाब न रखना और देश की परिस्थिति का ध्यान न रखना, यह ठीक नहीं है। कई सदस्य कह देते हैं कि गरीबी बढ़ गई और अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। यह हो सकता है कि कुछ अमीर और अमीर हुये हैं, लेकिन गरीब ज्यादा गरीब नहीं हुये। अगर होते तो इतनी बड़ी तादाद गरीबों की है कि हमारी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि ८०/९० प्रतिशत संख्या गरीबों की है। मैं अर्ज करूंगा कि सेंसस रिपोर्ट में हमारी आमदनी दी हुई है कि आल इंडिया फिगर ५०–५१ में ९५३० करोड़ यानी इतनी हमारी राष्ट्रीय इन्कम थी। १९६०–६१ में १४२ अरब हो गया। यू० पी० की जो आमदनी थी १,६२८ करोड़, १९१४ करोड़ यू० पी० की हुई। पर कैपिटा इन्कम १९५०–५१ में आल इंडिया २६६ रुपया थी। वह १९६०–६१ में ३२७ हुई। यू० पी० में २५९ थी, वह २६२ हुई। २६६ से ३२७ फी व्यक्ति की राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि गरीब और गरीब हो गये। ९० फीसदी आदमी गरीब हैं। उनकी जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक राष्ट्रीय पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ सकती। तो मेरा यह कहना है कि यह तो कहा जा सकता है कि जितना तरक्की होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई, लेकिन यह कहना कि प्लान से कोई काम नहीं हुआ, जैसा कि भानुप्रताप जी ने और उग्रसेन जी ने कहा कि योजनायें गरीबी बढ़ा रहीं हैं, अगर गरीबी बढ़ रही है तो देश की आमदनी कैसे बढ़

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

सकती है ? पूर्वी जिलों की मैं ज्यादा गारन्टी से नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सारे उत्तर प्रदेश में मजदूरी बढ़ी है, मजदूरों और किसानों का स्टैन्डर्ड बढ़ा है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। यह वास्तविकता माननी पड़ेगी। देश की हालत खराब हुई है, यह नहीं कहा जा सकता। यह बात हो सकती है कि उसमें ज्यादा सुधार होता।

मेरे विभाग के बारे में भी कुछ कहा गया। शायद एक जौनपुर के दूसरे मित्र हैं उन्होंने भी कुछ कृपा की। उन्होंने कहा कि सहकारिता का विभाग एम्बेजेलमेंट का डिपार्डमेंट है। उनको परिस्थिति नहीं मालूम है। एक दो जगह की बातें देख कर वह ऐसा कहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सब हिसाब किताब रखा जाता है। जो पैसा गबन होता है वह भी लिखा जाता है। १९५८-५९ में १६ परसेंट हमारे यहां गबन था, लाखों में १०.३७ लाख था। १९५९-६० में ७५ परसेंट था, लाखों में ४ लाख ६३ हजार था। वर्किंग कैपिटल बढ़ता गया। १९६१-६२ में वर्किंग कैपिटल हो गया १७ करोड़ ५७ लाख। एम्बेजेलमेंट ४ लाख ९४ हजार था, परसेंट हुआ .०४। १९६१-६२ में १३८ करोड़ ९८ लाख वर्किंग कैपिटल था। ४ लाख ३१ हजार एम्बेजेलमेंट हुआ है, .०३ परसेंट। तो १३८ करोड़ से ऊपर हमारा वर्किंग कैपिटल है और यह रुपये पैसे का मामला जहां होता है हर जगह कोई भी बेंच ऐसी नहीं होगी कि जहां रुपये पैसे का मामला हो और वहां पर कोई गड़बड़ी न हो। तो इसमें भी गड़बड़ी है, मैं इसको मानता हूं और खुद सख्ती चाहता हूं, लेकिन बड़ी मुश्किल की बात उसमें यह पड़ती है कि यह नान-आफिशियल आर्गेनाइजेशंस हैं, जब हम इनको सुपरसीड करते हैं, इनके खिलाफ ऐक्शन लेते हैं तो फिर वही सवाल होते हैं कि क्यों ऐक्शन लिया गया, क्यों सुपरसीड किया गया। माननीय दुबे जी के दिमाग में शायद जौनपुर का केस रहा होगा, जिसके बारे में उन्होंने एक सवाल भी किया था। इत्तफाक से वह सवाल आ नहीं सका, मैं चाहता हूं कि आ जाता तो उसकी सफाई हो जाती। वहां कोई प्रेस था, कुछ वहां गड़बड़ी की शिकायत आयी कि फर्जी लोगों के दस्तखत है, कोई जमानत नहीं है और उन लोगों के नाम रुपया लिखा हुआ है, जब कि सब रुपया खुद खा लिया है और उसका लेख भी निकला है। जब जांच करायी तो मालूम हुआ कि जो हिन्दी के सम्पादक हैं उन्होंने उर्दू सहकारी समिति के खिलाफ यह शिकायत की और उन्होंने वह लेख निकाला। लेकिन जो उस रुपये वगैरह को लिखने वाले हैं वह उनके ही सुपुत्र साहब हैं। तो अगर बिना दस्तखत के रुपया दिया गया तो उनके सुपुत्र साहब ने उसको लिखा कैसे ? असल में बात यह है कि जब रुपया वसूल होने लगता है तो हर आदमी जाता है और कहता है कि हमारे दस्तखत नहीं हैं। उसमें सब लोग सही इन्कार करने वाले ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग झूठे भी इन्कार कर देते हैं और जो खुद इस तरह का काम करने वाले होते हैं वह चाहते हैं कि उनके ऊपर वसूली किसी प्रकार रुक जाय और इसके लिये वह इन्कार कर देते हैं कि हमारे दस्तखत नहीं हैं।

प्रोडक्शन की बात कही गई। मैंने कहा था कि हमने वार टाइम के लिये कृषि की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। हम लोगों ने एक प्रोडक्शन कमेटी बनायी है जिसमें कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, विकास मंत्री और मैं हूं तथा मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। उसने काफी ऐसे काम किये हैं, काफी खर्चे ऐसे लिये हैं कि जिससे बाटिल नेक्स को दूर किया जा सके और गड़बड़ियां दूर हों। ३६-३७ करोड़ का हमारा शार्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन था। इस समय हम १२ करोड़ रुपया ज्यादा लोन देने जा रहे हैं और इसको हम खाद की शकल में देंगे ताकि यह सारे का सारा रुपया खेतों में जाय और पैदावार बढ़े। तो यह काम हमारा और आपका है। आखिर और कौन एजेंसी इसे करेगी ? डाक्टर साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती। सही है, डेमोक्रेसी हमारे यहां है, हम कोई ऐक्शन लेते हैं तो हाई कोर्ट तक रिट में जाते हैं, वहां से लटक जाता है, देर होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अर्ज करूं डाक्टर साहब से और उनके साथियों से कि वे कहते हैं कि नौकरशाही रखें तो आप क्या रखेंगे ? पार्टीशाही रखेंगे और अगर पार्टीशाही चलेगी तो कितना काम वह ले सकेंगे ?

आज की उनकी कम्यूनिस्ट पार्टी में मेजारिटी पार्टी की बात न मानने वाले कितने सदस्य हैं जिनको मैं जानता हूं, लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी ने उनमें से कितने लोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया, कितनों को निकाल दिया ? आप हमारे लिये कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी को नहीं दबा पाते, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितने आदमियों के खिलाफ आपने ऐक्शन लिया जो आपकी नेशनल पालिसी को नहीं मानते । और मैं आपसे कहता हूं कि तानाशाही में और ज्यादा करप्शन होता है, सिर्फ फर्क इतना रहता है कि उस वक्त आप शिकायत नहीं कर पाते । डर के मारे लोगों में मुंह बन्द रहते हैं । जब कोई तानाशाह आता है तो चन्द महीनों के लिये करप्शन को मिटाने की बात कहता है लेकिन ५,६ महीने के बाद वही लोग रहते हैं तो उससे दुगुना, चौगुना करप्शन बढ़ जाता है, जैसा कि आज पाकिस्तान के अन्दर है ।

एक चीज यह कही गई और इसको माननीय उग्रसेन जी ने कहा जसको सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि यहां की गवर्नमेंट करप्ट है और आफिसर भी करप्ट हैं । मैं उनसे पूछता हूं कि किसी माने में कुछ आदमी तो भले होंगें । अगर सब नहीं अच्छे हैं तो उनमें ७५ फी सदी आदमी भले हो सकते हैं । इसी के साथ उन्होंने एक और इल्जाम लगाया कि न केवल करप्ट हैं, बल्कि बुजदिल हैं क्योंकि एन० सी० सी० के विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और ट्रेनिंग पाते हैं, वह लड़ाई में जाने के लिये तैयार नहीं है और अपने देश की रक्षा करने के लिये जाने को तैयार नहीं हैं । यह वह क्या कह रहें हैं ? हम अपने यहां इस तरह की बातें कहकर दूसरे मुल्कों में यह क्या शौहरत फैला रहे है । हम करप्ट हैं, बुजदिल हैं इस तरह की बातें दूसरे देश के लोग सुनकर क्या कहेंगे जब कि वास्तव में यह बिल्कुल उलटा है ? आज दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो इतनी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हों जितना कि हिन्दुस्तान में किया जाता है । जैसे बहादुर हमारे सिपाही हैं, हमारे नौजवान बहादुर हैं ऐसे दूसरे देशों में आपको नहीं मिल सकते । अपने देश में लाखों और हजारों की तादाद में लोगों ने अपने को आफर किया और मिलिटरीवालों ने उनको नहीं लिया । ऐसा उदाहरण आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा । अगर आप यह ट्रेडीशन डालते हैं तो यह सही चीज नहीं है । जितने अफसर काम करते हैं वह सब पढ़े लिखे लोग हैं और जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वह भी पढ़े लिखे आदमी हैं । अगर वह बुज-दिल हैं और लड़ाई पर नहीं जाना चाहते हैं तो कहां से ऐसे आदमी आयेंगे जो देश की रक्षा करेंगे और देश के दफ्तरों का काम चलायेंगे ? १, २ गड़बड़ हो सकती है और इधर उधर जनता में कोई बात हो सकती है, लेकिन उससे यह परिणाम नहीं निकाल सकते हैं कि सब खराब हैं ।

एक बात यह कही गई कि आप चन्दा लेने में बड़ा कोअर्शन करते हैं । मैं आपसे बतलाऊं कि जितना रुपया मिला है आज तक वह सब लोगों ने वालन्टरी दिया है । अगर १,२ अफसर कहीं कोई ऐसा काम करते हैं तो यह उनकी नेकनामी नहीं है और हम उनको बुरा मानते हैं और उन पर ऐक्शन लेते हैं । जितना चन्दा हुआ है वह सब वालन्टरी हुआ है । सब से ज्यादा हमारे प्रधान मंत्री इस बात के लियें ख्वाहां हैं कि एक भी आदमी, अगर चन्दा नहीं देता है तो उससे जबर्दस्ती कोई चन्दा न लिया जाय । इसमें हिन्दुस्तान को अच्छा नाम मिला है । इस तरह की बातें कह कर देश को कलंकित न कीजिये । मेरी अपने मित्रों से प्रार्थना है कि इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिये । मैं भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूं और देखा है कि सब लोग दे रहें हैं । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट से जबरदस्ती करके लीजिये और दूसरी तरफ कहते हैं कि जबरदस्ती की जाती है । कोई जबरदस्ती नहीं की गई है । यह सब वालन्टरी आया है । हमारे यहां जो छोटे बड़े आदमी हैं वे सब देशभक्त हैं । उनके लिये इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक नहीं है ।

यह बात यह कही गई कि वेस्ट में जाओ और कुछ साहब कहते है कि ईस्ट में जाओ । कोई कम्युनिस्ट ब्लाक की बात करते है और कोई वेस्टर्न ब्लाक की बात करते है । मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान किसी तरफ नहीं जायगा । वह अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और हर एक की मदद लेगा । जो हमारा दोस्त है और हमारी मदद करने को कहता है उनसे हम मदद लेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगें । जो चीज हमारे हित में होगी हम वही करेंगें ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

हिन्दुस्तान अपने हित को जानता है और पंडित जवाहरलाल जी इस को ज्यादा जानते हैं। आज रूस भी हमारी मदद कर रहा है तो वह अपने इन्टरेस्ट में हमारी मदद करता है। अमरीका यदि हमको मदद देता है तो वह अपने नेशनल इन्टरेस्ट में मदद देता है। कोई भी देश जो काम करता है वह अपने नेशनल इन्टरेस्ट में काम करता है। हम अपने नेशनल इन्टरेस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि किस बात में हमारा इन्टरेस्ट है। मैं आपको बतलाऊं कि कांग्रेस गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हम सब लोग वही चीज करेंगे जिस चीज में देश का भला होगा। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी पालिसी ज्यादा सफल हुई है। उसमें यदि परिवर्तन करने की जरूरत आई तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको रोक सके। हम सब अपने देश की रक्षा करने के लिये तैयार हैं।

कहा गया कि तिब्बत को आजाद कीजिये। न हमने तिब्बत को गुलाम बनाया और न हम उसको आजाद कर सकते हैं। हमारी हमदर्दी तिब्बत वालों के साथ है और वह यदि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी हमदर्दी उनके साथ होगी। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन हमको अपने देश में अपनी रक्षा करनी है। दूसरे, जहां भी तानाशाही है, जहां भी गुलामी है, जहां भी कोलोनियलिज्म है, वहां की प्रजा यदि उसके विरुद्ध खड़ी होती है तो उसके साथ हमारी हमदर्दी होगी। इन चन्द शब्दों के साथ में इस बजट का अनुमोदन करता हूं।

*श्री ओंकारनाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सन् १९६३–६४ का बजट पेश किया गया है उसके विषय में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही, पहले अनुच्छेद में इकानामिक इमेंसिपेशन की बात कही है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ देश में, प्रदेश में आर्थिक स्वतंत्रता भी आनी चाहिये, लेकिन क्या केवल शब्दों द्वारा ही वह आर्थिक स्वतंत्रता आ सकती है? उसके लिये कुछ कार्य करने होंगे और जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यों की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि इसके कार्यों में और शब्दों में कोई तारतम्य नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता देश में आ गयी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता अभी तक नहीं आ पायी है और उसे लाने की ओर सरकार का अभी तक एक भी कदम नहीं उठा है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि में बहुत से लैन्ड रिफार्म्स हुए हैं। रिफार्म्स तब तक एफेक्टिव नहीं हो सकते जब तक कि प्रदेश का औद्योगीकरण न किया जाय। प्लानिंग को देखते हुये कुछ पता चलता है कि प्रदेश में उद्योगों के लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की खेती ओवर बर्डेन्ड है, बहुत से लोग खेती पर निर्भर करते हैं। जब तक उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं बढ़ते और विशेषकर कैपिटल गुड्स के उद्योग, तब तक हम पिछड़े ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम छोटी इंडस्ट्री बढ़ाते हैं तो उससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आपको तो ऐसी मशीनें बनानी हैं जिनके द्वारा दूसरी चीजें पैदा की जा सकें। सरकार का कैपिटलिस्टों के साथ समझौता है। वित्त मंत्री ने उन पूंजीपतियों से प्रार्थना की है कि वह सरकार का बकाया उसे अदा करने की मेहरबानी करें।

सरकार की इंडस्ट्रियल पालिसी क्या है? वह कहती है कि हम उद्योगों को समाजवाद के आधार पर डेवलप करना चाहते हैं और इसमें कुछ इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज भी किया गया है। जनता को भुलावे में डालने के लिये कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में भी लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कैपिटलिस्टों से करोड़ों रुपया वसूल नहीं किया जा रहा है। अगर हमें इस प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना है और यहां आर्थिक स्वतंत्रता लानी है तो जो लाखों, करोड़ों लोग खेती पर मुनहसिर है, और वह भी पिछड़ी हुई खेती पर, उनके लिये हमें इंडस्ट्रीज डेवलप

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करनी पड़ेंगी और जितनी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं उनको पब्लिक सेक्टर के अन्दर लाना होगा, उनके लिये कैपिटलिस्टों से समझौता नहीं करना पड़ेगा। उनकी पालिसी से इकोनामिक इमेंसिपेशन नहीं आ सकता, उनको इस इंडस्ट्रियल पालिसी में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर वह इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करते, प्रदेश में और देश में गरीबी और अशिक्षा बढ़ती है तो उससे जनता में असंतोष आता है और उसका नाजायज फायदा कैपिटलस्ट उठाते है और कैपिटलिस्टों के साथ जो अलायेंस है उससे इंडायरेक्टली काज आफ कम्युनिज्म बढ़ रहा है, साम्य वाद का हित बढ़ रहा है, क्योंकि जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनको कहने का मौका मिलता है कि यह सरकार आर्थिक समस्याओं को नहीं सुलझा सकती, हम सुलझा सकते हैं।

इधर आज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और व्यक्ति नेहरू जी की जय बोलते हैं, कहते हैं कि हम नेहरू जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जो संसार के इतिहास से परिचित नहीं होंगे वह अनेक भुलावे में आ सकते है। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये कि चीन में पहले जब च्यांग-काई-शेक था और जब तक वह पावर में था, स्टैलिन ने कभी भी उसको दोषी साबित नहीं किया। जब उसका पतन हो गया तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हो गयी और आज प्रचार किया जाता है कि नेहरू दोस्त है, हिन्दुस्तान दोस्त है। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू के साथ सारी बातें हो रही हैं। पर इसके अन्दर जो राजनीति छिपी हुई है वह यही है कि जवाहरलाल को इसी तरह से आगे रखकर जब इस सरकार की इन नीतियों के कारण पतन हो जायगा, जब डेमोक्रेसी का पतन होगा और धीरे-धीरे अन्दर-अन्दर कम्युनिज्म आयेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने हाथ में इस तरीके से शक्ति लेगी। तो जवाहरलाल का जो नारा लगा रहे हैं यह तो उनके स्वभाव और चरित्र के अनुकूल है ही। डिक्टेटरशिप और हीरोवर्शिप इनकी बुनियाद ही है, धर्म ही है और आज जवाहरलाल के नाम पर जो इस तरीके की बातें करते हैं उसके पीछे देश-हित नहीं है। जवाहरलाल बहुत बड़े हैं, हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन देश से ऊपर किसी व्यक्ति को बनाने में जो पार्टियां डिक्टेटरशिप में बिलीव करती हैं वही ऐसा कर सकती हैं, वरना जो प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले हैं उनके लिये देश आगे होता है, तब व्यक्ति का स्थान होता है। चर्चिल के प्रति सारा इंगलैन्ड आभारी है कि लड़ाई के जमाने में उसकी नीति के कारण इंगलैन्ड अपनी आजादी को बचा सका, लेकिन लड़ाई जैसे ही समाप्त हुई, चर्चिल को हटाने में लोगों को एक सेकिन्ड भी नहीं लगा, प्रजातंत्र के द्वारा।

अब मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज देश के अन्दर डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के अन्दर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। जिन देशों में डेमोक्रेसी आई है, मुख्यतः न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन्स में, वहां पर आपने देखा कि धीरे-धीरे वहां की डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली या तो वहां की सेना थी या ब्यूरोक्रेट्स थे। यह संघर्ष भारतवर्ष में अगर चल रहा है तो कोई नयी बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिनिस्टर यहां चुन कर आते हैं और जब जनता पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में कोई शिकायत करती है, तो मिनिस्टर लोग उसको अपनी शिकायत समझते हैं। मिनिस्टर जो जनता के प्रति या इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं, वे अपने को उन अधिकारियों के प्रति ही जिम्मेदार समझते हैं। सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के प्रति ही जिम्मेदार समझते हैं और जब भी उनकी कोई गलती होती है, वे उनकी रक्षा करते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि डेमोक्रेसी की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर ही है तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के संघर्ष में ब्यूरोक्रेसी का साथ न दें।

हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने बहुत सी बातें कहीं। वे आये दिन यह कहते हैं कि गांधी जी की हत्या इस पार्टी के आदमी ने की। मैं उनका ध्यान उन्हीं के पार्टी के इतिहास की तरफ दिलाना चाहूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सोवियत रशा के अन्दर एक नया लिक्वीडेशन हुआ। उन्होंने ट्राइब्स के ट्राइब्स को साइबेरिया भेज दिया। उनके तो लिक्वीडेशन और

[श्री ओंकारनाथ द्विवेदी]

लिबरेशन दो ही विशेष शब्द हैं। या तो लिबरेट करो, या किसी को लिक्वीडेट करो, यह उनका काम रहता है। पता नहीं कितना खून उनके सर पर सवार है। उसको वे नहीं देखते। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें सोच-समझ कर बोलना चाहिये।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सन् १९६३–६४ के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह व्यावहारिक है तथा समयानुकूल है और यह सरकार की दूरदर्शिता का परिचय देता है। इस बजट में हमारी राजस्व आय २,०१,८२,००,००० है और व्यय २,०६,७९,००,००० है। इस प्रकार घाटा है ४,९७,००,००० का। यह निकट भविष्य में कुछ टैक्स लगाकर पूरा किया जायगा। इस बजट की बड़ी आलोचना की गई है कि इसमें सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कोई प्रबन्ध किया गया है तो बहुत थोड़ी रकम रखी गई है। सुरक्षा से कोई एक चीज ही संबंध नहीं रखती है। एक फौजी जवान जो मैदान में लड़ता है उसके पीछे कितने आदमी काम करते हैं, कितनी चीजें उसके लिये चाहियें, उनमें खेती, सड़कें, उद्योग, बिजली, पुलिस, सहकारिता, नियोजन और राष्ट्रीय संकट की बहुत सी बातें आती हैं। कृषि विभाग पर ६,३१,१३,००० रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई है, सार्वजनिक विभाग में सड़कों के निर्माण में ९,५८,९३,०००, परिवहन पर २,०२,५५,०००, उद्योग विभाग पर १०,८९,११,००० की व्यवस्था है, विद्युत में ३,१८,९७,००० है, पुलिस पर, जिसमें ६४० मील लम्बी हमारे प्रदेश की सीमा तिब्बत से मिलती है सुरक्षा के लिये १११ राइफिल ट्रेनिंग सेंटर खोलकर जिनमें हमारी सशस्त्र पुलिस तैयार की जायगी, उसके लिये १२,९१,४५,००० रुपया व्यय होगा। सहकारिता पर ३,१२,५६,०००, नियोजन पर ११,७२,२९,००० रुपया व्यय करने की बात है। राष्ट्रीय संकट संबंधी बातों पर ७,०९,३२,००० रुपया है जिसमें होम गार्ड, प्रांतीय रक्षा दल, तथा पुलिस वगैरह सम्मिलित हैं। इस तरह से ८४,५८,५७,००० रुपया सुरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय होगा जो इस बजट का करीब एक-तिहाई है। कोई भी सरकार इस राष्ट्रीय संकट के समय में अपने सुरक्षा और विकास के कार्यों को नहीं रोक सकती।

कल जब मैं माननीय विकल जी की आलोचना सुन रहा था तो मुझे एक इतिहास की घटना याद आ गई। जब पृथ्वीराज चौहान भारत की एकता और सुरक्षा के लिये महान् प्रयत्न कर रहे थे तो उस समय जयचन्द ईर्षा और द्वेष की भावनाओं से मो० गोरी को निमंत्रण पत्र लिख रहा था। ठीक इसी तरह से जब हमारी राष्ट्रीय सरकार, कांग्रेस सरकार, अपनी योजनाओं में लगी है, सुरक्षा पर लगी है, तो हमारे ही दल के कुछ लोग जयचन्द की परम्परा को निबाह रहे हैं। वे देश के लिये घातक बातें करते हैं और साथ ही मनोबल बढ़ाने की बात भी करते हैं। यदि वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होते या डिप्टी मिनिस्टर होते तो मेरा विश्वास है कि वह ऐसी निन्दा नहीं करते और न बोल पाते कि सरकार छोटी की जाय। अब भी वह बड़े इच्छुक होंगे कि यदि वह इस आसन पर पहुंच जावें तो उनका बोलना बन्द हो सकता है।

एक बात और है। जब मैं बुलन्दशहर से यहां आया और सदन शुरू हुआ तो मुझ से कुछ सदस्यों ने बड़ी चर्चा की उनकी चांदी के तुलने की। पचासों सदस्यों ने मुझसे पूछा कि आपके जिले में माननीय विकल जी तो चांदी में तुले हैं। मैंने कहा कि हां भाई तुले हैं। पहली जनवरी में एक जलसे में घोषणा हुई कि विकलजी चांदी में तोले जावेंगे। देहात से माताओं और बहिनों के हार, हमेल, कड़े, बाजू, पत्तरे आये और श्री विकल जी तुलेंगे। लेकिन २६ जनवरी का दिन धीरे-धीरे आया और मैं दादरी पहुंचा करीब ५ बजे। विकल जी मौजूद थे, कुछ आदमी और थे। मैंने कहा कि भाई, वह चांदी कितनी जमा हुई। तो मालूम हुआ कि हार, हमेल, कड़े आदि जेवर तो नहीं थे, लेकिन गांवों से जो सरकार की ओर से धन जमा करने

की राशि निर्धारित थी, वह चन्दा इकट्ठा किया गया और श्री विकल जी इस ७,८ दिन की भागदौड़ में देहात में किसानों का दूध पी-पी कर ८,१० सेर वजन में बढ़ गये थे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार तौहीन की निगाह से, तौहीन के शब्दों में, यह कहना कि वह दूध पीकर देहात में मोटे हो गये, मैं समझता हूं कि इसमें भाव जो है वह अपमानजनक है और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इन शब्दों को वापस लेंगे।

श्री जसरामसिंह—

मैं वापस लेता हूं।

किसानों ने जितना रुपया इकट्ठा किया, इकट्ठा करके चांदी के वजन का रुपया दिया और उससे वह तौले गये। इस प्रकार देहात से जो चंदा वसूल हुआ वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के फंड में दिया गया और वहां से रसीद लाकर माननीय विकल जी ने उन लोगों को दे दी होगी। इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में जितना लक्ष्य है उतना लोगों से चंदा वसूल करके अगर और सदस्य भी तुलना चाहते तो तुल सकते थे। अभी माननीय विकल जी अखबार वालों से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं कल कैसा बोला। मैंने कहा बिल्कुल गलत बोले। उन्होंने कहा तुम भी ऐसा ही बोला करो तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा कि इतनी हिम्मत कहां है कि ऐसा बोल सकूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट के संबंध में सिद्धांतों की चर्चा करते हुये यह कहना चाहता हूं कि यह संकटकाल बताया जाता है। आज देश की रक्षा का प्रश्न दोनों ओर से उठाया गया है, लेकिन लोग चीन पर हमले के बजाय एक दूसरे पर हमला करने लगे और इस सदन को रण स्थल बना दिया है। अगर हम वाकशूर के बजाय रणशूर बनते तो ज्यादा अच्छा होता। एक दूसरे में हाथापाई की नौबत आ गयी। एक ओर श्री ऊदल खड़े हो गये और दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान खड़े हो गये। एक दूसरे पर सब-मेरीन की तरह से टारपीडो करने लगे हैं। अगर यह लड़ाई का ट्रायल आपस में ही करते रहेंगे तो फिर देश की रक्षा किस प्रकार से होगी? नौकरशाही के लिये हम कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर हम जनतंत्र के हामी लोगों में भ्रष्टाचार है तो किस प्रकार उनका भ्रष्टाचार दूर हो सकता है? यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि अगर किसी देश को जिन्दा रहना है तो उसे अपने भीतर के भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। अगर कोई आदमी अपने दल के अन्दर गंदे आदमियों को स्थान देता है तो वह भी देश का दुश्मन है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट की बात तो छोड़ दीजिये, यह कांग्रेस दल की भी गवर्नमेंट नहीं है, यह तो केवल एक गुट की गवर्नमेंट है। लेकिन आज नेशनल इमर्जेंसी के समय में देश चाहता है कि सब दलों के ईमानदार और अच्छे-अच्छे दिमाग एक जगह इकट्ठे हों और देश का प्रबन्ध अपने हाथ में लें ताकि हमलावर से लड़ सकें। लेकिन हम तो गुटबन्दी में पड़े हुये हैं। आज जितने भी गंदे आदमी होते हैं उन्हीं के दलों में बढ़ावा दिया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो सालभर से इस हाउस में वह दृश्य नजर आ रहा है कि यहां सब पार्टियां किसानों और मजदूरों को बेवकूफ बनाने के लिये हैं और हम यहां पर नाटक करते हैं। एक पार्टी के नेता अपनी दूसरी काउंटर पार्टी, हुकूमत करने वाली पार्टी से बंधे हुये है, और यही कारण है कि माननीय सम्पूर्णानन्द की मिनिस्ट्री में जो गंदा जातिवाद, भ्रष्टाचार था उसके दुगुने रूप में अब बढ़ता जा रहा है। जो भी शासन से च्युत हो जाता है वही डींग मारने लगता है।

[श्री दीपनारायणसिंह]

इधर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान में लड़ाई की स्थिति होते हुये भी इस सदन में आज जातिवाद व दलगत भावना से बहस की जाती है और दुहाई दी जाती है कि हम इस देश के सपूत हैं। किसान का एक लड़का खेतों में गल्ला पैदा करता है, उसी का एक भाई मजदूर कारखाने में काम करता है और तीसरा भाई मैदान में लड़ता है। लेकिन पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली पार्टी के लोग उनसे थैलियां लेकर अपने दल का विस्तार करते हैं। प्रजातंत्र के नाम पर वास्तव में पार्टीबन्दी व दलबन्दी का ही बोलबाला है। मैं मानता हूं कि आपमें भी ईमानदार आदमी है, आई० ए० एस०, आई०सी० एस० आदि में भी अच्छे आफिसर हैं और राजनीतिज्ञों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जैसा कि मैंने एक बार कहा कि कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार है, पूंजीपतियों के दलाल उसमें भरे पड़े हैं जो समय समय पर पूंजीपतियों की मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जन संघ में भी कुछ ईमानदार लोग हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जबकि हमें एक नेतृत्व चाहिये, फिर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं जिससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है? मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र लाने के लिये पंडित नेहरू के नेतृत्व की आवश्यकता है, लेकिन उसे श्रीमती इंदिरा गांधी को ही ऊपर लाकर किया जा सकता है क्या ? इसी बहाने श्रीमती इंदिरा को हमारे मुल्क पर क्यों थोपा जा रहा है और उनको ऊपर लाया जा रहा है? क्या किसी किसान या मजदूर के लड़के को ऊपर नहीं लाया जा सकता था। आपके पुराने डिप्टी मिनिस्टर विष्ट जी ने जो कल टारपीडो छोड़ा वह किस वजह से छोड़ा? मैं कहता हूं कि आप दूसरों के लिये पार्टीबन्दी व दलबन्दी की बात न कह कर पहले अपनी पार्टी को शुद्ध कीजिये। आपकी पार्टी के अन्दर जो बेईमान, मक्कार, भ्रष्टाचारी, गुटबाज भरे पड़े हैं, उनके कान पकड़ कर बाहर निकालिये। पंडित नेहरू के निकालने की बात नहीं है, अगर नेहरू इस वक्त लड़ रहे हैं तो वे नहीं नेतृत्व करेंगे तो क्या लोहिया नेतृत्व करेंगे?

माननीय अशोक मेहता जी से मैं कहना चाहता हूं कि सोशलिज्म के नाम पर मुंडे-मुंडे परिभाषा करके आपस में न लड़िये। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब की बात तो अलग ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि पी० एस० पी०, एस० पी० और जन संघ की डिमारकेशन लाइन कौन है। उस दिन जब मैंने कांग्रेस के पूंजीपतियों के गठबंधन की बात कही तो शंकर की नगरी के रहने वाले पंडित प्रवर वित्त मंत्री महोदय ने कविताबद्ध भाषा में उसे होली का हुड़दंगा कह कर टाल दिया कि यह अररर कबीर तो कितने दिनों से हो रहा है। आपके पुराने उपमंत्री विष्ट जी ने जो टारपीडो छोड़ा, क्या वह अररर कबीर था जिसे टाल देने की बात है ? आप तो भौजाई बने हुये हैं और आपके देवर इधर भी हैं और उधर भी हैं—

अधिष्ठाता महोदय, एक साहित्यिक के नाते पंडित प्रवर ने मुझ किसान की कही बात को भी अररर कबीर कह कर टाल देने की कोशिश की। लेकिन मैं कहता हूं कि आप सुन्दर हैं, आप पर लालिमा है, परन्तु यह लालिमा सही होती तो अच्छा होता। क्या आप पूंजीपतियों के साथ गुलाल खेल रहे हैं जो उन्होंने आपको सुन्दरी समझ लिया है और जो पाउडर लगाये हुये आप का मनोरंजन करते हैं? (लाल बत्ती होने पर) अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने मुझे १२ मिनट का समय दिया है, थोड़ा और दे दिया जाय।

माननीय पंडित जी विराजमान हैं, मैं उनके सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने २७ करोड़ रुपया गरीब किसानों से लगान के रूप में वसूल किया, ५ करोड़ सिंचाई के रूप में लिये और बिक्री-कर और न मालूम कौन-कौन से कर उनके ऊपर लगाये और हर तरह से उनका खून पिया, लेकिन उनके लिये आपने क्या किया ? यह तमाम आप के कमिश्नर, आई०सी० एस० और आई० ए० एस०, आई० पी० एस० जो अपने को दिमाग वाला कहते हैं कि यह नये घुड़सवार डेमोक्रेसी के आये हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और जो भ्रष्ट हैं और भूखे हैं इनको उखाड़ कर फेंक दो। उनको मैं क्या कहूं? आप तो अपने ह्विप विष्ट जी जो हैं उन पर ही, अपने घोड़े पर ही, लगाम नहीं लगा सके, उन्होंने आप पर ही कोड़ा लगाया।

यह आपने कल यहां देखा, उनका कोड़ा भी शासन के घोड़े पर पड़ने लगा। आपके ही संगठन में यह इस तरह की आपस की तू तू मैं मैं हो रही है। एक आप के अन्दर जो ईमानदार चरण सिंह जी थे उनको सेंडविच कर दिया गया है। श्रीमन्, मैं ५ मिनट और चाहूंगा।

× × ×

श्री अधिष्ठाता—

समय की कमी है, आप जल्द समाप्त करें।

श्री दीपनारायणसिंह—

आप को याद होगा कि १७ अगस्त, सन् ६० को पंत जी ने कहा था कि जिस तरह से इंगलैन्ड में ह्विटले कौंसिल्स की स्थापना की गई है उसी तरह से यहां भी की जायगी। उसमें नीचे वाला स्टाफ और ऊपर वाला आफिशियल स्टाफ रिप्रिजेंटेड होगा, लेकिन वहां पर भी एक के ऊपर दूसरा जकड़े बैठा हुआ है जैसे कि पंडित जी बैठे हैं, "श्रद्धा हो तो पालागन न हो तो पालागन।" यह नेहरू जी और गांधी जी के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा और पालागन कब तक करवाओगे समाज तो मुर्दा हुआ जा रहा है, उसकी समाधि बनी जा रही है और आप अपना मतलब गांठ रहे हैं। इस तरह से आप के हाथ मजबूत न होंगे। आप तो स्वयं ही पूंजीपतियों के दूसरे काउन्टरपार्ट हैं, आप महाजनों के हाथ में हैं, उन से आप बकाया कैसे वसूल कर सकते हैं? आप तो किसान से ही लाखों रुपया अलग-अलग करों के नाम से इकट्ठा कर सकते हैं, वही किसान का बेटा आप की फौज में लड़ सकता है और वही आप को पैसा भी दे रहा है। आप तो अपने यहां किसी को मार्शल रेस, किसी को नान-मार्शल रेस, किसी को शूद्र और किसी को हरिजन कह कर अपने अन्दर ही दुश्मनी बढ़ा रहे हैं।

आपके बजट में पुलिस प्रशासन पर खर्च होगा और ८० करोड़ रुपया तो केवल अफसरों का ही है। उनको आप कम करें और उनको कम करने के बाद आप अपने अन्दर की भी सफाई कीजिये, जैसे नेशनल गवर्नमेंट बनती वैसी बनाइये, माननीय कमला पतिजी हैं, ठाकुर हुकुमसिंह जी हैं या चौधरी चरणसिंह जी जैसे ईमानदार लोग हैं इनको आप रखिये और जो दूसरे आप के तीसमार खां हैं जो खाली हाथ खड़ा करते हैं उनके वही हाल हैं कि जिस तरह से मास्टर के सामने कुछ शैतान बेशर्म लड़के क्लास में कहते हैं कि 'दही बड़े वाला, पेठे वाला।' मेरा कहना यह है कि दोनों का कसूर है, उनका भी और आप की इस टीम की पसन्द का भी,. . . . समय समाप्त हो गया है। जयहिन्द!

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता, अभी अपने भाषण में हमारे भाई श्री दीपनारायण जी ने कुछ बातों की चर्चा करते हुये जो कहा कि "बेईमानों, घूसखोर और मक्कारों को भर रहे हैं, शासन और मिनिस्ट्री में", मैं चाहता हूं कि प्रोसीडिंग्स में जांच कर ऐसे शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—

हम एक दूसरे की आलोचना नहीं कर सकते कि हममें से कौन कम योग्य है और कौन ज्यादा योग्य है? अगर माननीय चरणसिंह जी की जगह हम किसी कम योग्यता वाले व्यक्ति को लेते हैं तो उस पर यदि हम चरणसिंह जी की ईमानदारी की बात करते हैं, तो इसमें किसी को बुरा लगने की बात तो नहीं है। मैं कहता हूं कि इतनी चापलूसी तो नहीं करनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री झारखंडेराय के खड़े होने पर) मेरा खयाल है कि मेरी आज्ञा के बगैर आप लोग बोलेंगे तो वह अनुचित होगा।

नोट—[× × ×] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री झारखंडेराय—

मैं आपकी आज्ञा से ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स को देख लें, उसमें बेईमान, घूसखोर और मक्कार शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने शायद जल्दी में या भूल से ऐसा इस्तेमाल किया है और अगर किया है तो उन शब्दों को निकाल देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

प्रोसीडिंग्स देख ली जायंगी और अगर उसमें ये शब्द होंगे तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह शब्द गुड सेन्स में कहे गये हैं। इनको रहने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

वह तो मेरा अधिकार है, निकालना या न निकालना। जो उचित होगा वह मैं करूंगा।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि ४ दिन से लगातार कोशिश करने के बाद आपकी कृपा से मुझे वक्त मिला।

इससे पहले कि मैं इस बजट पर कुछ कहूं यह कह देना जरूरी समझता हूं कि हम लोग जो अपने अपने हल्कों से चुन कर आते हैं उनके दिलों में सदन में अपने क्षेत्रों की बातें कहने का शौक होता है, लेकिन जो कागज और किताबों में लिखी हुई बातें हैं उनका पालन होना चाहिये और यह जो नया तरीका यहां निकला है कि अपनी बात किसी व्यक्ति विशेष के पास पहुंच कर कहें तो बोलने का मौका मिले, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

इसके बाद जो बजट हमारे सामने पेश है उसके लिये वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहूं कि जो बजट पेश हुआ है उसमें कुछ नहीं है। मैंने अपनी थोड़ी अक्ल के मुताबिक बजट को पढ़ने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि आज के संकटकालीन समयमें जितनी जरूरी चीजें हो सकती हैं उसको जिस लियाकत के साथ माननीय मंत्री जी ने रखा है वह तारीफ के काबिल जरूर है। रहा एतराज करने का सवाल, तो विरोधी दल तो उसके लिये आता ही है। साथ ही, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कौन किस भाव से एतराज करता, है इसका अलग अलग बताने का न तो मेरे पास समय है और न मैं इस समय उसमें जाना चाहता हूं। आज जो बातें सदन में कही गयी हैं उनके जवाब का मौका नहीं है, लेकिन हमारे इस सदन में जितने बैठने वाले हैं उनमें से किसी की देशभक्ति पर शुबहा करना या कीचड़ उछालना मुनासिब नहीं है। आज भारतवर्ष एक बहुत बड़ी बेचैनी की हालत में है, चीन ने हम पर आक्रमण किया है और जब एक-एक सूत को जोड़कर रस्सी को मजबूत करना है उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हमारे आपोजीशन के इरादों में जो एक दूसरे पर तानाजनी जारी है उससे कितना अच्छा प्रदर्शन हम कर रहे हैं कि लोग यह पढ़ते होंगे कि यू० पी० असेम्बली में संकटकालीन समय में भी वहां के सदस्य निहायत इत्मीनान के साथ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं।

एक सदस्य—

कोई गाली नहीं देता।

काजी जलील अब्बासी—

कीचड़ उछालने से मेरा मतलब है। मैं निहायत अदब से कहना चाहूंगा कि आज अगर हम किसी को अपना या अपने भारतवर्ष का नेता नहीं मानते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी लड़ाई को लड़ने के लिये सबसे पहले किसी कमांडर-इन-चीफ की जरूरत होती है और उसी की मातहती में हर पार्टी को, चाहे वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जन संघ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, चाहे हिन्दू महासभा हो, चलना पड़ेगा और तभी कामयाबी हो सकती है। अब अगर आप शासन को हाथ में नहीं ले सकते तो महज चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शासन जिसके हाथों में है वह सारी दुनिया का नेता है, अकेले भारत का ही नहीं, उनकी नीति ने सारी दुनिया में एक हलचल मचा दी। कोलम्बो पावर्स उसी नीति के आधार पर दौड़ रही हैं। ४७ मुल्कों ने चीन को आक्रमणकारी कहा और भारत से हमदर्दी जाहिर की, यह नान-एलाइनमेंट पालिसी का ही नतीजा था। चीन के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गये तो इसलिये रुक गये कि रूस ने साफ कह दिया कि सीमा से आगे चीन बढ़ता है तो वह भारत पर आक्रमण करता है। इसलिये वह वहीं रुक गया। जहां मैं अमरीका और ब्रिटेन को उनकी मदद के लिये धन्यवाद देता हूं वहां यह भी नहीं भूल सकता कि रूस ने चीन की मदद न करके और जो सीज फायर हुआ है उसमें काफी रूस का हाथ है। कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम करके आप खुद अपने को कमजोर कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जैसी है वह तो है ही।

कब्ल इसके कि मैं सुझाव रखूं, मुझे इसका दुख है कि हमारी आपस में जो गुटबन्दी है उसका मुजाहिरा इस सदन के अन्दर ऐसे भद्दे तरीके से हुआ जो नहीं होना चाहिये था। हमारा सिर ऊंचे उठ गया जब हमने पढ़ा कि माननीय रामचन्द्र विकल चांदी से तौले गये, जरूर कुछ उन्होंने अच्छे काम किये जिससे जनता ने उनको चांदी में तौलना चाहा। हमने उसको इस तरह से पेश किया कि यू० पी० की सरकार ने जो रुपया जमा किया था वह रुपया जवाहरलाल जी के पास भिजवाने के लिये यह तरीका निकाला गया। अगर वह रुपया पंडित नेहरू के कोष में गया तो खर्च तो वह एक ही काम के लिये होगा। हमने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फंड के रुपये का कोई झगड़ा नहीं किया। हम सबने एक किश्ती पर सवार होकर रुपया इकट्ठा किया है और चीफ मिनिस्टर फंड के लिये रुपया जमा किया, माननीय भानुप्रताप-सिंह जी जानते हैं। हमको माननीय विकल जी के तौले जाने पर खुशी होनी चाहिये।

हमारा जिला बहुत गरीब जिला है और उसकी सीमायें नैपाल से मिलती हैं, हालांकि इस समय कोई झगड़ा उससे नहीं है, लेकिन सीमायें जब किसी दूसरे देश से मिलती हैं तो उनको मजबूत रखना हमारा काम है क्योंकि जिस तरह से चीन ने पागल होकर गलती की उस तरह से कोई और गलती भी हो सकती है। तो हमें मजबूत रहने के लिये सड़कों और पुलों को बनाना है। बजट में इन कामों के लिये रुपया रखा गया है और इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि डुमरियागंज का पुल बनाना चाहिये और जो चरनजीत घाट से सड़क जाती है और अयोध्या से मिलती है, वह निहायत मुनासिब सड़क है और उसके जुड़ जाने के बाद २०, २५ मील लखनऊ से सीधी दूरी कम हो जायगी। इसलिये इसको बनवाने की कृपा वे जरूर करें। (लाल बत्ती जलने पर) अपने समय के अलावा मैं दो मिनट और चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

बोलिये आप।

श्री काजी जलील अब्बासी—

हमारे वित्त मंत्री जी वहां तक हो आये हैं इस वास्ते मैं चाहूंगा कि उसका खयाल रखें।

इसके बाद, मुख लिफ बेन्चेज की तरफ से बहुत जोरों से कहा गया कि नेशनल डिफेन्स फंड का रुपया जबरदस्ती वसूल किया गया। मैं चुनौती देता हूं और साथ चलने को तैयार हूं अगर मेरे जिले में किसी मुकाम पर यह साबित हो जाय कि कोई जबरदस्ती हुई। हमारे डी० एम० डाक्टर चालूं, हम आदी नहीं हैं किसी की यों ही तारीफ करने के, लेकिन जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहां गये तो उन्होंने इन लफ्जों में कहा कि हमारा जिला पिछड़ा और गरीब है। अगर चाहते तो वे भी सख्ती करके बजाय ६ लाख के १६ लाख रुपया दे देते। तो यह एक बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया गया है।

इस सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे यहां के अस्पताल में जो सिविल सर्जन और सर्जन मुकर्रर किये गये हैं उनकी वजह से वहां सर्जरी के केसेज बहुत

[काजी जलील अब्बासी]

खराब हो रहे हैं। मेरी नोटिस में भी एक केस आया है जिसमें उन्होंने ग्लैंड्स निकाले थे। वह ग्लैंडस पैथालोजिस्ट के यहां भेजने थे, लेकिन वे पैथालोजिस्ट के पास न पहुंच कर मालूम हुआ कि उनको कुत्ता खा गया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, अब्बासी साहब की पहली और अब की तकरीर में बड़ा फर्क था। पता नहीं वे डर गये। मैं इस बजट को संकटकालीन बजट मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरे आंकड़े क्या होंगे, यह मैं चाहता हूं कि गोविन्दसहाय जी भी सुनें क्योंकि वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी समाजवाद की तरफ जा रही है। लेकिन अगर १७ साल के बाद भी इस देश के अन्दर गरीबी है, अगर इनकी तीन पांच साला योजनाओं के बाद भी इस प्रदेश में खेती की पैदावार गिरती है, उद्योग का प्रोडक्शन गिरता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या है। कारण क्या है इसका? या तो प्लानिंग गलत है या ये सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। सोशलज्मि के नाम पर अगर इनके आंकड़े गिर रहे हैं तो मेहरबानी करके सोशलिज्म का नाम आप न लें। कोई न कोई कमी आखिरकार जरूर है। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने नेहरू जी की नान-एलाइनमेंट पालसी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का बहुत नाम लिया। लेकिन अगर यही कांग्रेस का समाजवाद है तो मैं कहूंगा कि यह समाजवाद नहीं है। सोशलिज्म के अन्दर यह नहीं हो सकता है, श्रीमन्, कि गरीब गरीब बना रहे और अमीर अमीर बना रहे। १९३५ में बिड़ला की कैपीटल ५ करोड़ थी जो आज ३०० करोड़ रुपये से ज्यादा है। आज उसकी आमदनी ६० गुना ज्यादा है। इसी तरह से जे० के० ग्रुप्स की पहले ११ मिल्स थीं जो आज ६७ हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर नेहरू जी के राज्य में यह सोशलिज्म है, तो बिड़ला, टाटा और पद्मपत के लिये हो सकता है, गरीब के लिये नहीं है। आखिर इसके अन्दर कोई पैमाना अमीरों पर है?

इस बजट से हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे एक मंत्री जी ने कहा कि चीन के मुकाबले में हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। इस किस्म की गलतफहमी हम लोगों में पैदा करें, यह गलत चीज है। १० साल में चीन ने हिन्दुस्तान से दुगनी तिगुनी ताकत हासिल की है। मेरे ऊपर कोई चार्ज न लगाया जाय कि बलवानसिंह लोगों को डिमोरेलाइज कर रहा है, क्योंकि मैं कुछ कहता हूं तो सवाल आ जाता है कि हम मुल्क का मनोबल गिरा रहे हैं। एशिया के जितने मुल्क हैं चीन सबको एड दे रहा है जैसे इंडोनेशिया, नैपाल आदि। आज उसका लोहे का प्रोडक्शन हिन्दुस्तान से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद भी आप इस सड़े हुये बजट को संकटकालीन समय में चीन का मुकाबला करने के लिये ला रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आप चीन का मुकाबला करने के लिये तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर तैयारी करना चाहते तो आपके बजट की तस्वीर दूसरी ही होती। आपके कोई टारगेट नहीं हैं, सिर्फ इधर की चीज उधर और उधर की चीज इधर कर दी है।

मैं डाक्टर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि यह रुटीन बजट हिन्दुस्तान के चेहरे पर धब्बा लग गया है, उसकी बेइज्जती हो गई है। यू० पी० बोर्डर पर है इसलिये कोई विशेष चीज आनी चाहिये थी। इस वक्त एक लाख टन अनाज हम यू० पी० में बाहर से मंगा रहे हैं। इसके अन्दर कोई सोल्यूशन नहीं है अगर हिन्दुस्तान अब भी विदेशों से अनाज मंगाता है तो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। अगर आप यह टारगेट दें कि हिन्दुस्तान विदेश से अनाज नहीं मंगायेगा तो आप एक नई स्कीम देश को देंगे। एग्रीकल्चर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे मामले में भी आपके पास कोई प्लान नहीं है। मैं थोड़े से सजेशन्स दूंगा । काश्तकार की हालत यह है कि अगर वह एक एकड़ जमीन देशी हल से जोतता है तो उसे १८ मील का चक्कर काटना पड़ता है। इतनी बड़ी मेहनत जब वह करता है तो उसको आप देने क्या जा रहे हैं ? पानी आप दे दीजिये, ड्रेनेज आप दे दीजिये, रोड्स आप दे दीजिये, उसके साथ साथ आप मार्केट दे दें। एक लाख रुपया फी गांव खर्च करें तो खेती का प्रोडक्शन डबल हो सकता है। यू० पी० में ५० करोड़ का टार्गेट है। अगर दस हजार गांवों को लें तो दस साल में आप हिन्दुस्तान भर के गांवों को ले सकते हैं। ५० हजार करोड़ का बजट है हिन्दुस्तान के अन्दर, दस साल के अन्दर होगा। यू० पी० में हम ५० ब्लाक लें तो ५० करोड़ रुपया आता है और उसके अन्दर इंटेंसिव कल्टीवेशन कीजिये। आपका चार्ज होता है कि अपोजीशन की तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया जाता है। यह मेरा आपको सुझाव है। अगर आप एक गांव को ले कर बैठें तो उस गांव का भला हो सकता है। आज जिन लोगों का देहात में रसूख है उन्हीं लोगों को रुपया मिलता है। प्लानिंग के नाम से करोड़ों रुपया बेकार जा रहा है। यदि आप कृषि पर अपना ध्यान दें तो मैं आपसे कहता हूं कि उससे मनोबल बढ़ेगा क्योंकि जितनी आयडियालोजिकल वार है, सिर्फ किसान का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा करने पर निर्भर है। इस बजट में कहीं कह दिया है कि कुछ पानी का इंतजाम है, कहीं कुछ चीजों का जिक्र है, लेकिन यह नहीं कहा है कि हमारा यह टार्गेट है कि यू० पी० में डेढ़ दो लाख टन अनाज विदेशों से आता है, यह नहीं आयेगा। हमारा ख्याल है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि १९५२ के बाद विदेशों से अनाज नहीं आयेगा, लेकिन आज भी आ रहा है। कृषि और सोशलिज्म के बारे में पंडित जवाहरलाल जी की स्कीम नहीं ठीक है।

एक बात मैं आपके सामने यह रखूं कि आपको क्या दिक्कत है ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऐक्ट लाने में। वह क्यों नहीं आ रहा है ? काश्तकार के फायदे की चीज क्यों नहीं आ रही है ? यह अब तक लापरवाही है। शुगरकेन की कीमत न बढ़ाने से यू० पी० के अन्दर कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कृषि का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए किसान को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

आपने डिफेंस के सिलसिले में पी० आर० डी० और होम गार्ड्स का जिक्र किया है, लेकिन इससे गांवों वालों का क्या फायदा होगा ? गांव के अन्दर राइफल्स हैं नहीं। १८७८ का आर्म्स ऐक्ट अब भी जिन्दाबाद है। उसको अंग्रेजों ने अपने बचाने के लिये बनाया था। अगर आप आर्म्स ऐक्ट को तोड़ दें तो आपका क्या नुकसान है ? आर्म्स ऐक्ट तोड़ने के बाद लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर बंदूकें सब्जी की तरह ठेले पर लदकर जायं और बेची जायं तो क्या नुकसान होगा ? अगर चाइना की फौजें आती हैं तो क्या आप आर्म्स ऐक्ट को लेकर बैठेंगे ? अंग्रेजों का वही पिटा पिटाया कानून आज भी मौजूद है; उसको खत्म करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इसका जबाव देंगे कि लाइसेंस देने की पिटी पिटाई नीति आज भी क्यों चली आ रही है। डाक्टर जेड० ए० अहमद ने ब्यूरोक्रेसी पर कहा है। मेरे ख्याल से रशा में ब्युरोक्रेसी पूरी पूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि एस० पी० और पी० एस० पी० का कोई सोशलिज्म नहीं है। हमने सोशलिज्म की कुछ थोड़ी सी तशरीह की है जैसे हमने कहा कि १०० से कम नहीं और हजार से ज्यादा नहीं आमदनी होनी चाहिये। हमारा सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनामी का सोशलिज्म नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो जो एस० पी० और पी० एस० पी० को जनसंघ को मिलाने की कोशिश करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ब्युरोक्रेसी की कैसे आलोचना करती है। चाइना और रूस में तो सब की सब ब्युरोक्रेसी है।

इसके बाद मैं एक बात अंग्रेजी के ऊपर कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार खास तौर से एक टार्गेट रख दें कि दो साल के अन्दर, पांच साल के अन्दर, दस साल के अन्दर हिन्दी यू० पी० में जरूर आ जायगी। कम से कम यू० पी० में तो हिन्दी आ ही सकती है।

[श्री बलवानसिंह]

आप अंग्रेजी को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन नहीं चाहता है कि अंग्रेजी यहां से जाय। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार घोषित करे कि यू० पी० के अन्दर अंग्रेजी का चलन खत्म होने जा रहा है।

रूस की बात यहां पर कही गयी। मेरा यह कहना है कि डाक्टर साहब ने नान-अलाइनमेंट की बात की। अगर रूस हमको हथियारों की मदद दे तो इसमें क्या हर्ज है? अमेरिका से पिछली लड़ाई में रूस ने मदद ली थी। इसलिए अगर हम अमेरिका या ब्रिटेन से मदद लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम नान-अलाइनमेंट पालिसी को तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आज आगाह करता हूं कि चाइना की वार सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं है, आयडियालाजिकल वारफेयर है। चाइना की तरफ से ब्रेन वाशिंग हो रही है। इस लिए जो वालंटियर फोर्स आप तैयार कर रहे हैं उसको कुछ ऐसी सामाजिक नीतियां दें, कुछ ऐसी सिटीजनशिप दें, कुछ ऐसी आयडियालोजी दें जिससे जो हिन्दुस्तान के ऊपर कम्युनिज्म का भूत आ रहा है, उसका वह मुकाबला कर सकें। यह केवल आर्थिक लड़ाई ही नहीं है, यह दिमागी लड़ाई भी है। जो एक लाख से ज्यादा वालंटियर फोर्स होगा, उसको आप एक आयडियालोजी दीजिये।

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट पर चालू सामान्य विवाद के कुछ अंशों को सुनने का मुझे अवसर मिला। विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तकरीरों से काफी प्रकाश मुझे मिला है। परन्तु उन तकरीरों से मुझे एक शिकायत है। यह निर्विवाद सत्य है कि कृषि का महत्व इस राष्ट्रीय आपाद काल में नियोजन काल से भी और अधिक हो गया है। परन्तु मेरी आपत्ति है कि विरोधी दल के सदस्यों की तकरीरों में कृषि विभाग और कृषि की समस्याओं को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिला। जनसंघ के सदस्यगण ने आम तौर से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के ऊपर और कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यगण ने आम तौर से जनसंघ के सदस्यों के ऊपर कीचड़ उछाले। मेरी नाकिस राय में इससे जनहित और जनमनोबल दोनों को ही फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा है। वक्त की जरूरत के लिहाज से अच्छा होता यदि वह अपना समय बजाय कीचड़ उछालने के कृषि और कृषि उत्पादन की चर्चा पर खर्च करते। श्रीमन्, इस सीमित समय में मैं प्रयास करूंगा कि कृषि के सम्बन्ध में जो सुझाव माननीय सदस्यगण ने दिये हैं उनके सम्बन्ध में अपनी राय पेश करूं। परन्तु पेश्तर इसके कि मैं ऐसा करूं, मैं चाहूंगा कि प्रस्तुत बजट के वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में जो कुछ आपत्तियां विरोधी दलों की ओर से पेश की गई है उनके सम्बन्ध में भी मैं अपनी राय पेश कर सकूं।

श्रीमन्, मोटे तौर से प्रस्तुत बजट के वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में तीन आपत्तियां पेश की गई हैं। पहली आपत्ति यह की गई कि यह बजट पिछले बजटों की तरह से जो सन् ५०. से लगातार आयतन में बढ़ते जा रहेहैं, आयतन में गत बजट से बड़ा है। दूसरी आपत्ति यह की गई कि बजट उत्तर प्रदेश में डेफिसिट (घाटे के) पेश किये जाते हैं और यह बजट भी घाटे का है; सन्तुलित बजट नहीं है बल्कि इसके अन्दर भी इम्बैलेंस है। तीसरी आपत्ति यह की गई कि इस बजट में भी नये टैक्स लगाने की बात कही गई है। मान्यवर, किसी भी पिछड़े मुल्क की वित्तीय पालिसी को मापने की कसौटी यह होती है कि उस वित्तीय नीति से उस मुल्क की रेट आफ ग्रोथ के ऐक्सेलेरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी पिछड़े मुल्क के सामने सबसे अहम सवाल यह होता है कि उसका पिछड़ापन दूर हो, रेट आफ ग्रोथ का ऐक्सेलेरेशन बढ़े। उसके सामने अव्वल प्राबलम या सवाल यह नहीं होता है कि यह अपनी आबादी को सुविधा पहुंचाये, यह प्रश्न सेकेंडरी हो जाता है। सबसे अहम सवाल उसके सामने होता है कि किस प्रकार से रेट आफ ग्रोथ के ऐक्सीलरेशन को बढ़ाया जाय। वित्तीय विशेषज्ञों ने इस सम्बन्ध में एक फारमूला पेश किया है जिसको मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो के नाम से पुकारते हैं और जो फोर इज टू वन है। सीधीसादी भाषा में मैं अर्ज करूंगा कि यदि किसी मुल्क की आबादी स्थिर रहेऔर उस मुल्क की सरकार अतिरिक्त आय का ५ प्रतिशत अधिक इन्वेस्ट करे तो उस मुल्क की

जन-संख्या की प्रति व्यक्ति आय में १.२५ प्रतिशत का इजाफा होगा। हम जानते हैं पिछले दस साल के तजुर्बे के आधार पर कि हिन्दुस्तान के अन्दर प्रति वर्ष २ पर सेंट आबादी बढ़ रही है। इसलिए अपने मुल्क के अन्दर प्रति व्यक्ति आय को केवल स्थिर रखने के लिए ही, उसको गिरने न दिया जाय, केवल इसके लिए अतिरिक्त आय का ८ परसेंट इनवेस्टमेंट करना हमारे लिए आवश्यकीय हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर वर्ष हमारी प्रति व्यक्ति आय ५ पर सेन्ट बढ़े। तो यह आवश्यकीय हो जाता है कि २८ प्रति शत हम अतिरिक्त आय का इन्वेस्टमेंट और अधिक करें। पिछड़े हुये मुल्कों में इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में अधिक होता है। इसलिये जाहिर है कि केवल अभी ही नहीं बल्कि आने वाले उन १०, २० वर्षों में जब तक हमारा पिछड़ापन काफी मात्रा में दूर नहीं हो जाता तब तक हमारे बजट का आये साल आयतन बढ़ता रहेगा। माननीय नेकराम शर्मा जी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने आपत्ति पेश की कि यह बजट सन्तुलित बजट नहीं है। इस तर्क का जवाब पेश करते हुये मैं इस किताब से जिस का नाम है "Fiscal Policies of Under Developed Countries" कुछ शब्द पढ़ देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार से हैं:

"The budget need not always be balanced. Under conditions of less than full employment, for instance, a deficit would be desirable."

ऐसे मुल्कों के अन्दर जहां बेरोजगारी पूर्णतः दूर न हो पाये वहां पर यह हितकर होगा कि वहां का बजट घाटे का बजट हो। श्रीमन्, तीसरी आपत्ति यह पेश की गई कि इस बजट के अन्दर भी नया टैक्स लगाने की बात कही गई है। पिछड़े हुये मुल्कों के सामने बहुत सी समस्यायें होती हैं। उनमें एक अहम समस्या होती है कैपिटल के फारमेशन की धन किस प्रकार से इकट्ठा किया जाय ताकि उसके इस्तेमाल से और अधिक Capital formation हो और जिससे मुल्क के अन्दर दौलत की पैदावार हो सके। हम जानते हैं कि गरीबी की वजह से पिछड़े हुये मुल्क की जनता कुछ ज्यादा बचा सके, यह सम्भव नहीं हुआ करता है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार बजरिये टैक्सों के ही उस धन को इक्ट्ठा करे। और इस तरह से इस्तेमाल करे कि उस मुल्क के अन्दर दौलत की पैदावार में इजाफा हो और इस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़े। जो मुल्क पिछड़े हुये होते हैं या जब तक हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ रहेगा, मेरी राय में उस समय तक देश और प्रदेश के बजट का आयतन बराबर बढ़ता रहेगा। बजट बराबर डैफिसिट के होते रहेंगे और बराबर टैक्सेशन के लिये देश और प्रदेश की जनता को तैयार रहना पड़ेगा। इसके पश्चात् जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था उन बातों और आरोपों के सम्बन्ध में अपनी राय देना चाहता हूं जो कृषि के सम्बन्ध में पेश किये गये हैं। नेकराम जी ने अपनी जबरदस्त नुक्ताचीनी करते हुये दूसरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को ही गलत पेश कर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि उत्पादन का टारगेट १४२ लाख टन था जिसको बढ़ा कर उन्होंने १४४ लाख टन बता दिया। मैं अर्ज करूं कि खुशकिस्मती से दूसरी पंचवर्षीय योजना में न केवल खाद्यान्न में बल्कि गन्ने में, आयल सीड्स और जूट में हमको टारगेट न केवल हासिल हो गये बल्कि काटन को छोड़ कर उन टारगेट्स से हर क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा हुआ है। मैं माननीय सदस्य की तवज्जह तीसरे प्लान के वाल्यूम १ के पृष्ठ ८३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर यह तमाम आंकड़े दिये हुये हैं। वह उनका अवलोकन करने की कृपा करें। इतना ही नहीं, इससे हिम्मत बढ़ कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो targets रखे हैं वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के targets से कई गुणा ज्यादा हैं, अतिरिक्त पैदावार की वृद्धि है। नेता विरोधी दल ने यह बात कही कि हमारी पैदावार की टारगेट के कोई आधार नहीं हैं। वह हमारी वास्तविक जरूरतों को पूरी नहीं कर पायेंगे। मैं उस संबंध में कोई जवाब न देते हुये उनकी खिदमत में यही किताब पेश करूंगा। वे थर्ड-फाइव-ईयर प्लान की वाल्यूम वन को....

श्री कल्पनाथसिंह—

यह लेखपाल के कागज का रेकार्ड है या कृषि विभाग का ?

श्री शिवराजसिंह—

थर्ड-फाइव-ईयर प्लान की वाल्यूम के यह आंकड़े हैं और उन्हें आप पढ़ने का कष्ट करें। जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट थी उसके आधार पर हमने तीसरी योजना में कृषि उत्पादन के

[श्री शिवराजसिंह]

टार्गेट्स रखे हैं और उनके अन्दर जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी जरूरतों को पूरा करने का विचार है। तो इस ग़लतफहमी में नहीं रहना चाहिये कि ये टार्गेट्स हमारी जरूरतों को पूरी करने वाली नहीं हैं। यह बात सही है, जैसा उन्होंने कहा, कपास में हम अपने टार्गेट पूरे नहीं कर पाये, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि उसमें भी हमारी तरक्की संतोषप्रद है। पहली योजना काल में कपास की पैदावार घट गयी थी, ४५,००० बेलों से घट कर २९,००० बेल रह गयी थी। योजना काल में भले ही हमको टार्गेट हासिल नहीं हुए लेकिन उत्पादन में ६० पर सेंट वृद्धि हुई और उत्पादन २९,००० बेल से बढ़ कर ४९.५ हजार बेल्स हो गया। तीसरी योजना काल में प्रथम वर्ष में ही दूसरी योजना काल से उत्पादन ३० परसेंट बढ़ गया और इस बार ६४,००० बेल्स हमारी पैदावार तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में ही हुई है। भानुप्रतापसिंह जी ने शंका प्रकट की थी कि दूसरी योजना में भले ही हमें टार्गेट हासिल हो गये हों, लेकिन तीसरी योजना में टागट हासिल हो सकेंगे, इसमें उनको शुभा है; और उन्होंने अगर मेरी याद सही है; यह भी कहा था कि तीसरी योजना के पहले साल में कोई टार्गेट हासिल नहीं हो पाया है। वह कृषि के विशेषज्ञ हैं और कृषि जिन-जिन बातों से प्रभावित होती है उन्हें जानते हैं। कृषि की उन्नति आंकने के लिये हम किसी एक वर्ष पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इसमें मूविंग एवरेज से काम चलता है। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष से अगर हम अरहर की पैदावार निकाल दें तो बाक़ी सब टार्गेट्स हमारे हासिल हो गये हैं। उनको याद होगा कि १९६१-६२ में, जो तीसरी योजना का पहला साल था, बड़े पैमाने पर पाला पड़ा था जिसके कारण अरहर पूर्णतया मारी गयी थी और मुझे उम्मीद है कि उनके फार्म पर भी अवश्य ही ऐसा हुआ होगा। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में हमारा बेस था १३४.४ लाख टन; इसमें से अरहर की १९६०-६१ की पैदावार निकाल दें तो बेस बन जाता है १२६.७ लाख टन और अतिरिक्त पैदावार करनी थी ८ लाख टन। इस प्रकार हमें १३४.७ लाख टन खाद्यान्न पैदा करना था अलावा अरहर के और इस साल में अरहर को छोड़ कर खाद्यान्न पैदा हुआ है १३५.२९ लाख टन। इस प्रकार आप देखें कि हमारे लक्ष्य हासिल हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे?

श्री शिवराज सिंह--

२० मिनट। इसके अतिरिक्त आयल सीड्स, जूट और गन्ना में भी तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के जो लक्ष्य हैं वह हासिल होते चले गये हैं।

श्रीमन्, इस सदन में एक आम सुझाव दिया गया कि कैटिल और क्राप का इनश्योरेंस होना चाहिए। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे २० मिनट का टाइम और दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आप ४ बजने से ५ मिनट पहले खत्म कर दें तो अच्छा है।

श्री शिवराजसिंह--

श्रीमन्, मैं कोशिश करूंगा। कई माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के फार्म्स के बारे में जानकारी के इच्छुक हैं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने आरोप लगाये हैं। फार्म्स दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक मिकैनाइज्ड स्टेट फार्म्स हैं--वह संख्या में ११ हैं। इनकी दशा सुधारने के लिये सरकार ने १९५९ में एक मिकैनाइज्ड स्टेट फार्म्स कमेटी बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट १९६० में आ गयी। सरकार ने उस पर अपने फैसले ले लिये जिनके अनुसार कार्य हो रहा है। पिछले १० वर्षों में इनका काम बराबर बढ़िया होता जा रहा है और इनका घाटा जो १९५८ में ६.२७ लाख रुपया था वह १९६०-६१ में केवल १.६२ लाख रुपया रह गया है। लेकिन जब हम घाटों का अनुमान लगायें तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बहुत बड़ी शरह से इन फार्म्स पर डेप्रिसिएशन और पूंजी की लागत पर ब्याज देना पड़ता है और ५ साल के अन्दर इस मद में २९.५ लाख रुपया इन मदों में व्यय हुआ है।

एक सदस्य—

प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय नेकराम शर्मा पत्रकारों की कुर्सियों पर बैठे हैं।

श्री शिवराजसिंह—

इसी प्रकार में निवेदन करूंगा कि कोई भी रिआयत इन फार्मों पर नहीं की जाती है। यदि इम्प्रूवमेंट का इवैलुएशन किया जाय तो इन फार्मों पर वह ३५ लाख रुपया आता है। तो इसमें २९.५ लाख जोड़ने पर ६४.५ लाख की रकम पड़ती है। अगर ५ साल के अन्दर घाटा २० लाख रुपया आया है और अगर बैलेंस शीट सही तौर से तैयार की जाय तो इन फार्मों पर घाटे के बजाय मुनाफा है। इतना कहने के पश्चात् भी मैं यह नहीं कहता कि इनमें सुधार की गुंजायश नहीं है या प्रयास नहीं करना चाहिए। सरकार बराबर इनकी दशा सुधारने में लगी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और सरकार ने निर्णय ले लिये हैं।

कुछ सदस्यगण का विचार है कि जितने भी सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स हैं वह घाटे में चल रहे हैं। श्री भानुप्रताप जी ने इससे पूर्व पूछा था कि सामूहिक रूप सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स का क्या है, आज डिटेल्स मौजूद हैं। इनमें ज्यादा लाभ तो नहीं हो रहा है लेकिन ८,६३८ रुपये का लाभ है। हमारे करीब ७९ फार्म्स ऐसे हैं जो फायदे में चल रहे हैं। इस में हमें यह भी देखना चाहिये कि कितनी हमारी पूंजी की लागत है और किस प्रतिशत से कितना हमको उस पर सूद देना होता है। जो भी इम्पलीमेंट्स हैं, उन पर हमको डिप्रीसिएशन भी देना पड़ता है। मजदूरों को अच्छी मजदूरी भी देनी पड़ती है। कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता है। मैं आपसे बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इन फार्म्स पर उत्पादन अच्छे कृषक के खेत के उत्पादन से कम नहीं है। मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म पर भी हमारी ईल्ड बढ़ी है और वह संतोषजनक रही है। (व्यवधान) जो आराजी लैंड फार्म हैं, उस पर भी आप देखें कि ४० रुपये प्रति एकड़ तो डिप्रीसिएशन का निकल जाता है। ५० रुपये प्रति एकड़ इन्टरेस्ट का निकल जाता है। इस तरह से यह ९० रुपये प्रति एकड़ बैठ जाता है। फिर इनकी वास्तविक उन्नति को आंकने के लिये आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इन फार्मों पर पशुधन की कितनी उन्नति हुई है। अगर आप यह सब देखें तो उन्नति संतोषजनक है।

यह सदन में कहा गया कि इस प्रान्त के अन्दर क्राप इन्श्योरेन्स होना चाहिये। मान्यवर, इस प्रश्न पर सरकार ने विचार किया। सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि इस परिस्थिति में यह योजना अव्यावहारिक है। जो वित्तीय साधन चाहिये और जो हालात चाहिये उसके लिये, वे उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों में भी इतनी क्षमता नहीं है उसके लिये जितनी चाहिये। यह कहा गया कि आन्ध्र में यह योजना चालू की गयी। हमने वहां से मालूम किया, वहां इस प्रकार की कोई योजना नहीं चलाई गई। पंजाब से यह जवाब जरूर आया कि वहां पर इस तरह की एक पाइलट प्रोजेक्ट चलाने की योजना १,२०० गांवों के अन्दर, बनायी गयी है। गौर किया जाय कि उस १,२०० गांवों की योजना को चलाने के लिये ही उनको ५० लाख के रेजर्व फंड की आवश्यकता है और करीब ६ लाख कर्मचारियों पर खर्च होगा। फिर यह भी देखना होगा कि इस योजना को आवश्यकीय रूप से चलाया जाय या आप्शनल रखा जाय। फिर यह भी देखना होगा कि कुछ फसलों पर ही यह योजना चलाई जाय या सब फसलों पर। जैसा कि पंजाब के अन्दर है, अगर इसे सभी किसानों पर लाद दिया गया तो छोटे किसानों को बड़ी दिक्कत होगी। ५० फी सदी से कम नुकसान वालों को इससे क्या फायदा होगा? यह सब सोच कर ही यह कहना पड़ता है कि यह योजना हमारे यहां सफल नहीं हो सकती। अमेरिका में भी इस योजना पर भारी घाटा हुआ है। सन् १९३७-४३ तक वहां करीब ३१ मिलियन डालर्स का नुकसान हुआ है और १९४८ से १९५४ तक साढ़े सात मिलियन डालर का नुकसान हुआ। इसलिये यह योजना आजकल की किसानों की स्थित के अनुकूल नहीं है। और इसीलिये इस योजना को शीघ्र ही लेने का सरकार का इरादा नहीं है।

[श्री शिवराजसिंह]

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उत्पादन के संबंध में सरकार ने एक कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की सब कमेटी बनायी जिसको प्रोडक्शन सब कमेटी कहा जायगा जो कृषि के बारे में अहम मामलों की देखभाल करेगी, उसमें जो बाटलनैक है उसको दूर करेगी। इसी प्रकार से उच्च अधिकारियों की भी एक समिति बना दी गयी है, उससे विभागों में जो बाटिलनेक्स हैं वह दूर हो जायेंगे। इस प्रकार से सरकार पूर्णतया सचेष्ट है और भागीरथ प्रयत्न कर रही है कि उसकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के टारगेट्स साल ब साल पूरे हो जायं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृषि की जितनी भी योजनायें हैं उनको बढ़ाने, उनके बारे में प्रचार करने और उनको एक्टेंड करने में योग देने का अपना पवित्र कर्तव्य सीखें, खास-तौर से इस राष्ट्रीय आपत्ति के समय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

माननीय मन्त्री जी ने मेरा नाम प्रोडक्शन के बारे में लिया लेकिन तीसरी योजना की फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फूड प्रोडक्शन १४२ के बजाय १३९ रह गया है। तो क्या सरकार बतायेगी कि फूड प्रोडक्शन कम हुआ है?

श्री अधिष्ठाता---

यहां प्रश्नों का उत्तर देने का बात नहीं है, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता था।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, स्पष्टीकरण ही दिला दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

इस समय ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

(श्री ब्रह्मदत्त मायर का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक राजनैतिक दल से संबंध रखता हूं। उस दल का एक सदस्य होने के नाते मैंने आपके पास लिख कर भेजा है। उसके किसी सदस्य को बुलाने का आपने कोई खयाल किया है या नहीं, मैं हाउस में बैठूं या वाक-आउट कर जाऊं?

श्री अधिष्ठाता---

वाकआउट करने में आप स्वतंत्र हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि यह सदन साढ़े पांच बजे तक चलता है। आपके इस प्रकार से उत्तेजित होने से आपको समय नहीं मिल सकता है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

जहां तक मेरे अधिकार का ताल्लुक है, मेरा अधिकार है कि मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आपका अधिकार रिक्वेस्ट करने का था, वह आपने कर ली। अब समय देने का मेरा डिस्क्रिशन है, जिसको मैं उचित समझूंगा समय दूंगा।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, बजट के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करने से पहले मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह इमरजेंसी को हमारे ऊपर थोप कर जनता के बजाय अपने फायदे के लिये उसको इस्तेमाल करना चाहती है। जिस समय इमरजेंसी लागू की गयी थी चीन का आक्रमण था, देश में एक नयी जागृति पैदा हो गयी थी, बच्चे-बच्चे का खून उबल रहा था, हर व्यक्ति देश की सेवा के लिये बलिदान कर रहा था, लेकिन दुःख की बात है कि उस नयी जिन्दगी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही फायदा नहीं उठाया गया और सही ढंग से चैनेलाइज करने के बजाय उसको गुटबंदी के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो यह देखना चाहता था कि देश में एक नयी जिन्दगी नजर आती और हिन्दुस्तान की ४४ करोड़ जनता की ८८ करोड़ भुजायें फड़क उठतीं। अगर ये चीजें नजर आतीं तो मैं मानता कि सरकार ने उस रवानी से फायदा उठाया और तब देश भी कुरबानी के लिये, शत्रु से भिड़ जाने के लिये तैयार नजर आता। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेता जिनका हमने भरोसा किया था उनकी हालत कुछ और थी। कुछ लोगों ने पार्टीबन्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने यह नहीं देखा कि इस वक्त हमारे देश के सामने मुसीबत है और उस मुसीबत ने एक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। उसका नतीजा यह हो सकता है कि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किल से बड़ी कुरबानियों के बाद जो आजादी हमने हासिल की, अगर एक बार अपनी गलती से हमने उसे खो दिया तो आयन्दा शायद फिर हिस्ट्री के अन्दर या कम से कम हमारी जिन्दगी के अन्दर नहीं आने की। मैं तो तब मानता जैसे कहा गया है—

"रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल,
जो आंख ही से न टपके, तो फिर लहू है क्या?"

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी डिफेंस नीति के अनुसार जिस तरीके से इस देश की रक्षा करना चाहती है उसके लिये इस बजट के अन्दर कौन सा इन्तजाम किया गया है। दोनों तरफ के सदस्यों ने इस बात को माना है कि देश के अन्दर बन्दूक, रायफल व दूसरे औजार इतनी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। यह तो आम जनता की बात है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिस रूप में पी० आर० डी० और होम गार्ड्स आदि बनने जा रहे हैं उन तक के लिये हथियार नहीं हैं जिससे उनको ट्रेनिंग दी जा सके। अगर इस बजट में बन्दूक व दूसरे औजारों के बनाने की फैक्टरी का इन्तजाम किया गया होता तो उससे फौरन ही ये हथियार अपने यहां उपलब्ध हो सकते थे। यही नहीं, बल्कि हमारे यहां बहुत-सी जगहों पर अन लाइसेंस्ड आर्म्स आदि बनते हैं, अगर उन्हीं को कहा जाता कि वे अपने हथियार वापस कर दें या लाइसेंस ले लें, ताकि वे लीगलाइज्ड हो जायं या लाइसेंसशुदा लोगों के हथियार भी ले लिये जाते तो ट्रेनिंग देने के काम में हमें काफी मदद होती। साथ ही जो कारीगर अनलाइसेंस्ड आर्म्स आदि बनाते हैं अगर उन्हीं को बिश्वास में लेकर उनकी कारीगरी का फायदा उठाया जाता तो काफी अच्छी तादाद में हमें हथियार उपलब्ध हो जाते। लेकिन लाखों रुपया लगा कर भी आज कल लकड़ी के बन्दूक बनाये जाते हैं और इस तरह से जनता की कमाई का इस्तेमाल गलत व बुरे तरीके से किया जाता है। इसका कोई हल होना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे नेता—जैसा कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि वही पुराने तरीके का बजट हमारे सामने ला रहे हैं, कोई भी परिवर्तन इसके अन्दर नजर नहीं आता, फिर मैं कैसे मान लूं कि यह इमर्जेन्सी का बजट है?

हाल ही में केन्द्रीय सरकार की एक पालिसी के मुताबिक हमारे प्रान्त में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे आदमी हैं जो सुनारी का काम करते हैं, वे बेकार हो गये हैं। इस बजट में उनको काम देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे वे अपनी गुजर बसर कर सकें। यह एक बड़ी बात है, उनकी तरफ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये था। उनके लिये सरकार ने यह समझ लिया कि जैसे वह कोई प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं और जैसे उन्होंने जीवन निर्वाह के लिये कोई तिजोरियां भर रखी हैं। वह तो बेचारे जेवर का काम करने वाले मजदूर हैं जो दिन भर मजदूरी कर के किसी तरह अपना पालन-पोषण करते हैं। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

इस बजट में बताया गया है कि सवा करोड़ की कटौती खर्च में की गयी है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बचत के लिये ३१ लाख रुपये की रकम हरिजन कल्याण से काटी गयी है और दूसरे जो सार्वजनिक कल्याण विभाग हैं उसमें से भी ९ लाख की रकम

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

काटी गई है, यानी सवा करोड़ में से यह ४० लाख की रकम ऐसी मदों से काटी गई है जिनमें कि और अधिक धन देने की जरूरत थी। हरिजन कल्याण से ३१ लाख की कटौती कर डालना कहां की समझदारी की बात है ?

इसके अलावा, बड़े दुख की बात है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है और सदन के हम प्रतिनिधियों में से २५० के करीब सदस्य कांग्रेस के हैं जो उधर बैठते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई दस पन्द्रह आदमियों का ऐसा सेट नहीं मिला जिस के ऊपर आम जनता का विश्वास होता और जिस पर जनता आक्षेप न करती और उंगली न उठायी जाती। वह उन आदमियों को भी कैबिनेट में शामिल कर सकते थे कि जो अपना सब कुछ देकर सही मानों में जनता की सेवा कर सकते थे। आज के सेट-अप में उनके यहां जिस तरह से गुटबाजी और पार्टीबाजी चल रही है उसमें वह अपने कल्याण की हर वक्त सोचेंगे या प्रदेश के कल्याण की सोचेंगे ? आपस में ही एक दूसरे की आलोचना होती रहती है। हम तो आशा करते थे कि कांग्रेस दल पुराना बुजुर्गों का दल है और वह जनता के कल्याण के लिये कोई आदर्श उपस्थित करेगा, लेकिन अगर उनकी यह दशा है तो उन पर जनता का विश्वास क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो रहा है, एक मिनट बाकी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

कृषि विभाग के बारे में भी मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि उसमें भी कोई विशेष सफलता उनको मिली है। एक कृषि विभाग जो पहले था उसको अब इस तरह से डिसइन्टेग्रेट किया गया है कि कृषि कहीं है, सिंचाई का प्रबन्ध कहीं है, बीज का प्रबन्ध कहीं है और उनकी योजनायें कहीं बनती हैं। इस तरह से एक-एक कृषि के काम को तोड़-मरोड़ कर इधर-उधर किया है कि एक व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, कृषि मंत्री किसी टारगेट पर पहुंच ही नहीं सकते। हर एक प्रकार की शक्ति का निचोड़ खींचकर मुख्य मंत्री जी ने अपने हाथ में रख लिया है। अगर ईमानदारी से किसी विभाग का पूरा कार्य करना चाहें तो वह कर ही नहीं सकता, ऐसी हालत उन्होंने पैदा कर दी है। जब तक कोई उन पर पूरा ईमान न लाये, तब तक कोई भी अपनी जिन्दगी और कुर्सी को सलामत नहीं समझ सकता।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गत वर्ष जब बजट अधिवेशन का प्रारम्भ हुआ था उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में एक बड़ा भारी अन्तर आ गया है। अन्तर ही नहीं, बल्कि आज ऐसी भयंकर और नाजुक परिस्थिति उत्पन्न है कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने छल, कपट, धूर्तता और प्रपंच से हमारे देश के सम्मान और स्वतंत्रता को चैलेंज किया है। तो आज इस बदली हुई परिस्थिति में वित्त मंत्री महोदय ने उस दृष्टिकोण से सोचा-विचारा और इस आय-व्ययक को तैयार किया जिसकी कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी और है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस हाउस में अनेक प्रकार के विचारों, तर्कों और बहसों को सुना। यह स्वाभाविक ही है जब विविध आदर्शों, विभिन्न सिद्धांतों और विभिन्न नीतियों को मानने वाले दलों के राजनीतिक नेता यहां मौजूद हों। इस बजट में अनेक बातें विवरणात्मक रूप से कही गयी हैं। मैंने इस बजट को पढ़ने का प्रयत्न किया और सार रूप मंत्री महोदय के भाषण के पृष्ठ २ पर लिखित वक्तव्य को पाया। उसको मैं उद्देश्य रूप में समझता हूं जिसमें उन्होंने कहा है:—"इस राष्ट्रीय संकट ने हमें यह अच्छी तरह बता दिया है कि भारत की स्वतंत्रता और समृद्धि तथा सम्मान की रक्षा के लिये आवश्यक यह है कि हमारा राष्ट्र सबल और सशस्त्र हो तथा शांति की स्थापना के लिये किये जाने वाले हमारे प्रयास की सफलता भी उसी समय संभव होगी जब हम सशक्त और प्रबल राष्ट्र के रूप में अवतरित हों। चीनी आक्रमण

का खतरा कब तक बना रहेगा, यह निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता, तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि हमें अपनी सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने के प्रयत्न में न तो किसी प्रकार की शिथिलता आने देनी है और न आत्मतुष्टि की भावना से असावधान हो जाना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम तेजी से अपने को अपने देश की महानता के अनुरूप शक्तिशाली बनायें और उसके लिये सभी संभव प्रयास करें।

यद्यपि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इस राष्ट्रीय संकट का प्रबल प्रभाव पड़ा है तथापि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये उसे उपयोग में लाना ही होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि विकास योजनाओं को अब अधिक तीव्रगति से चलाना होगा। हमें अन्य दिशाओं की ओर अपना ध्यान बंट जाने की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण रखना है। फलस्वरूप हमें अपनी योजना में इस प्रकार की उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे जिससे कि हमें शीघ्र ही वह सफलता प्राप्त हो सके जो हमारी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है। समूचे देश में इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। एक सीमान्त राज्य होने के कारण हमारे प्रदेश का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के सभी प्रबंधों में उत्तर प्रदेश अपने प्रधान मंत्री का हाथ सदैव बटाता रहेगा।

श्री अधिष्ठाता––

आप अपनी बात भी कुछ कहें, नहीं तो आपका समय समाप्त हो जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

पूरा भाषण ही पढ़ दीजिये।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने स्वयं ही कह दिया है।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी––

इसमें अनेक मदें दी गयी हैं, जैसे कृषि उत्पादन, विद्युत्, शिक्षा, संचार साधन, नागरिक सुरक्षा, मितव्ययिता, आदि। श्रीमन्, जिस तरह से आज संकटकाल है उसके अनुरूप वे हैं। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने इस संकट पर विजय पाने के लिये पूरी तैयारी नहीं की। अब जब संकट उपस्थित हो गया है और सरकार ने तैयारी आरम्भ कर दी तब सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस संकट की स्थिति को वापस ले लिया जाय और संकटकाल की घोषणा समाप्त कर दी जाय। तो यह सोचने की बात है कि क्या सचमुच संकट समाप्त हो गया है? चीन ने चाहे जिन कारणों से हथियार डाला हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि चीन आगे क्या करेगा। उससे समझौते की बात करना दुराशामात्र है और फिर कभी भी हमारे देश पर संकट उपस्थित हो सकता है। विरोधी दलों की बातें सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य और परेशानी हुई। अगर विरोधी दल की गवर्नमेन्ट होती तो क्या वे ऐसी हालत में संकटकाल को समाप्त कर देते? और अगर कर देते तो क्या ऐसा कर के वे देश को मजबूत कर सकते थे? उसकी सुरक्षा कर सकते थे? आप लोग एक जिम्मेदारी के स्थान पर हैं। आपको तो मुल्क को प्रकाश देना है। इस तरह की बातों से देश को हानि होगी।

मैं बद्रीनाथ के इलाके से आया हूं जो बहुत पिछड़ा है। आज हमारा हिमालय खतरे में है। उसमें बड़ाहोती और मांणां पास हैं। मैं यह कहता हूं कि जब तक हिमालय सुरक्षित है तभी तक यह देश सुरक्षित है। हिमालय इस देश का मुकुट है। उसके चले जाने के परिणाम बड़े भयंकर होंगे। मेरा क्षेत्र शिक्षा, सड़कों, आदि में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके बारे में अभी समय नहीं है, जब अनुदानों पर बहस होगी तब कहूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि डिफेंस की पहली शर्त अच्छी सड़कों का होना है। गत वर्ष भी मैंने निवेदन किया था कि सड़कों की हालत बहुत खराब है और उनका निर्माण बहुत तेज गति से होना चाहिये। सीमा की सड़कों को पी०डब्लू०डी० के हाथ में देना खतरे से खाली नहीं है। यह सड़कें फौज के हाथ में दे दी जायं ताकि उनका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बार अपना भाषण बजट के समर्थन में समाप्त करता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

अधिष्ठाता महोदय, सदन में चार दिन से बजट पर सामान्य विवाद चल रहा है और हमारे प्रदेश की गरीब जनता इस ओर देख रही है कि हमारा बजट कितने घाटे का है। प्रदेश के श्रमजीवी किसान, रिक्शा चालक, मजदूर, यह सब गरीब जनता आपकी प्रगति और बजट के लक्ष्यों को न देख कर यह देख रही है कि बजट में कितना घाटा है। हमारे बजट में करीब साढ़े ४ करोड़ का घाटा है और वह इसलिये कि यह सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की परिचायक है। हमारे प्रदेश की जनता को यह विश्वास है कि राष्ट्र पर संकट आया और इस संकटकालीन स्थिति में उस गरीब जनता ने सरकार को और उन आर्गनाइजर्स को, जो लड़ाई को पीपुल्स वार डिक्लेयर करने के लिये जनता के बीच में कार्य कर रहे थे, उत्साहित किया और उनकी मदद की। लेकिन वे लोग जिन पर आज भी १८.५ करोड़ रुपया टैक्सेज और इंडस्ट्रियल लोन्स के रूप में बाकी है उस समय जबकि हमारे देश के बहादुर सिपाही नेफा और लद्दाख के बरफीले पहाड़ों पर देश के सम्मान और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिये अपने प्राण दे रहे थे उस समय हीटर की गर्मी में सेठ और पूंजीपति वर्ग के लोग ब्लैक मारकेट की कमाई अपनी तिजोरियों में सोने की बड़ी-बड़ी ईंटों के रूप में रख रहे थे। प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था का व्यापक रूप होने के कारण आज प्रदेश के मेहनतकश मध्यमवर्गीय लोग और किसान यह सोचते हैं कि साढ़े चार करोड़ रुपये का जो घाटा है उसे हमें ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के रूप में देना है। मैं अपने राजनीतिक दल की ओर से किसान मजदूर भाइयों को तथा मध्यमवर्गीय लोगों को यह आवाहन करता हूं कि यदि उनको अपना सर्वस्व भी निछावर करना पड़े, यहां तक कि घास की रोटी भी खाना पड़े, तो भी वे राष्ट्र के लिये सब कुछ दे दें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिये किसी भी बलिदान में पीछे न हटें और पूंजीवादियों से प्रार्थना है कि वे सोना न इकट्ठा करें, खूब रुपया कमायें और राष्ट्र के लिये भी दें। आज मंत्रियों के रहन सहन में कोई कमी नहीं आई है। अगर हमारे देश की ९० प्रतिशत जनता गरीब भी रहेगी तो देश की रक्षा होना मुश्किल नहीं होगा। १०-१५ प्रतिशत लोग जो उंगली पर गिने जा सकते हैं वे देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। वही देश को सुरक्षित रखेंगे जो ९० प्रतिशत लोग हैं।

श्रीमन्, एक बात मैंने देखी है कि सभी वक्ता अपनी बात कहते कहते इस बात पर आ जाते हैं कि हमारे जिले में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस दल की सरकार होती है वह अपने लोगों के इशारे पर अपनी योजनाओं और प्लान में उन्हीं क्षेत्रों में काम करती है जहां उनके लोग जीतते हैं। पिछले वित्त मंत्री माननीय पालीवाल जी जो अच्छे पार्लियामेंटेरियन कहे जाते हैं उन्होंने भी आगरा के लिये कोई ऐसे कार्य नहीं किये। आगरा विदेशी मुद्रा भी सब से अधिक देता है लेकिन जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स खोली गई हैं उनमें आगरे की उपेक्षा की गई है। आगरा ऐतिहासिक नगर है और उन नगरों में से है जब दुनियां में इसकी शान और कला कौशल का दूसरा नगर नहीं था, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में। इसलिये हमारी सरकार को इस नगर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। १९४७ में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से पूर्व दूसरे विश्व युद्ध में प्रतिदिन आगरा में २५,००० जोड़ी जूते का उत्पादन होता था। १९४६ तक यह जारी रहा। उस समय यह उत्पादन लगभग साल में करीब ढाई करोड़ के होता था और आज जबकि हम नारा लगाते हैं सोशलिस्टिक पटर्न आफ सोसायटी, समाजवादी समाज की रचना का और इस बढ़ती हुई प्रगति व स्वतंत्रता के जमाने में उस शहर में मुश्किल से १५ हजार जोड़ियां भी नहीं बन पाती हैं। वहां पर जो एक जूता गृह-उद्योग है उसको हमारी सरकार ने इन पद्रह वर्षों में किसी प्रकार की कोई व्यापक सरकारी सहायता नहीं दी और इस वजह से आगरे की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत गिरी है। हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त अच्छी तरह से आगरे को पहचानते हैं और आगरा चाहे उन्हें न जानता हो, लेकिन वह आगरे को जीवनभर नहीं भूल सकते। (व्यवधान) उस आगरे के रहने वाले लोगों के सामने आज अपने जीविकोपार्जन की समस्यायें हैं। वहां पर पिछली योजनाओं में निर्माण कार्यों के लिये सरकार ने यह वादा किया था कि नेशनल हाईवे जरूर बनाया जावेगा क्योंकि आगरे में ताज, वहां का किला, सिकन्दरा और फतेहपुर सीकरी की तमाम

इमारतों को देखने के लिये काफी तादाद में विदेशी यात्री आते हैं। इसलिये नेशनल हाईवे की वहां पर आवश्यकता है। लेकिन अभी तक उसका कोई सूत्रपात नहीं हुआ। पिछले दिनों मैंने कहा था, ग्रामीण क्षेत्र की डकैतियों, चोरियों और बढ़ते हुये क्राइम के सम्बन्ध में, कि उसका बुनियादी कारण जमुना और चम्बल के शैल शिखर हैं। इसके अलावा वहां के रहने वाले लोगों को रोजी की समस्या से परेशान होना पड़ता है और उसके लिये क्रिमिनल बनना पड़ता है। पिछले दिनों इस बात के लिये जब संत बिनोवा जी, जो कि हमारे देश के महर्षि के रूप में कहे जाते हैं और बीसवीं शताब्दी के महाप्रणेता कहे जाते हैं, वह स्वयं उन जंगली इलाकों में गये और सुना है कि वहां के डकैतों के गिरोह से मुलाकात की। श्रीमन्, १५ मिनट तो मुझे मिलेंगे....

श्री अधिष्ठाता—

१२ मिनट की व्यवस्था उपाध्यक्ष महोदय आप लोगों की राय से कर गये हैं। दो मिनट आपके और हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

पांच मिनट मुझे और दे दीजिये। यदि उन इलाकों में जहां मैंने पिछले वर्ष कहा था जमुना ब्रिज से शिकोहाबाद तक के क्षेत्र, जमुना चम्बल क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया जाय और आज कल की मशीनरी आदि के द्वारा उस भूमि को समतल करके भूमि हीन किसानों में बांट दिया जाय, यदि वह कर दिया गया होता तो ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ता और उन लोगों को रोजी भी मिल जाती और पी०ए०सी० जो वहां अपराध रोकने के लिये रखी जाती है, उसका खर्चा भी बच जाता। लेकिन इस ओर कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि उस क्षेत्र में जितने भी व्यापारीवर्ग के लोग थे वह लोग सब शहरों में भाग आये हैं। अगर वह वहां होते तो उनका कुछ खयाल किया जाता लेकिन अब वहां तो और पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं।

दूसरी बात—फिरोजाबाद जो आगरा जिले का एक कस्बा, उसकी एक तहसील है, उसके बारे में मैंने पिछली दफा बताया था कि वहां के रहने वाले लोगों से ६० लाख के करीब सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स सरकार को मिलता है। वहां एक ग्लास टेक्नालाजी का दफ्तर होना चाहिये जो ग्लास इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिये वहां बनाया जाना चाहिये था। कानपुर के डाइरेक्टोरेट में उसका एक उप–विभाग है जिस पर काफी रुपया खर्च होता है। लेकिन ३० वर्षों से उस विभाग ने वहां पर कोई नव विकास कार्य नहीं किया। ३० वर्ष पहले जैसे आदमी अपने हाथ से काम करता था, अपने मकान में बैठकर किरोसिन की गैस से टीबी का शिकार होता था, उसी तरह से आज भी उसका स्वास्थ्य और उसकी जिन्दगी खतरे में बनी हुई है। उस कांच उद्योग की ओर कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। एक और बात मुझे ग्लास टैक्नालाजी के दफ्तर में मालूम हुई है कि करीब दो महीने से पूर्व से कुछ पार्टीबन्दी और दलगत भावना के आधार पर हमारे उद्योग विभाग के लोगों ने वहां की कुछ फैक्टरियों को कोयला देना बन्द कर दिया है, जिसके कारण वहां पर काफी क्राइसिस आई है और मुसीबत खड़ी हो गई है।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि इस बजट के सिलसिले में जो सामान्य विवाद हो रहा है उसमें मुझे भी आपने मौका दिया। लेकिन इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं नम्रता से कि जिस प्रकार से यहां पर उठक-बैठक करनी पड़ती है, वह असहनीय है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो अभी बिलकुल नौजवान हैं।

श्री देवेन्द्रसिंह—

मान्यवर, सन् १९६३–६४ के प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में जहां तक मेरी राय है, मैं यह समझता हूं कि बजट सरकार की नीतियों का मापदंड हुआ करता है जिसके जरिये हम इस बात का पता लगाते हैं कि आनेवाले वर्ष में हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वह क्या है। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें ४.९७ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। जहां तक सरकार

[श्री देवेन्द्रसिंह]

के बजट का सवाल है, घाटे का बजट अच्छा बजट समझा जाता है क्योंकि सरकारी या अर्ध सरकारी जो संस्थायें होती हैं उनकी प्रगतिशीलता का यह एक नमूना होता है। यदि यह बजट एक व्यक्ति विशेष का बजट होता तो जो माननीय विरोधी दल के सदस्य इसकी आलोचना करते हैं या इसके विपरीत अपनी राय सदन के सामने प्रस्तुत करते तो उनकी यह बात कहीं तक सही हो सकती थी। अगर आप वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आज हमारे सारे बजट का जो ट्रेन्ड है और उनकी बजट स्पीच का जो ट्रेन्ड मालूम होता है उसका सारा जोर सिविल डिफेंस के ऊपर है जिसके जरिये से हम सुरक्षा कायम रखना चाहते हैं। इसलिये उसके ऊपर जोर दिया गया है। आज हमारे बजट में ७ करोड़ रुपये का प्राविजन खास इस बात के लिये कर दिया गया है जिससे कि हमारी सुरक्षा के कार्य में कोई बाधा न पड़े और हम अपने सिविल डिफेंस के कार्यों को और मजबूत बनायें। कृषि, यातायात, सिंचाई, शिक्षा के साधनों के अलावा यह ७ करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है जिससे हम मेन लक्ष्य अपने सिविल डिफेन्स के लिये रख सकें। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि लड़ाई केवल फ्रंट में जाकर नहीं लड़ी जाती है। आज कोई देश लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसके लिये प्लानिंग की जरूरत होती है और प्लानिंग से ही वह विजयी हो सकता है। गलत प्लानिंग होने से कोई भी देश खतरे में पड़ सकता है। आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न प्लानिंग का है कि हमारी योजनायें सही उतरें। हम जिस योजना को लेकर चलना चाहते हैं और जिसके ऊपर हम चल रहे हैं अगर हमारी वह योजना सफल होती है तो हम अवश्य विजयी होंगे, इसमें दो राय नहीं हैं।

मान्यवर, संकटकालीन अवस्था में जैसी कि आज हमारे देश में विद्यमान है, कुछ चीजों की विशेष आवश्यकता पड़ती है, जिसके ऊपर सरकार और जनता को एक साथ गाड़ी के दो पहियों की तरह से चलना है। जिन दो-चार चीजों पर जनता और सरकार को मुख्यतया जोर देना है उनमें एक कृषि है। कृषि का उत्पादन आज हमको बढ़ाना है। उसके बढ़ाने की ओर हमारा नियोजन होगा तो हम अपने देश की अन्न की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। बजट में इसके लिये तरह तरह के उपाय किये गये हैं। बीज देने के लिये सबसीडी का प्राविधान किया गया है। फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाने के लिये ४ लाख टन का हमारी सरकार का टारगेट है १९६३-६४ में। इसी प्रकार वाटर पोटेंशियल भी २.८३ लाख से बढ़ कर ४.५६ लाख सन् १९६३-६४ में सरकार का करने का विचार है।

दूसरी जरूरत इंडस्ट्रीज की है। उद्योगों के बारे में काफी विवाद हुआ। उद्योग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसमें शक नहीं। पहाड़ी इलाकों पर यातायात की कमी की वजह से वहां विकास कार्य, अगर कहें कि निल के बराबर है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वर्तमान समय में जबकि देश में संकट आया हुआ है और इंडस्ट्रीज पर हमको विशेष ध्यान देना है तो पहाड़ों पर जो उद्योग हो सकते हैं उनको बढ़ाया जाय। यह कमी नहीं होना चाहिये कि पैसा कहां से आयेगा। जब किसी चीज की जरूरत महसूस हो और वह उचित समझे तो सरकार पैसा मुहैया कर सकती है और उसे करना चाहिये। पहाड़ों में रा मैटीरियल की कमी नहीं है। मैं वहां का रहने वाला हूं, जगह-जगह मैंने देखा है। वहां पर कागज के कारखाने, टरपंटाइन के कारखाने खुल सकते हैं। जिप्सम की इंडस्ट्री, कार्ड-बोर्ड इंडस्ट्री, जूते, रंग, वारनिश, प्लाईवुड, पेंसिल, ऐसे ही अनेक प्रकार के कारोबार, चटाई मेकिंग इत्यादि बहुत से कारखाने खुल सकते हैं जिनमें लागत भी कम लगेगी और बेकार लोग, जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है वह भी सालभर अपनी गुजर-बसर कर सकते हैं और इससे उनको राहत मिलेगी।

मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के लिये सही है कि पानी की अत्यन्त आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे जिले की एक विशेष परिस्थिति है क्योंकि वह कुछ पर्वतीय इलाका है, कुछ भावर का है, कुछ तराई का है। पहाड़ियों पर तो छोटी-छोटी नालियों से सिंचाई होती है और घाटियों में खेती की जाती है। इसलिये छोटी-छोटी नालियों का वहां पर बनाना बहुत आवश्यक है। जहां तक भावर का सम्बन्ध है, वहां पर नहरें बाबा आदम के जमने की हैं यानी जब से वह हिस्सा बना है तब से उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया है। यातायात

के साधनों की भी वहां बहुत कमी है। पी० डब्लू० डी० के द्वारा जो कार्य वहां पर हुआ है वहां बड़ा असंतोषजनक है और अगर मैं यह कहूं कि यह विभाग "प्लंडर विदआउट डेंजर" है तो गलत न होगा। हजारों और करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन छोटे-छोटे टुकड़े नहीं बन पाये हैं। अगर सरकार उस रुपये पर सूद ही लेती तो काफी रुपया उससे मिल जाता। माइनर पुलों की बात तो दूर रही, तृतीय योजना में जो पुल वहां पर बनाने की योजना है वह भी बनना सम्भव नहीं दीख रहा है।

श्रीमन्, हमारे यहां शिक्षा की भी एक विशेष स्थिति है। वहां पर जाड़ों में बर्फ पड़ जाने के कारण जाड़ों में छुट्टियां होती हैं और प्लेन्स में गर्मियों में। किन्तु टेन्थ, इंटर और बी०ए० आदि की जो परीक्षायें होती हैं वे एक ही समय में होती हैं जिससे वहां के विद्यार्थियों को उतना समय पढ़ने के लिये नहीं मिल पाता जितना कि यहां प्लेन्स में। तो तृतीय योजना में जो हिल यूनिवर्सिटी की बात शामिल है उस पर अवश्य सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, इस चार दिन की बहस और प्रस्तुत बजट की रूप रेखा को देखने से ऐसा लगता है कि इस संकटकालीन में उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट संकटकालीन परिस्थितियों के अनुकूल बना हो या न बना हो, कांग्रेस सरकार के सारे कार्य कलाप देश की सुरक्षा की दृष्टि से हों या नहीं, यह बातें कोई अहमियत नहीं रखतीं, मगर मेरी समझ में जो आया है वह यह आया है कि इस सरकार की तरफ से यह कोशिश हो रही है कि उसका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन हो जाय और उनकी तरफ से यह भी कोशिश है कि इस इमरजेंसी में हमारी उनकी मिली जुली एक नीति बन जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट का यह नापाक गठबंधन देश के लिये थोड़ा खतरनाक होगा। जब मैं डाक्टर अहमद की तकरीर को सुनता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं पूछता हूं सन् १९४२ में यह लोग क्या करते रहे। उस समय अखबारों में इनको इम्पीरियलिस्ट के एजेन्ट्स लिखा जाता था। आज एक स्वर से जनतंत्र की बात करते हुये माननीय जेड०ए० अहमद साहेब कहते हैं कि जवाहर लाल नेहरू समाजवाद के बड़े समर्थक हैं और हिन्दुस्तान में समाजवाद लाने वाले हैं। आज से १०,२० वर्ष पहले जवाहर लाल नेहरू क्या थे? इस देश में कांग्रेसी कूड़े पर कम्युनिस्ट कीड़ा पल रहा है। नेफा में और जैसा नरेन्द्रसिंह विष्ट जी ने कहा, उत्तराखंड में "कम्युनिस्ट कीड़ा" मौजूद है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या यह 'कीड़ा' शब्द पार्लियामेंटरी है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

लोक सभा के अध्यक्ष ने इसे पार्लियामेंटरी करार दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

भले ही संसदीय हो, लेकिन अशोभनीय तो है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उत्तराखंड में सुरक्षा होम गार्ड और पुलिस की भर्ती से नहीं हो सकती। वहां की सुरक्षा के लिये आप २,३ साल में अधिक से अधिक लोगों को तालीमयाफ्ता बनावें, उनको खुशहाल बनावें और आवागमन के मार्गों की वहां सुव्यवस्था करें। वहां की दुर्दशा का जो चित्र माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने खींचा है उसका सुधार किसी प्रकार से इस बजट से नहीं हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबन्धन इस सूबे में करोड़पन्त और कंगाली को प्रश्रय देगा। इसका उदाहरण है कि कम्युनिस्ट लोग हमारी विधान सभा में खुल्लमखुल्ला जब यह कहते हैं कि पूंजीपतियों की मिलों का राष्ट्रीयकरण करो, लेकिन वे अपना चुनाव घोषणापत्र तो ज़रा देखें। उन्होंने कहा है कि विदेशी पूंजी को छूट दी जाय और जब उनकी सरकार केरल में बनी तो बिरला साहेब की पूंजी से वहां कारखाने खुले ? कम्युनिस्ट सरकार ने वहां कानून लगाया कि पूंजीपति पर किसी प्रकार का टैक्स न लगे और मजदूर हड़ताल न करें। हमारे यहां एक कहावत है कि "कोदो बिदैहलें और गुरबक सरैहलें।" यह कहावत इनके लिये लागू होती है। आज पंडित जवाहर लाल नेहरू की और कांग्रेस के लोगों की तारीफ करके ये कम्युनिस्ट अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। चीन की ओर से नेफा में प्रचार हो रहा है कि हमारी लड़ाई हिन्दुस्तान की जनता के साथ नहीं है, उसे तो हम खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस तरह के पैम्फलेट आसाम में कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सरकार बांट रही थी। ठीक वही दलील हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जब शांतिनिकेतन में दीक्षांत भाषण करते हैं तो देते हैं। इस कांग्रेस और कम्युनिस्टों के गठबंधन से हिन्दुस्तान की सुरक्षा मजबूत होने वाली नहीं है।

जो भी भाषण सरकार की तरफ से किये जाते हैं उनमें कहा जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग तो हिन्दुस्तान का मनोबल गिराने की बात करते हैं। कौन लोग जिम्मेदार हैं मनोबल गिराने के लिये ? डांगे जैसे लोग जो यह कहते हैं कि चीन कहता है कि हिन्दुस्तान ने हमला किया और हिन्दुस्तान कहता है कि चीन ने किया है, उनके लिये यह विवादग्रस्त है कि चीन हमलावर है या नहीं। ऐसे लोगों को यह सरकार छूट देती है विदेशों में प्रचार करने की। केशवदेव मालवीया ने मास्को में कहा था कि आई हैव गाट माई ओन व्यूज (I have got my own views) जब उनसे पूछा गया कि चीन ने हमला किया या नहीं और इस प्रकार के लोग हिन्दुस्तान की सरकार में रखे जाते हैं। इसी प्रकार उसको भी देखा जाय जो गोविन्द सहाय जी ने कहा तथा डांगे साहब ने कहा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय केशवदेव मालवीय का नाम न लें, वे केन्द्र के मंत्री हैं। आप विधान सभा और उत्तर प्रदेश की सरकार से संबंधित विषयों पर ही बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इसमें सुरक्षा की बात कही गयी है और उसके बारे में इसी सदन में बहुत से विचार प्रकट किये गये हैं। माननीय कमलापति जी ने भी अपने भाषण में उसका जिक्र किया, इसलिये मैं यह कहने के लिये मजबूर होता हूं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जायं। इस सदन में कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार की तरफ से नेहरू चालीसा तो बहुत सा पढ़ा गया, लेकिन अब नेहरू जी के खिलाफ भी तो कुछ बातें सुन ली जायं और इस तरह की बातें करके देश की जनता को गुमराह न किया जाय। सरकारी पक्ष भी इस बात को समझता है कि हम से इस देश की सुरक्षा नहीं हो पायेगी, इसलिये जितना इमरजेंसी के नाम पर अपनी पार्टी को मजबूत किया जा सके उतना ही अच्छा है।

बड़े अफसोस की बात है कि डी० आई० आर० में किसी चीनी या उसके मुखबिर को तो गिरफ्तार नहीं कर पाये, जब कि वे हिन्दोस्तान की सर जमीन पर घुस आये और ३ हजार आदमियों को बन्दी बना कर चले गये और आपने उनकी एक इंच भूमि भी न ली और न एक आदमी ही गिरफ्तार किया। बजाय उसके आपने दिल्ली में गिरफ्तार किया धर्मपालसिंह जी को जिनके बारे में आचार्य कृपलानी, श्री राजगोपालाचारी और श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वे जवाहर लाल जी से कम ईमानदार और देशभक्त नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रदेशीय सरकार ने तो उनको गिरफ्तार नहीं किया है। आप व्यर्थ के आरोप न लगायें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्री शिवराज सिंह ने आकड़ों को देते हुये कहा कि कृषि के टारगेट्स पूरे हो गये हैं। दाल मूंग का हिसाब बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो यह देखते हैं कि उसके साढ़े सात करोड़ आदमियों का पेट नहीं भर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दाल किस भाव बिक रही है? हापुड़ में डेढ़ सेर का चना बिक रहा है। राशन की दूकानों पर चना और गेंहूं का क्या भाव है, इसको देखा जाय। खाली कागज पर ही ये टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। जब हम लखनऊ शहर में देखते हैं कि चित्रों में हिन्दोस्तानी सिपाही चीनी सिपाही को अपने पैरों से दबा रहा है, लेकिन मौके पर हम एक भी चीनी को चोट न पहुंचा सके और चीनी हमारे सिर को फोड़ गये।

(इस समय ४ बजकर ५७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस प्रकार से आप लोगों को कायर बना रहे हैं। आपको चाहिये था कि लोगों को बताते कि किस प्रकार से चीनियों ने भारत मां की बेइज्जती की, किस बुरी तरह से हराया, तो उससे लोगों के मन में वह जाग्रति पैदा होती जिससे प्रत्येक भारतीय चीनियों से उस बेइज्जती और दुर्व्यहार का बदला लेने के लिये तैयार हो जाता। सरकार की कृषि नीति, शिक्षा नीति व सुरक्षा नीति जिस तरह से चल रही है, इससे उत्तर प्रदेश मजबूत नहीं होगा। अगर सचमुच में माननीय त्रिपाठी जी इस संकटकालीन स्थिति में उत्तर प्रदेश को मजबूती की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस बजट में कम से कम तीन योजनायें बनानी चाहिये थीं। एक तो शिक्षा—कि अगले एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाय क्योंकि आज तक केवल १६ प्रतिशत ही शिक्षित हैं अर्थात् १०० में ८४ आदमी अशिक्षित हैं। आपके आंकड़ों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश ने पिछले ४ सालों में सबसे अधिक रेवेन्यू दिया है। करीब ५,५८० करोड़ रेवेन्यू है, जब कि उत्तर प्रदेश की आमदनी सारे हिन्दुस्तान में जितने स्टेट हैं, एक दो स्टेट को छोड़ कर, सब से कम है। तो ऐसी हालत में जब कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया है, शिक्षा पर फी आदमी ३–४ रुपया मुश्किल से खर्च करते हैं, जब कि बंगाल आसाम, बिहार, आदि जो कम रेवेन्यू देते हैं वे शिक्षा पर फी आदमी ५ से ८ रुपये तक खर्चा करते हैं। तो इस तरह का बजट तैयार करने से उत्तर प्रदेश मजबूती की तरफ नहीं जाने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। २० अक्तूबर, १९६२ के बाद का जब कि चीन ने हमारे देश पर हमला किया, यह पहला बजट है जो इस आदरणीय सदन के सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और संतुलित बजट पेश किया है। कहा जा सकता है कि यह बजट जनता के हर वर्ग को राहत नहीं दे सकेगा, लेकिन मैं समझती हूं कि इस समय जब दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे समय का बजट इससे अच्छा नहीं हो सकता। वास्तव में वे सारी चीजें इसके अन्दर मौजूद हैं, जो हमारे प्रदेश की जनता की तरक्की के लिये और देश की सुरक्षा के लिये जरूरी हैं। वह पहाड़ी क्षेत्र जिसके समीप ही दुश्मन की फौज खड़ी है, वहां की प्रशासकीय व्यवस्था के लिये व लड़ाई की पूरी तैयारी के लिये जिन बातों की आवश्यकता होती है वे सब इस बजट में उपस्थित हैं। इसलिये इस बजट का मैं स्वागत करती हूं। साथ ही मैं सरकार के इस निश्चय का भी स्वागत करती हूं कि उसमें एक और सैनिक स्कूल खोलने की वित्तीय यव्वस्था की गई है। हमारे जो सैनिक आज मोर्चे पर हैं उनके बच्चों के लिये हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा देने की योजना सरकार की तरफ से पेश की गयी है और उनके आत्मजों के लिये भी बिना व्याज के तकावी लेने की सुविधा भी दी गई है। इससे सीमा पर लड़ने वाले हमारे जवानों का मनोबल बढ़ता है क्योंकि वे अब बेफिक्री से अपना काम कर सकेंगे।

इस बजट में नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड्स और पुलिस दल बढ़ाने के लिये ७ करोड़ ९ लाख रुपये रखा गया है। द्वितीय मोर्चे को मजबूत करने के लिये ये संगठन सबल बनाये जा रहे हैं।

[श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन]

चमोली में जो अलग से पुलिस के असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल का हेडक्वार्टर बनाया गया है, उसका भी मैं स्वागत करती हूं और सुझाव देती हूं कि इसी तरह से रक्षा के द्वितीय मोर्चे वाले संगठनों में पर्वतीय जन की अधिकाधिक भर्ती की जाय; टेहरी गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल को भी अलग पुलिस जिला बना दिया गया है, यह सत्य है ।

दूसरी बात यह है कि इस बजट में एक नया सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। वह स्कूल यदि नरेन्द्रनगर टेहरी में खोला जाय तो अति उत्तम होगा क्योंकि वह स्थान मैदानी हिस्से के करीब है और वहां की जलवायु भी ऐसी है कि जिससे अभ्यस्थ होने पर प्रशिक्षणार्थी लोग चीन से पहाड़ी मोर्चे पर अच्छी तरह लड़ सकते हैं और यदि कभी पाकिस्तान की तरफ से भी हमला हो तो उस जलवायु के आदी होने के बाद, हमारे सैनिक उससे भी मुस्तैदी से लड़ सकेंगे । इस-लिये इस स्कूल के लिये नरेन्द्रनगर ही स्थान चुना जाना चाहिये ।

बजट के सिलसिले में मैंने निवेदन किया कि यह एक बहुत ही संतुलित बजट है । संकट-कालीन परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा के समुचित इन्तजाम के साथ-साथ कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन और प्राविधिक प्रशिक्षण आदि की अनेक योजनाओं को भी भुलाया नहीं गया है । और मैं कहूंगी कि सुरक्षा के मोर्चों को मजबूत करने के साथ-साथ जो इन कार्यों के लिये ९० करोड़ रुपया इस बजट में रखा गया है, इससे हमारी तरक्की का बहुत कुछ काम आगे बढ़ सकेगा । सामान्य स्थिति में इन कामों पर १०३ करोड़ रु० खर्च करने का इरादा था, अब ९० करोड़ रुपया इसी प्रकार के कामों में व्यय होगा, कुल १३ करोड़ की ही इस में कमी है । घाटे का बजट कोई बुरी चीज नहीं है जब कि हमारे प्रदेश की सरकार और लोगों की नजर सूबे की उन्नति की तरफ लगी हो । इसमें अच्छाईही है, कोई बुराई नहीं है ।

इस तीन चार दिन की बहस में मैं सुनती रही कि हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि पंजाब में जिस तरह मंत्रिमण्डल घटाया गया है वैसे ही वह यहां भी कम होना चाहिये । लेकिन क्या उन्होंने कभी दूसरी तरफ यह भी सोचा है कि पंजाब में मंत्रिमण्डल घटाया तो गया है पर उस के साथ ही साथ वहां सलाहकार लोग रखे गये हैं, उन पर वहां कितना खर्च हो रहा है ? मैं वहां पर मंत्रिमंडल के इस प्रकार घटाने में किसी खास खर्च की कमी हुई है, ऐसा नहीं समझती हूं ।

एक बात मुझे अवश्य आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और उन के सहयोगियों से कहनी है कि उनके जो दौरे होते हैं उन में वह कुछ कमी करें । इसका मतलब यह है कि इससे शासन को जनता के दुख-सुख सुनने का मौका मिलेगा और जो हमारे कार्यकर्त्ता और विभागीय लोग हैं, उनको भी डटकर काम करने का मौका मिलेगा और जो मंत्री, उपमंत्री हमारे हैं, वे फाइल अच्छी तरह से देखेंगे और वे अच्छी तरह से विभागीय अध्यक्षों को निर्देशन दे सकेंगे ।

यह भी आरोप लगाया जाता है कि विभागीय लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और मंत्रिगण अपने महत्वपूर्ण विषयों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं । इस काम की जिम्मेदारी वे अफसरों पर डालते हैं, ऐसी स्थिति में वे अगर उसमें कुछ मनमानी कर देते हैं तो वह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है । अगर इस बजट को दूसरे मोर्चे का बजट कहा जाय तो उपयुक्त होगा क्योंकि इस बजट में ज्यादातर वही चीजें रखी गई हैं जो हमारी सीमा की सुरक्षा के लिये जरूरी थीं, चीन ने हमारे देश पर हमला किया है उससे बचने के लिये हमें सुरक्षा और साथ ही प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करना ही चाहिये थी । लेकिन यह भी मुझे कहना है कि अगर पहाड़ की तरक्की की योजनायें स्थानीय स्थितियों के जानकार लोगों से बनवाई जातीं तो अच्छा होता। अगर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं और जरूरतों को देखकर यह योजना बनतीं तो वे आपकी अधिक सहायता कर सकते थे । उस हालत में उनकी कठिनाइयों को आप अधिक आसानी से दूर कर सकते थे और उन योजनाओं पर अमल कर सकते थे जो कि उनकी आगे की भावनाओं से गुथी हुई हैं ।

अब हमारे जिले की बात लीजिये। टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल का जो मुख्य क्षेत्र हमारा है उसकी बात कहूंगी। वहां पोखरी में एक स्कूल है जिसके लिये जनता ने बार बार मांग की कि सरकार उसको अपने हाथ में ले ले। वैसा ही स्कूल दुद्धी घड़ियाल और कैलाश वांगर में भी है लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कहती है कि अनुदान जितना चाहो ले लो, लेकिन चलाओ तुम्हीं, इस तरह की बात से जनता में असंतोष बढ़ता है। तो मेरा यह कहना है कि सरकार उन स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं की मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया करे और उन्हें अपने हाथ में ले ले।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पी० डब्ल्यू० डी० के काम पर पहाड़ों में ज्यादा जोर दिया जाय। हमारे पहाड़ों में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है रास्तों की समस्या। सड़कों की पेचीदा समस्या है। कुछ रोड्स तो ठीक हैं, लेकिन कुछ रोड्स ऐसी हैं जो अधूरी होने के कारण बिलकुल बेकार सी हैं। जनता ने मांग की है कि उनको पूर्ण किया जाय लेकिन अभी तक उन रोड्स को पूर्ण नहीं किया गया है। एक टेहरी देवप्रयाग रोड है और भी वैसी ही दूसरी रोड्स हैं जिनको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इन सड़कों का निर्माण फौरन पूर्ण हो जाना चाहिये। अन्त में मैं फिर कहूंगी कि पहाड़ की शिक्षा संस्थाओं को सरकार को अपने हाथ में लेकर चलाना चाहिये जिससे लोगों को संतोष हो और आपकी सुरक्षा का काम सफलता के साथ आगे बढ़ सके।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बजट के विषय में विवाद को चलते हुये आज चौथा दिन है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संकट काल में जो बजट प्रस्तुत किया है वह घाटे का है यह अत्यन्त निराशाजनक है। इस समय अपने देश पर कम्युनिस्ट चीन ने आक्रमण किया है। अपने भारत का मुकुटमणि हिमालय आज विदेशी आक्रान्ताओं से कुंठित है। चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में सरकार का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। आज जिस प्रकार से स्थिति का निर्माण हो गया है उस स्थिति में हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। परन्तु आज जो स्थिति देश में निर्मित हुई और अपने प्रदेश के शासक दल का जो रवैया रहा है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। आज जबकि जनता सब प्रकार से अपने बलिदान से राष्ट्रीय सुरक्षा के यज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिये तैयार है, उस समय हमारे शासकों ने जो आदर्श उपस्थित किया है वह एक दुख की बात है। आज कहने से काम नहीं चलेगा कि देश की जनता ने धन दिया है, जनता ने सोना दिया और जनता अपना बलिदान करने के लिये तैयार है। यह तो हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब-जब देश पर संकट आया है तब-तब देश की जनता अपने भेद-भाव को भुलाकर देश की सुरक्षा में योग देती रही है। इतिहास हमें बताता है कि हमारी मां बहनों ने अपने जेवर दिये, अपने सुन्दर बालों को भी काट कर दे दिया है, किन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे समय में देश-द्रोहियों की एक परम्परा सी रही है जिन्होंने सारे प्रयासों को विफल किया है।

हमारे देश का इतिहास बताता है कि हमारे देश में पौरुष का अभाव कभी नहीं रहा। हमारी सेना अशक्त थी या अपर्याप्त थी लेकिन उसमें देशद्रोही परम्परा का भी काफी बड़ा हाथ था जिसने समय-समय पर इस राष्ट्र के साथ द्रोह किया था और आज भी वह अपनी वही नीति अपना रहे हैं जब कि देश की सारी गरीब जनता, किसान, मजदूर आदि अपना सहयोग दे रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपने भेद भाव को भुला कर आगे बढ़ रहे हैं। सभी इस बात की प्रशंसा करते हैं कि आज की परिस्थिति में जनता आगे है और नेता पीछे हैं और जिस भावात्मक एकता के निर्माण के लिये पिछले कई सालों से प्रयास हो रहा था और वह नहीं हो पा रही थी वह अपने आप हो गयी। आज उत्तर से दक्षिण तक, सारा देश एक हो गया है। आज न कोई सिखिस्तान की मांग करता है, न द्रविड़िस्तान की मांग करता है और न अंग्रेजी और हिन्दी का प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन आज जनता पूछती है कि इस प्रदेश की सरकार ने, इन मंत्रियो ने क्या आदर्श उपस्थित किया। क्या आपने अपनी इतनी बड़ी विशाल सेना में कोई कमी की? अपने दौरों में कमी की? भत्ते के

[श्री जगन्नाथ राव]

लेने में कमी की ? नहीं की । कहते हैं कि इस पर खर्चा बहुत कम होता है । पहले तो वह कम नहीं होता लेकिन अगर यह मान भी लिया जाय तो भी जनता की भावना को देखते हुये आज यह आवश्यक था कि सरकार मंत्रिमंडल को छोटा करके जनता के मनोबल को ऊंचा करती । लेकिन वह नहीं हुआ । आज संकट के समय में सीमावर्ती जिलों की क्या स्थिति है, वह माननीय नरेन्द्रसिंह जी विष्ट ने बताया । उन्होंने उत्तराखंड में जिस तरह से कार्य किया गया है वह बताया । उससे यही कहा जा सकता है कि हम देश में संटकालीन परिस्थिति के अनुरूप तैयार नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार ने वहां सड़कें बनाने के लिये काफी रुपया दिया, लेकिन हर बार रुपया देने के बाद भी पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर और अन्य लोग यही कहते हैं कि वहां ठेकेदार नहीं मिलते । आखिर इन्हीं पहाड़ियों पर चीनियों ने अपनी सड़कें बना लीं और उसमें भारतीय मजदूरों का भी सहयोग लिया और पैसा दे कर लिया, लेकिन हमारी सड़कें नहीं बन पायीं । उत्तराखंड की हालत देख कर ऐसा लगता है कि इस संकटकाल का कोई प्रभाव इस सरकार पर पड़ा ही नहीं ।

इसके साथ ही साथ नेपाल से जो हमारे लगे हुये जिले हैं उनमें भी जासूसों का जाल बिछा हुआ है और आज इस देश के अन्दर होने वाली छोटी से छोटी घटना विदेशियों के पास पहुंचती है और इस प्रदेश, देश और इस मंत्रिमंडल में रह कर जो फेलो ट्रैवलर का काम करते हैं वे आपके द्वारा संरक्षण पाते हैं । यह बड़े दुःख की बात है ।

सुरक्षा कार्यों के लिये जो नगण्य सी रकम इस बजट में रखी गयी है, .३ परसेंट के करीब, वह बहुत अपर्याप्त है । आज देश की बदली हुई हालत के अनुरूप सुरक्षा कार्यों के लिये अधिक से अधिक पैसा व्यय करना चाहिये था और विकास के नाम पर उसका दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता । जहां अपनी योजनायें सफल बनानी हैं वहां प्रदेश के यातायात के साधनों को भी सुदृढ़ करना है और अधिक से अधिक शक्ति लगा कर देश को तैयार करना है । उपाध्यक्ष महोदय, इनका एक दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास यह है कि वे कहते हैं कि एक नेता, एक दल और एक नीति हो । लेकिन यह लोकतंत्र की परम्परा के अनुरूप नहीं है । वास्तव में तानाशाही देशों में यह बात कही जा सकती है । एक नेता हो सकता है, एक नीति हो सकती है, लेकिन कई विचारधारा के लोग देश में रह सकते हैं और उनकी विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिये । लेकिन एक नीति और एक नेता कहकर एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और देश के प्रति चिन्ता बहुत कम है । हम कहते हैं कि व्यक्ति महान् होता है, व्यक्ति से दल महान् होता है और दल से देश महान् होता है और जब देश का सवाल आता है तो दोनों को अलग रख देने की आवश्यकता पड़ती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निश्चित मत है कि इस मंहगाई के जमाने में घाटे का बजट हटना चाहिये और इस प्रकार से ऊपर से कर्ज लेकर और बाहरी सहायता लेकर प्रयास किये गये तो देश की मंहगाई को रोकने में सफल नहीं होंगे । आज मंहगाई बढ़ रही है और जन साधारण का जीवन संकट में है । आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक लघु उद्योगों को पनपायें और अधिक से अधिक रुपया देकर गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खोलें । इस प्रदेश में जो रुपया खर्च किया गया है उससे कोई उद्योग-धंधे नहीं खुले और लोगों ने रुपया लेकर उसका दुरुपयोग किया है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्तीय वर्ष के बजट का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । राज्यपाल महोदय के भाषण के विवाद के समय विरोधीदल के नेता ने यह कहा था कि इमर्जेन्सी नहीं है, इसे हटा दिया जाय और इस तरह की कुछ आवाज संयुक्त दल के नेता माननीय उग्रसेन जी ने भी कही थी कि इमर्जेन्सी हटा ली जाय । लेकिन बजट भाषण पर दुबे जी ने अपनी गलती अनुभव की और उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि इमर्जेन्सी है । उग्रसेन जी ने अपने भाषण में कहा था कि बदरीनाथ पर संकट है और मानसरोवर में चीनी तैयारी कर रहे हैं और

अन्त में यह कहा कि देश में इमर्जेन्सी नहीं है। मैं समझता हूं कि संकट की बात तो वे भी मानते हैं और आज देश में संकट है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

मान्यवर, कुछ लोगों ने यह कहा कि मद्य निषेध में जो संशोधन किया गया है वह गलत है। मैं भी ड्राई जिले का रहने वाला हूं। हमारा जौनपुर जिला है। वहां पर मद्य निषेध कानूनी रूप में रहा है लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी और चोरी-चोरी शराब तथा दूसरी चीजें बिक रही थीं। लोग जिंजर पीने लगे थे। जब से शराब की दूकानें खुली हैं लोगों ने जिंजर पीना बन्द कर दिया है। आज भी और उस समय भी गांजे की दूकानें खुली थीं और ट्रकों द्वारा तस्कर व्यापार चल रहा था। इस पर सरकार ठोस कदम उठाये। लोगों ने कहा कि सरकार ने उद्योग की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राविधिक शिक्षा के लिये व्यवस्था इस बजट में की है। मान्यवर, मेडिकल कालेज में २५ प्रतिशत छात्रों की वृद्धि, मेरठ में मेडिकल कालेज खोलना और मेडिकल के छात्रों को ऋण देना, इसी तरह से एम० एस-सी० के अधिक से अधिक लोगों को तैयार करना, इन सब बातों के लिये प्राविधान इसमें किया गया है, उसके लिये भी माननीय वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि आज के युग में विज्ञान की शिक्षा हमारे देश के लिये बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से रुड़की इंजीनियरिंग कालेज में छात्रों की संख्या १०३ से बढ़ाकर ३०६ कर देने की व्यवस्था है और दयालबाग में भी छात्रों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है। ऐसे ही ड्राइवर्स और वायरलेस आपरेटर्स को ट्रेंड करने की व्यवस्था की गई है और औद्योगिक संस्थाओं में सभी जगह छात्रों की वृद्धि करने की व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने की है वह आज की संकटकालीन स्थिति को देखते हुये बड़ा ही उपयुक्त कदम है और इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं।

मान्यवर, अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने संकेत किया है कि आगे हमें इन कमियों को पूरा करने के लिये टैक्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिये, मान्यवर, जो इधर के भी बहुत से माननीय सदस्यों और उधर के भी बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं.....

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

एक प्वाइन्ट आफ रिक्वेस्ट है। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री माताप्रसाद--

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सभी माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि पूंजीपतियों पर जो टैक्स बकाया है वह उनसे वसूल किया जाय। यह इधर के माननीय सदस्यों ने भी कहा और उधर के माननीय सदस्यों ने भी कहा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज किसान लेखपालों से बड़ा परेशान रहता है। यद्यपि सरकार ने उनके अधिकार ले लिये हैं, लेकिन कैफियत के खाने में वह इन्दराज आज भी करता है और उसके द्वारा लोगों को परेशान करता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि हर साल किसानों को इन्तखाब मिल जाया कर चाहे इसके लिये किसानों को कुछ पैसा ही क्यों न देना पड़े। इससे उन किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रेमसिंह--

मान्यवर, मैं बहुत खुश हूं कि अब थोड़े दिन के लिये हम लोग चले जायेंगे, इसलिये थोड़े से अल्फाज हम भी कह दें। इससे पहले कि मैं बजट के ऊपर कुछ कहूं, मैं आपके सामने एक कविता रखना चाहता हूं। उसको आप सुन लें तो अच्छा है--

चीनियों को चीन प्यारा, तो हमें भी हिन्द प्यारा,
किस तरह से चल सकेगा साम्यवाद एक नारा ?
आक्रमण से थोप सकता " वाद" कोई अब नहीं है।

[श्री प्रेमसिंह]

चाऊ वाली चाल तज दे, बस यही है एक नारा ।
चीनियों को चीन प्यारा, तो हमें भी हिन्द प्यारा ।।
तुम बढ़ोगे हम बढ़ेंगे, तुम झुकोगे, हम झुकेंगे,
तुम लड़ाकू, हम लड़ाकू, किस तरह दोनों रुकेंगे ?
पग तुम्हारा जहां होगा, वहीं होगा पग हमारा ।
चीनियों को चीन प्यारा, तो हमें भी हिन्द प्यारा ।।
तुम हिमालय पार रहना, जहां सीमा है तुम्हारी ।
इसी में कल्याण होगा, अन्यथा है युद्ध भारी ।
तुम अकेले पड़ गए हो, क्या कभी इस पर विचारा ?
चीनियों को....

अब मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा कि अंग्रेजी की तरफ मैंने ध्यान दिलाया तो लोगों ने बहुत एतराज किया, तो अब अरबी की बात बताता हूं---

"कुलित ला हुम्मा मलिकल मुल्क
तोतिल मुल्क मन्शाओ
वतन जए उल मुल्का
मिन मन्तशा वतो इज्जो मन्तशा
वतो जिल्लो मन्त शा
बैडेया दे कल खैरइननक अल्ला कुल्ले शै इन कदीर"

यानी इसके माने यह हैं कि---जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। मैं इनको ही नहीं कहता हूं बल्कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। यदि हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है तो हमको हरएक को मिलकर चलना है तभी हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं वरना उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

अब मैं अरबी की तरफ फिर आता हूं। "वतो इज्जो मन्तशा वतो जिल्ल मन्तशा।" इसका मतलब यह है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला वही पाक परवरदिगार है। इसी नसीहत को लेकर हम को चलना चाहिये। चीन ने जो हमारा मुल्क फतेह किया है उससे हमको डर नहीं जाना चाहिये बल्कि उसका सख्ती से मुकाबला करना चाहिये। यहां पर जो हाउस में बहस होती है हम उस बहस से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमको भरोसा रख कर और उस को फतेह करने के खयाल से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर एक एम० एल० ए० को मिलिटरी ट्रेनिंग लेने की कोशिश करनी चाहिये। तभी हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं और चीन का हौसला पस्त कर सकते हैं। मगर किया क्या जाय ? वह अल्लाह एक है और वह मुल्कों का मालिक है, जिसको चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है। वही अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। हर किस्म की खुशी और जिल्लत उसी के हाथ में है।

अब मैं कुछ बजट के ऊपर भी कह देना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि "मैंने किया था भरोसा, पर वक्त पर तुम भी काम न आये"। आप ने जो बजट में अपना एक्सपेन्डीचर पेश किया है हम चाहते हैं कि उस को पास न करें क्योंकि गये साल जब एलेक्शन हुआ था तो आप लोगों में आपस में झगड़े की वजह से मुख्य मन्त्री ने सब ढेरों से पोर्टफोलियो सम्भाल लिये थे जिसमें फाइनेन्स का भी था। आप लोगों के आपस की सुलह होने पर हमारे वित्त मन्त्री ने बजट पेश करने के थोड़े दिन पेशतर चार्ज लिया। तो हम लोगों ने बड़ी रियायत की। आप लोग जो गरीब परवर और अपने तईं बहुत सयाने समझते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने छूट दी कि भाई आप टैक्स पीछे से सोचकर लगाइयेगा। आप लोगों ने आर्डिनेन्स पास कर के टैक्स लगा दिये और सदन के पास आये कि इस को पास करो। आप लोग मंजूर कीजिये। यह

हर साल अब नहीं चलेगा। अब आप नया वर्क पलटिये। हम को अपने देश की हिफाजत के लिये तैयार होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि ऊपर से कुछ और अन्दर से कुछ।

अब मैं सोचता हूं कि कुछ सप्लीमेंटरी बजट के ऊपर भी कहूं। माननीय नवल-किशोर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस सिलसिले में उन्होंने हम से दरख्वास्त की थी कि हम सप्लीमेंटरी ग्रान्ट की, जो १५ करोड़ रुपया मांगा है, मन्जूरी दे दें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस १४ तरीख से ३१ मार्च तक आप १५ करोड़ का खर्चा कर लेंगे? या मैं समझूं कि आलरेडी खर्च कर आये हैं? या फिर यह कहूं कि यह सही होगा कि इसको आलरेडी खर्च कर लिया गया है तो फिर मैं यह जानना चाहूंगा कि किस कानून के मातहत आपने खर्च किया है? कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल २६६, सबक्लाज (३) जो है उसके मातहत आपको खर्च करना चाहिए, उसमें साफ कहा गया है कि मरकजी या सूबाई फंड का कोई रुपया बिला कानून के खर्च नहीं हो सकता। वह कानून आर्टिकिल २०४ में दिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप का टाइम समाप्त हो गया।

अब हम उठते हैं और २८ तारीख को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इस के बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर बृहस्पतिवार, २८ फरवरी, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२१ फरवरी, १९६३।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अंतर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर]

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सहारनपुर नगर तथा जिले से होने वाली मनोरंजन कर से आय के आंकड़े ।

वित्तीय वर्ष	सहारनपुर नगर से मनोरंजन कर की आय	सहारनपुर जिले से मनोरंजन कर की आय
१९५९–६०	४,१०,४११	६,२०,५७२
१९६०–६१	४,९०,७७९	७,१३,१२४
१९६१–६२	५,४१,३२९	७,८०,२५३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर]

श्री सत्यानन्द गौड़ ने २४ मई, १९६२ से सहारनपुर नगर में मनोरंजन कर निरीक्षक का कार्य संभाला है। चूंकि उनके आने के बाद नौ महीने २३ फरवरी, १९६३ को पूरे होते हैं, अतः वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के पहले नौ महीने (१ अप्रैल, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक) की ही अवधि में मनोरंजन कर से होनेवाली आय तथा पिछले तीन वर्षों की उन्हीं नौ महीनों की आय के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

अवधि		सहारनपुर नगर की आय	सहारनपुर जिले की आय
		रु०	रु०
१ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९५९	..	३,०४,१९४	४,६२,०३०
१ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६०	..	३,६३,०६८	५,२९,८३५
१ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६१	..	४,०२,५४२	५,८१,५७३
१ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६२	..	४,२८,३१६	६,५१,३३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्

(संरक्षक: श्री विश्वनाथ दास, राज्यपाल)

१—श्री चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मन्त्री .. .. .. अध्यक्ष

२—श्रीमती सुचेता कृपालानी, चेयरमैन, सेना-सेवा समिति तथा श्रम मंत्री .. उपाध्यक्ष

३—श्री कैलाश प्रकाश, एम० एल० सी० .. .. .. महामंत्री

४—श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्या, आई० ए० एस०, राज्यपाल के सचिव संयुक्त मंत्री तथा कोषाध्यक्ष

५—श्री मंगला प्रसाद, प्रेसीडेन्ट प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फिडरेशन, वाइस प्रेसीडेन्ट, उत्तर प्रदेश काउन्सिल आफ स्पोर्ट्स तथा सदस्य, नेशनल सेविंग्स स्टेट एडवाईजरी बोर्ड, लखनऊ .. .. .. सदस्य

६—डा० ए० सी० बनर्जी, रिटायर्ड डाईरेक्टर आफ मेडिकल तथा हेल्थ सर्विसेज, लखनऊ .. .. ,,

७—डा० डी० एन० बनर्जी, चेयरमैन, उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक बोर्ड तथा मेयर, नगर महापालिका, कानपुर .. .. .. ,,

८—बेगम अली जहीर, प्रेसीडेन्ट, सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड तथा वाइस चेयरमैन, नेशनल सेविंग्स, लखनऊ .. .. .. ,,

९—श्री ए० जी० खेर, प्रेसीडेन्ट, भारत सेवक समाज, यू० पी० तथा भूतपूर्व स्पीकर, विधान सभा, लखनऊ .. .. ,,

१०—श्री पदम्पत सिंहानियां, उद्योगपति, कानपुर .. .. ,,

११—श्री ए० पी० जैन, एम० पी०, प्रेसीडेन्ट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लखनऊ। ,,

१२—श्री पीताम्बर दास, एम० एल० सी० लीडर, जन संघ लेजिस्लेचर पार्टी, लखनऊ .. .. ,,

१३—श्री उग्रसेन, एम० एल० ए०, लीडर, सोशलिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी, (अब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी) लखनऊ .. .. .. ,,

१४—राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह, एम० एल० ए०, लीडर स्वतंत्र लेजिस्लेचर पार्टी, लखनऊ .. .. ,,

१५—श्री उदित नारायन शर्मा, चेयरमैन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लखनऊ .. ,,

१६—श्री गेंदा सिंह, एम० एल० ए०, यू पी० लीडर प्रजा सोशलिस्ट विधायक पार्टी ,,

१७—श्री दरबारी लाल शर्मा, एम० एल० सी०, प्रेसीडेन्ट, इन्डियन मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ .. .. ,,

१८—श्री मदन मोहन, एम० एल० सी०, नेशनल स्काउट्स कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, मेरठ .. .. ,,

१९—श्रीमती उषा दास, (सेना सेवा समिति) लखनऊ .. .. ,,

२०—कु० श्रद्धा देवी, एम० एल० ए०, कनवीनर, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी, लखनऊ .. .. ,,

२१—श्रीमती सुशीला रोहतगी, एम० एल० ए०, कानपुर। .. .. सदस्य
२२—श्री टी० पी० भल्ला, रिटायर्ड आई० जी० पुलिस, लखनऊ। .. ,,
२३—डा० ए० वी० राव, वाइस चान्सलर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। .. ,,
२४—श्री राजा राम शास्त्री, एम० एल० सी०, श्रम कार्यकर्ता कानपुर। .. ,,
२५—श्री मसुरियादीन,एम० पी०, (पिछड़ी जातियां) इलाहाबाद। .. ,,
२६—श्री जगन प्रसाद रावत, एम० एल० ए०, भूतपूर्व उप मंत्री। .. ,,
२७—राजमाता कमलेन्दुमती शाह, एम० पी० टेहरी। .. .. ,,
२८—श्रीमती लता टंडन, कमिश्नर, स्काउट्स तथा गर्ल्स गाइड, लखनऊ। .. ,,
२९—ले० क० महाराज कुमार डा० विजया आर विजयानग्रम (पदम भूषण) एम० पी०, वाराणसी। .. .. ,,
३०—श्री सैयद अहमद खां (नवाब छतारी) प्रो-वाइस चान्सलर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, तथा भूतपूर्व गवर्नर, अलीगढ़। .. .. .. ,,
३१—श्री विशन चद्र सेठ, एम० पी०, (हिन्दू महासभा) लखनऊ। .. ,,
३२—श्री हयातउल्ला अंसारी, एम० एल० सी०, एडीटर, कौमी आवाज तथा सेक्रेटरी अंजमन, तरक्की उर्दू, लखनऊ। .. .. ,,
३३—कुंवर गुरु नारायन एम० एल० सी० कनवीनर, भारत सेवक समाज, लखनऊ। ,,
३४—श्री काशीनाथ पांडेय, एम० पी०, प्रेसीडेन्ट, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश शाखा लखनऊ। .. .. ,,
३५—श्री त्रिलोकी सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए०, लखनऊ। .. .. ,,
३६—श्रीमती कमला बहुगुना, इलाहाबाद। .. .. ..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२७ पर।)

रायबरेली जिले की तहसील महाराजगंज के अन्तर्गत चारों थानों बछरावां, शिवरतनगंज, महाराजगंज एवं मोहन गंज, में १९६१–६२ में हुई डकैती तथा चोरियों का विवरण

क्रम सं०	थाना	अपराध	अपराधों की कुल संख्या	मामले जिनमें जांच की गई	मामले जिनमें जांच नहीं की गई	
					संख्या	कारण
१	२	३	४	५	६	७
		सन् १९६१				
१	बछरावां ..	चोरी	७३	६८	५	कुछ में माल की शिनाख्त नहीं हो सकती थी और कुछ में बहुत छोटी चोरियां थीं
		डकैती	२	२	..	
२	शिवरतनगंज ..	चोरी	२८	२६	२	,, ,,
		डकैती	..	..	..	
३	महाराजगंज ..	चोरी ..	२९	२६	३	,, ,,
		डकैती	१	१	..	,, ,,
४	मोहनगंज ..	चोरी ..	३१	३०	१	,, ,,
		डकैती ..	१	१	..	
		सन् १९६२				
१	बछरावां ..	चोरी	१०८	९७	११	,, ,,
		डकैती	१	१	..	
२	शिवरतनगंज ..	चोरी	२९	२६	३	,, ,,
		डकैती	१	१	..	
३	महाराजगंज ..	चोरी ..	४३	४१	२	,, ,,
		डकैती	१	१	..	
४	मोहनगंज ..	चोरी	२२	२०	२	,, ,,
		डकैती	१	१	..	

नोट—सन् १९६२ में घटित उक्त चोरी की ३ घटनाओं में पुलिस जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर (पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद तथा विभाग का नाम
१	श्री मुहम्मद जहीर, आई० ए० एस०	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव शाखा तथा संचालक। सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग। इसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग
२	श्री जैनारायण तिवारी, आई० ए० एस०	संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग।
३	श्री श्याम नारायण मेहरोत्रा, आई० ए० एस०	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग
४	श्री सुरेश कुमार सहगल, आई० ए० एस०	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव शाखा
५	श्री भरतनरायन, आई० ए० एस०	उप सचिव, वित्त विभाग
६	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, आई० ए० एस०	उप विकास आयुक्त तथा उप सचिव, नियोजन विभाग।
७	श्री लक्ष्मण दास भार्गव, आई० ए० एस०	उप सचिव, शिक्षा विभाग
८	श्री ज्ञान स्वरूप गुप्त, आई० ए० एस०	उप सचिव, मुख्य सचिव शाखा, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त आयुक्त उत्तराखण्ड डिवीजन।
९	कुमारी कुसुम लता मित्तल, आई० ए० एस०	उप सचिव, सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति विभाग।
१०	श्री फरहत अली, पी० सी० एस०	उप सचिव, श्रम विभाग
११	श्री गुलाम याजदानी, पी० सी० एस०	सहायक विकास आयुक्त, उ० प्र० (प्रशिक्षण) और उप सचिव, नियोजन विभाग।
१२	श्री गिरिजा किशोर जोशी, पी० सी० एस०	उप सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राज्य सम्पत्ति अधिकारी।
१३	श्री प्रेम प्रकाश, एच०जे० एस०।	उप सचिव, न्याय शाखा तथा उप विधि परामर्श-दाता।
१४	श्री उमेशचन्द ओसवाल, एच० जे० एस०	उप सचिव, न्याय शाखा तथा उप-विधि परामर्श-दाता।
१५	श्री कैलाश नारायण मालवीया, यू० पी० ई० एस०	उप सचिव, शिक्षा विभाग
१६	श्री नरेश चन्द्र रे, यू० पी० एकाउन्ट्स सर्विस	उप सचिव, वित्त विभाग
१७	श्री शंकर मोहन गोयल, पी० सी० एस०	इनका स्थानान्तरण दिल्ली हो गया है
१८	श्री लक्ष्मी नारायण सकलानी, पी० सी० एस०	इनका स्थानान्तरण दिल्ली हो गया है

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर।)

मुरादनगर सब-स्टेशन पर आकस्मिक आग लगने के कारण हानि का विवरण

मेरठ जिले के मुरादनगर में एक १३२ के० वी० सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। २० एम० वी० ए० १३२ ६६ के० वी० के २ ट्रान्सफारमर इस सब-स्टेशन पर लगाये जा रहे थे और इनके सुखाये जाने के काल में जनवरी १३, १४, सन् १९६३ की रात को लगभग १ १/२ बजे इस सब-स्टेशन में आग लगी। आग का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है।

आग में निम्नलिखित मशीनरी क्षतिग्रस्त हुई:

१—२-२० एम० वी० ए०, १३२/६६ के० वी० के ट्रान्सफार्मर

२—२-१३२ के० वी० सर्किट ब्रेकर्स

३—२-६६ के० वी० सर्किट ब्रेकर्स

४—२-आयल फिल्टर मशीन।

५—टी० एन्ड पी० के कुछ छोटे-२ यंत्र जैसे वेल्डिंग ट्रान्सफार्मर, मेगर इत्यादि।

तत्काल ही देहली, मेरठ और मुरादनगर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। मुरादाबाद की फायर ब्रिगेड ने सुबह के २ बजे अपना कार्य आरम्भ किया। मेरठ और देहली की फायर ब्रिगेड सुबह ३ १/२ बजे व ४ बजे क्रमशः पहुंचीं। आग पर सुबह ४ १/२ बजे तक नियंत्रण कर लिया गया।

इस आग से हानि का अनुमान ९ लाख रुपये के लगभग है।

इस सामान का निर्माण-समय के लिए बीमा करवा लिया गया था

निम्नलिखित कर्मचारियों को जिन पर कार्य की जिम्मेदारी थी जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं होती निलम्बित कर दिया गया है:

१—अधिशासी अभियंता,

२—सहायक अभियंता,

३—अधीक्षक सब-स्टेशन

४—सेन्ट्रीपयुगल मिस्त्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

नकल रपट नं० ९, समय ८–३० मिनट, दिनांक २६–१०–१९६२, रोजनामचा ग्राम थाना मूंड़ा, जिला मुरादाबाद ।

इस समय श्री चुन्ना पुत्र छुट्टन कौम घोसी, सा० ग्राम खरगवीरपुर ने बहाजिरी थाना बहमराही बब्बू पुत्र नन्हें कौम घोसी नि० ग्राम खरगदीरपुर दरियापार इलाका हाजा ने सूचना दी कि श्रीमती रईसन पुत्री बुद्धू घोसी साकिन देह जो गांव के लल्ला पुत्र छुन्नू घोसी को व्याही थी रात मर गयी है करीब १२ बजे । उसके घर वाले कहते हैं कि हैजे से मर गई है लेकिन कल शाम तक वह ठीक थी । घर की लीप-पोत को थी । ऐसा मालूम होता है कि घर वालों ने उसे कुछ खिला दिया है या गला घोट दिया है, मौत में शुबहा है । रिपोर्ट हस्ब बयान दर्ज की गई नकल रपट, जरिये कानिस्टेबल नं० ८४७ शराफत खां मय जिल्द पंचायत नामा व दीगर कागजात पास HC विजयपाल सिंह जो इजलास ए० डी० एम० (जे) में मौजूद हैं रवाना की गई । कि खुराक नं० १९/११३ व मु० रु० २/–विराई लाश व २०/११४ रु० ५/– ढलाई लाश मालखाने से देकर ताला बंद दुरुस्त का पहरा को दिखाकर रवाना किया गया । कठेरा लाश दिया गया ।

(ह०) मुन्नू सिंह का० क्लर्क
थाना मूंडा ।

नोट—नकल रपट मुताबिक असल क है ।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३२३ एल० ए० (प्रो०)—१९६३—८५० ।